

C O N T E N T S

**Sixteenth Series, Vol. XXXII, Fifteenth Session, 2018/1940 (Saka)
No. 07, Thursday, July 26, 2018/Shravana 4, 1940 (Saka)**

<u>S U B J E C T</u>	<u>P A G E S</u>
OBITUARY REFERENCES	11-12
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
* Starred Question Nos. 121 to 124	15-52
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 125 to 140	53-99
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	100-599

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

- (iv) Need to address the problem of contaminated water in Sambhal Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Satyapal Singh

669

- (v) Need to undertake renovation of approach roads to railway stations, construction of foot-over bridges and road over bridges on level crossings in Gopalganj district, Bihar

Shri Janak Ram

670

- (vi) Need to set up a Committee of Experts to study use of Formaldehyde for preservation of fish

Adv. Narendra Keshav Sawaikar

671

- (vii) Regarding irregularities in post office situated in Pipargawan village in Bidhnu Development block in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Devendra Singh Bhole

672

- (viii) Need to provide adequate compensation to villagers relocated from Sanjay National Park in Sidhi Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shrimati Riti Pathak

673

- (ix) Need to fill up vacant posts in Government offices and Departments and also to regularise the services of contractual/temporary employees working in Government sector

Shri Harish Meena

674

- (x) Regarding irregularities in operation of petrol pumps in Thane district, Maharashtra
- Shri Gopal Shetty
- 675
- (xi) Need to start skill development and entrepreneurship programme in Uttarakhand based on the potential of natural resources of the State
- Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank
- 676
- (xii) Need to expedite four-laning of Jammu - Akhnoor - Poonch National Highway
- Shri Jugal Kishore
- 677
- (xiii) Need to impart knowledge of Constitution of India to students in schools and higher educational institutions
- Shri Vinod Kumar Sonkar
- 678
- (xiv) Need to set up a Planetarium in Meerut, Uttar Pradesh
- Shri Rajendra Agrawal
- 679
- (xv) Need to grant the status of state government employee to Aanganwadi workers
- Shri Mohd. Asrarul Haque
- 680-681
- (xvi) Regarding final notification on Western Ghats relating to Ecologically Sensitive areas
- Shri Anto Antony
- 682

(xvii)	Need to allocate funds to Kerala for construction of sea walls along the coastline	
	Shri Mullappally Ramachandran	683
(xviii)	Need to set up a Kendriya Vidyalaya at Kumbakonam in Tamil Nadu	
	Shri R. K. Bharathi Mohan	684
(xix)	Need to provide stoppage of Antyodaya Express and Rameshwaram - Bhubaneswar Express at Chidambaram railway station	
	Shri M. Chandrakasi	685-686
(xx)	Regarding non-payment of insurance amount to farmers of Odisha by a private insurance company	
	Shri Nagendra Kumar Pradhan	687-688
(xxi)	Need to set up fast track courts for early disposal of corruption cases	
	Shri Shrirang Appa Barne	689
(xxii)	Need to implement Land Acquisition Act, 2013 in letter and spirit in Jharkhand	
	Shri Vijay Kumar Hansdak	690
	TRAFFICKING OF PERSONS (PREVENTION, PROTECTION AND REHABILITATION) BILL, 2018	691-873
	Motion to consider	691

Shrimati Maneka Sanjay Gandhi	691-703, 827-848 854-855
Dr. Shashi Tharoor	704-721
Shri Om Birla	723-729
Shrimati Pratima Mondal	730-734
Shrimati V. Sathyabama	735-737
Shri Tatahagata Satpathy	738-744
Shri Vinayak Bhaurao Raut	745-748
Shri Muthamsetti Srinivasa Rao (Avanthi)	749-754
Shrimati Kavitha Kalvakuntla	755-761
Shri Md. Badaruddoza Khan	762-765
Shrimati Surpriya Sadanand Sule	766-772
Shrimati Kothapalli Geetha	773-776
Shri Dharambir	777-778
Shrimati Meenakashi Lekhi	779-785
Shri Vincent H. Pala	786-787
Shri N.K. Premachandran	788-794
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	795-797
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	798-802
Shri Dushyant Chautala	803-805
Shri Kaushlendra Kumar	806-807
Shrimati Satabdi Roy	808-810

Shri Ravindra Kumar Pandey	811-813
Shri Prasanna Kumar Patasani	814-815
Shrimati Butta Renuka	816-817
Shri E.T. Mohammed Basheer	818-819
Shrimati P.K. Shreemathi Teacher	820-821
Shrimati Jayshreeben Patel	822-824
Shri Rajesh Ranjan	825-826
Clauses 2 to 59 and 1	856-873
Motion to Pass	873

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER	875-876
------------------------------------	----------------

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2018**

AND

**HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT)
BILL, 2018**

877

Motion to Consider	877
Shri Shripad Yesso Naik	877-885
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	877, 886-896

ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions	897
Member-wise Index to Unstarred Questions	898-903

ANNEXURE – II

Ministry-wise Index to Starred Questions	904
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	905-906

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

Shri Kalraj Mishra

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, July 26, 2018/Shravana 4, 1940 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

OBITUARY REFERENCES

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे तीन पूर्व सदस्यों सर्वश्री कामेश्वर पासवान, पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर और राज नारायण पासी के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री कामेश्वर पासवान बिहार के नवादा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

इससे पूर्व, श्री पासवान दो बार बिहार विधान सभा के सदस्य रहे और वर्ष 1977 से 1979 तक बिहार सरकार में कल्याण मंत्री के रूप में सेवाएँ दीं। वह वर्ष 1990 से 1996 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

अध्यापक और सामाजिक कार्यकर्ता, श्री पासवान ने समाज के कमजोर और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया।

श्री कामेश्वर पासवान का निधन 77 वर्ष की आयु में 28 मई, 2018 को पटना, बिहार में हुआ।

श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर महाराष्ट्र के अकोला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नौवीं, दसवीं और ग्यारहवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री फुंडकर वर्तमान महाराष्ट्र सरकार में कृषि और बागवानी मंत्री थे। इससे पूर्व, वह दो बार महाराष्ट्र विधान सभा के सदस्य और तीन बार महाराष्ट्र विधान परिषद् के सदस्य भी रहे।

श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर जी का निधन 67 वर्ष की आयु में 31 मई, 2018 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ।

श्री राज नारायण पासी उत्तर प्रदेश के बांसगांव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दसवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे थे।

श्री राज नारायण पासी का निधन 69 वर्ष की आयु में 19 जुलाई, 2018 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में हुआ।

हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मुझे विश्वास है कि शोक-संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में यह सभा मेरे साथ है।

अब यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

11 01 hrs

The Members then stood in silence for a short while

HON. SPEAKER: Question Hour.

Question No. 121 - Shri Ravneet Singh.

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बैठिए, मुझे मालूम है। प्रश्न काल के बाद यह 12 बजे होगा।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री खड़गे जी, कौन-सी बड़ी बात हो गई?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बारह बजे, अभी नहीं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठिए। अभी नहीं, क्वेश्चन आवर के बाद।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे, जी कौन सी बड़ी बात हो गई?

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, रिज़र्वेशन ऑन एस.सी., एस.टी। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : हां, मुझे मालूम है। उसके बारे में सरकार ने आदेश निकाला हुआ है। बारह बजे, अभी नहीं। आई एम सॉरी।

श्री रवनीत सिंह। प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

...(Interruptions)...

HON. SPEAKER: After Question Hour means after Question Hour.

* Not recorded

11 05 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

HON. SPEAKER: Question No. 121.

(Q. 121)

श्री रवनीत सिंह : थैंक यू, स्पीकर महोदया । मैं खास तौर पर पंजाब और लुधियाना की बात करूंगा। पंजाब और लुधियाना नॉर्थ इंडिया का टैक्सटाइल हब है। We are the leaders in export and manufacturing of woolen garments. पंजाब से जितना एक्सपोर्ट होता है, उसमें 40 परसेंट हिस्सा लुधियाना डालता है। जितने भी मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे वे इंटरनेशनल ब्रांड्स हों, जिनमें मार्क स्पेनसर की बात की जाए, ज़ारा की बात की जाए या एच एण्ड एम की बात की जाए। खास तौर पर जो हमारे ब्रांड्स हैं, उनमें ओसवाल आप जानते हैं, मॉन्टी कार्लो आप जानते हैं, प्रिंगल जानते हैं, ड्यूक जानते हैं, वर्धमान जानते हैं। आप ये बड़े से बड़े ब्रांड्स जानते हैं। मैं निफ्ट की बात करने जा रहा हूँ। खास तौर पर जो डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं, उनमें हर साल नए डिज़ाइंस तैयार होते हैं। उनका अरबों रुपये का बिज़नेस होता है। वहां पर डिज़ाइनर्स की जो हाई पेड जॉब्स हैं, उनके लिए हमें निफ्ट मुंबई, कोलकाता और दिल्ली से डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स लाने पड़ते हैं। यह अच्छी बात है। पंजाब में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वे छोटी मशीनों पर काम करते हैं और छोटी नौकरियां करते हैं। हमें वहां होने वाले डिज़ाइनिंग के काम के लिए बाहर से क्यों लोगों को लाना पड़ता है? आप वहां निफ्ट का कोई कॉलेज या सेंटर क्यों नहीं खोलते हैं, ताकि वहां के स्टूडेंट्स को और पूरे पंजाब को फायदा हो सके?

श्री अजय टम्टा : महोदया, माननीय सदस्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पंजाब के लुधियाना का विशेष रूप से जो टैक्सटाइल उत्पादन है, वह पूरे देश-दुनिया में है। उन्होंने यह भी कहा कि अच्छे डिज़ाइनर्स उपलब्ध करवाने के लिए वहां निफ्ट की शुरुआत की जाए।

महोदया, मैं माननीय सदस्य जी को जानकारी देना चाहूंगा कि 5 मई, 2010 से लगातार पंजाब की सरकार वहां निफ्ट खोलने के लिए हमारे बी.ओ.जी., जो कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस है,

उसके साथ लगातार पत्र व्यवहार कर रही है। एन.आई.आई.एफ.टी. इंस्टीट्यूट मोहाली, लुधियाना और जालंधर में स्थापित हैं। राज्य सरकार द्वारा इसे निफ्ट से संचालित करने के प्रस्ताव पर कई बार चर्चा हुई। बी.ओ.जी. की नई गाइडलाइन दिनांक 4.9.2012 से प्रारंभ हुई है। उसके अनुसार राज्य से प्रस्ताव की मांग की गई है और उस ओर प्रयास किया जा रहा है। पूर्व में भी इस पर काफी चर्चा हुई है। पूर्व के सूचना एवं प्रसारण मंत्री जी द्वारा और आपके टाइम पर भी ये सारी चीजें रही हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बी.ओ.जी. की कुछ गाइडलाइंस हैं। बी.ओ.जी. एक ऑटोनोंमस बॉडी है। उसी को इस पर कार्यवाही करनी होती है।

माननीय अध्यक्ष : सैंकेंड सप्लीमेंटरी।

श्री रवनीत सिंह : स्पीकर महोदया, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि इसको फ्रीज कर दिया गया। आपने फ्रीज करने वाली जो बात कही, वे तीन साल भी पूरे हो चुके हैं। इन्होंने अपने आंसर में जो दूसरी बात कही है, उससे मुझे दुख हुआ। इन्होंने यह कहा कि पंजाब में फैकल्टी नहीं है और वहां ब्रांड इक्विटी है।

मैडम, पंजाबी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। मैं अगर लुधियाना जैसे शहर की बात करूं, तो मर्सिडीज अगर कहीं सब से ज्यादा बिकती है, तो वह लुधियाना है। जब मारुति आई, तो वह भी सब से ज्यादा लुधियाना में आई थी।... (व्यवधान) आपने ये आंसर दिया कि वहां ब्रांड इक्विटी है। आप क्या समझते हैं कि पंजाबियों को ब्रांड के बारे में नहीं पता? दुनिया में सब से बड़ा जो नाम है, वह पंजाबियों का नाम है। इसके बारे में मंत्री जी बताएं। मैं मंत्री जी को लगातार तीन पत्र लिख चुका हूं। स्पीकर महोदया, मैं हाउस में आपके सामने यह कहना चाहता हूं कि मुझे उनमें से एक भी पत्र भी जवाब आज तक नहीं आया।

आप ब्रांड इक्विटी की अपनी बात पर माफी मांगिए कि पंजाबियों को वहां इस चीज की कमी है। आप वहां निफ्ट शुरू करने का भरोसा दीजिए। आप स्टेट गवर्नमेंट से जो चाहते हैं, वह वैसा करने के लिए तैयार है, क्योंकि दस साल निकल गए हैं। मैं पिछली बार आनंदपुर साहब से एम.पी. था। वहां भी मैंने बार-बार इस विषय के बारे में कोशिश की थी। आज मैं लुधियाना से एम.पी.

हूं और वहां से कोशिश कर रहा हूं ... (व्यवधान) मंत्री जी, आप इसका कुछ तसल्लीबख्श जवाब दीजिए। बड़े मंत्री जी को यहां होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं हैं। अकेला यह जवाब तो मेरे पास आ गया। आप इससे आगे भी बढ़ें। वहां सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स बनते हैं ... (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा : माननीय सदस्य ने अपनी भावनाओं को बताया और पत्र के जवाब में भी मैं आपको सम्माननीय रूप में कहना चाहता हूं कि ऐसा हुआ नहीं है। यदि आप 'निफ्ट' के बारे में कह रहे हैं तो आपके पत्र का भी संज्ञान लिया गया होगा, क्योंकि ये सारी चीजें बी.ओ.जी. के माध्यम से ही होता है और चूंकि 'निफ्ट' 1986 से देश के अंदर प्रारम्भ हुआ और निफ्ट को 2006 में एक्ट में लाया गया। चूंकि देश भर में 16 संस्थान निफ्ट के परिसर हैं, जिनमें 450 योग्य फैकल्टीज भी हैं और 11040 छात्र, छात्रएं उनमें अध्ययन करते हैं और 23 हजार युवा उससे बाहर निकले हैं।

माननीय सदस्य को मैं फिर दोबारा बताना चाहूंगा चूंकि बी.ओ.जी. एक स्वतंत्र बॉडी है और उसके माध्यम से ही हम उसको संचालित कर सकते हैं। राज्य सरकार के द्वारा इसमें पत्रों के द्वारा हमने उनको अवगत भी कराया है। मैं अवगत कराना चाहता हूं कि वह राज्य सरकार के माध्यम से उस पर विचार करके अपने प्रस्ताव को बी.ओ.जी. में भेजें। हम भी आपके पत्रों का संज्ञान बी.ओ.जी. को देंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

(Q.122)

SHRI T.G. VENKATESH BABU : Madam Speaker, I would like to know from the hon. Minister through you as to whether the Government has allocated exclusive funds to various villages, Town Panchayats, Municipalities and City Corporations in the country and set any targets for the construction of community toilets to achieve ODF status by 2023. If so, I want to know the details of the funds sanctioned to various villages, Town Panchayats, Municipalities and Corporations of Tamil Nadu in the last three years.

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा खान मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर) : अध्यक्ष महोदया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ भारत मिशन शहरी ये दो भागों में विभक्त है। स्वच्छ भारत मिशन को पेयजल स्वच्छता मंत्रालय संचालित करता है और स्वच्छ भारत मिशन शहरी को अर्बन मिनिस्ट्री संचालित करती है। नई सरकार बनने के बाद लगातार यह कोशिश की जा रही है कि स्वच्छ भारत के मिशन के माध्यम से पूरे देश में स्वच्छता का प्रतिशत लगातार बढ़े और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि 2014 में देश में स्वच्छता का प्रतिशत 38.7 प्रतिशत था, जो आज बढ़कर 88.42 प्रतिशत हो गया है। इसके साथ ही 19 राज्य ओडीएफ हो चुके हैं। 418 जिले, 4088 से अधिक ब्लॉक्स, 1,77,780 ग्राम पंचायतें और 4,0,1925 गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में पैसे की कोई कमी नहीं है। तमिलनाडु सहित सभी राज्यों में समय-समय पर पैसा दिया जाता है और वह पैसा अभी भी राज्यों के पास अवशेष है।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्चस्त करना चाहता हूँ कि वह स्वच्छ भारत मिशन के काम को आगे बढ़ाएं, जब भी पैसे की आवश्यकता होगी, उनके राज्य को और देश में कहीं भी पैसे की कमी आने नहीं दी जाएगी।

SHRI T.G. VENKATESH BABU : Madam, I would like to know from the hon. Minister about the total amount spent by the Government in the last three

years for publicity campaigns and advertisements in TV and print media to promote and create awareness on the importance of using toilets to achieve ODF status and also about the total amount contributed by the various profit-making PSUs and private companies in the last three years.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: महोदया, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में यह प्रयत्न किया गया है कि सामुदायिक भावनाओं को जाग्रत किया जाए और जो लोग इस आंदोलन में समर्थन करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, कारपोरेट क्षेत्र के लोग और पीएसयूज और बाकी अन्य संस्थाएं सरकार सबका सहयोग ले रही है और लगातार इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है।

आईईसी के माध्यम से सरकार की कोशिश है कि सूचना के जितने प्रकार के भी साधन हैं, चाहे वह इलैक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो या समुदाय को जागरूक करने की अन्य प्रकार की पहलें हों, स्वच्छता प्रेरक खड़ा करने की, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धि जैसे कार्यक्रम आयोजित करने और गांवों-गांवों में जागृति लाने के लिए जो भी विषय हो सकते हैं, उन सभी विषयों के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि स्वच्छता के लिए सब लोग जागृत हों और स्वच्छता को स्वभाव में लाएं, जिससे कि आने वाले कल में हमारा देश पूरी तरह स्वच्छ हो सके, सुंदर हो सके, साफ हो सके और गंदगी के कारण जो बीमारियां होती हैं, उनके प्रतिशत को हम घटाने में सफल हो सकें।

श्री पशुपति नाथ सिंह : आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी मंत्री जी ने विस्तार से उत्तर भी दिया है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, दोनों की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें इन्होंने कहा है कि खास कर बच्चों की मृत्यु दर कम हुई है। इसके लिए मैं इनको बधाई दूंगा। यह जो स्वच्छ भारत और शौच मुक्त भारत का अभियान चालू है, जिसके तहत काम भी बहुत अच्छा हो रहा है और इससे सामाजिक विषमता को भी दूर किया जा रहा है। जिनके घरों में शौचालय होता था, वे बड़े आदमी माने जाते थे, जिनके पक्के मकान होते थे, वे बड़े आदमी गिने जाते थे, जिनके घरों में गैस का चूल्हा होता था, वे बड़े आदमी गिने जाते थे।

इस सामाजिक विषमता को दूर करने में मोदी सरकार ने काफी सफलता पाई है। महोदया, जितने शौचालय बन रहे हैं, उनमें दो प्रकार के शौचालय हैं। एक तो घरों में बन रहे हैं, जो निजी शौचालय होते हैं और दूसरे प्रकार के शौचालय, सामुदायिक शौचालय बन रहे हैं। लेकिन दोनों में बाधा है, जिसकी वजह से लोग शौचालय बनने के बाद भी शौचालय का उपयोग नहीं करते हैं। उसमें बाधा पानी की है। उसके लिए समुचित व्यवस्था करने के लिए कौन से उपाय सरकार करेगी, क्या आकलन सरकार ने किया है कि पानी के अभाव में शौचालय बनने के बाद भी उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदया, माननीय सदस्य की चिंता अपनी जगह ठीक है और सरकार उसके लिए प्रयत्नशील भी है। गांवों में जल की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता हो, यह भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की प्रतिबद्धता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से शौचालय बनाने का काम पूरे देश में तेज़ी के साथ चल रहा है, उसी प्रकार से उनका उपयोग होना चाहिए। हम निर्माण के प्रति जितने सजग हैं, उतने ही उपयोग के प्रति सजग हैं। उपयोग हो, इसके लिए लगातार आईईसी के माध्यम से मंत्रालय, राज्य सरकार और जिला प्रशासन यह प्रयास करता रहता है। अभी हम लोगों ने जो स्टडी कराई थी, उसके अनुसार 93 प्रतिशत शौचालय ऐसे हैं, जिनका उपयोग हो रहा है और बाकी जो शेष हैं, उन पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन पानी की उपलब्धता हो, यह भी जरूरी बात है। दूसरा, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ और माननीय सदस्य ने भी यह बात कही है कि बच्चों की मृत्यु दर में कमी आ रही है। गंदगी के कारण जो बीमारियां फैलती थीं, जैसे डायरिया होता था या बाकी जो बीमारियां होती थीं। माननीय सदस्य ने पूछा था, यूनिसेफ का एक हवाला दिया था, उनकी स्टडी के अनुसार एक लाख से अधिक बच्चे मृत्यु में समा जाते हैं। अभी डब्ल्यू.एच.ओ. की एक स्टडी आई है। अभी कुछ दिन में वह स्टडी प्रकट होने वाली है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2017-18 तक इस प्रकार की मृत्यु में लगभग 75 हजार डेथ्स कम हुई हैं। जब वर्ष 2019 में स्वच्छ भारत

मिशन का लक्ष्य पूरा होगा तब एक लाख 22 हजार डेथ्स कम होंगी, ऐसा अनुमान डब्ल्यू.एच.ओ. की स्टडी में है।

श्री विनायक भाऊराव राऊत : महोदया, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ओ.डी.एफ. स्कीम यानी शौच मुक्त योजना को हम मराठी में हागणदारी मुक्त योजना कहते हैं। इस योजना के अन्तर्गत पूरे देश में मेरे संसदीय क्षेत्र के सिंधुदुर्ग जिले का प्रथम नामांकन हुआ और प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी साहब के हाथों से सिंधुदुर्ग जिले को सम्मान प्रदान किया गया। इससे समस्या यह हुई कि इस जिले के शौच मुक्त घोषित हो जाने के बाद, शौचालय बनाने के लिए जो निधि दी जाती है, जो आर्थिक सहायता दी जाती है, वह बंद हो जाती है। हमारे जिले में हर वर्ष अनुमति लेकर कम से कम 800 से 1,000 तक नये घर बनते हैं। भाइयों का आपस में बंटवारा होता है तो उनके नये घर बनते हैं। जहाँ ऐसे नये घर बनते हैं, अगर वहाँ शौचालय बनाना हो तो उसे आर्थिक सहायता नहीं मिलती है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से विनती करता हूँ और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि शौच मुक्त जिला जाहिर होने के बावजूद भी, अगर उस जिले में अनुमति लेकर घर बनाए जाते हैं तो उन्हें इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता मिलने का क्या आप कोई प्रबन्ध करेंगे?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदया, माननीय सदस्य का प्रश्न उनके क्षेत्र के हिसाब से है, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि स्वच्छता व्यवहार और स्वभाव परिवर्तन का विषय है। स्वच्छता के लिए जो राशि दी जाती है, वह एक तौर से प्रोत्साहन राशि है। इस प्रोत्साहन की हमेशा एक सीमा रहती है। आदर्श स्थिति तो यह होनी चाहिए कि एक बार समुदाय जागृत हो गया और उसने पूरे जिले को ओ.डी.एफ. किया तो जागृति इतनी आ जानी चाहिए कि जब नया मकान बन रहा है तो उसमें शौचालय खुद-ब-खुद बनाने का प्रयत्न लोगों को करना चाहिए।

DR. RATNA DE (NAG) : Thank you Madam. It is pertinent to point out here that out of 20 districts in our West Bengal, 14 districts have been declared ODF

districts, and out of 38,000 villages, 33,525 villages have been declared Open Defecation Free villages with the active initiatives of our Chief Minister. Madam, through you I would like to ask the hon. Minister, whether the Ministry has tried to find out the impact of the programme on the health of people ever since the programme came into being? Have the toilets built been disabled-friendly? If yes, what are the details there of.

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर : महोदया, मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूँ कि जब कोई गाँव, जिला या राज्य खुले में शौच से मुक्त होता है तो उसकी अपनी एक प्रक्रिया है। पहले गाँव अपने आपको घोषित करता है, उसके बाद उसकी जाँच की जाती है और उसके बाद वह ओ.डी.एफ. माना जाता है। इसी प्रक्रिया को जिला और राज्य भी करते हैं। इसके साथ ही साथ पेयजल स्वच्छता मंत्रालय अपनी ओर से थर्ड पार्टी स्टडी भी कराता है और उसकी पूरी तरह जाँच कराता है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, आपको और शायद हमारे सारे साथियों को इसकी जानकारी होगी कि हिन्दुस्तान में फ्लैगशिप प्रोग्राम की निगरानी रखने के लिए, देखभाल करने के लिए केन्द्र की सरकार ने पहले विजिलेंस एंड मानिट्रिंग कमेटी बनाई थी। वर्ष 2016 से इसके नए अवतार के रूप में इसका नाम दिशा हो चुका है।

अपने डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद से सबसे सीनियर एमपी होने के नाते मैं वर्ष 2012 से वहाँ की 'दिशा' कमेटी का चेयरमैन हूँ, लेकिन आज तक वहाँ मीटिंग नहीं बुलायी गयी है।...(व्यवधान) मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूँ।...(व्यवधान) वहाँ जब एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने मीटिंग बुलाने की हिम्मत दिखायी, तो दूसरे दिन ही उसका तबादला कर दिया गया।...(व्यवधान) हम लोग पार्लियामेंट में आकर आम लोगों की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे जैसे एमपी खुद उससे वंचित हो रहे हैं।...(व्यवधान) बंगाल में जो सरकार चल रही है, वह तानाशाही की सरकार चल रही है, इसलिए बंगाल में कोई लोकतंत्र नहीं है।...(व्यवधान) वहाँ एक एमपी की हैसियत क्या है,

...(व्यवधान) 'दिशा' कमेटी के चेयरमैन होने के नाते उसकी देखभाल करने का जो अधिकार है, उसे वह मौका नहीं दिया जाता है।...(व्यवधान)

माननीय मंत्री जी, आपने जो चिट्ठी भेजी है, 'दिशा' कमेटी के लिए एक डेटाबेस सप्ताह मनाने की बात कही गई थी, ...(व्यवधान) लेकिन हम वहाँ कैसे सप्ताह मना सकते हैं? ...(व्यवधान) आप चेयरमैन को चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन पिछले छह सालों से चेयरमैन कोई भी मीटिंग नहीं बुला सकते हैं, ...(व्यवधान) मैं आप की चिट्ठी का कैसे सम्मान कर सकता हूँ? ...(व्यवधान)

मेरा एक दूसरा सवाल है। मंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि आप जितनी सफलता की बात कर रहे हैं, आप जितनी कामयाबी की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी कह रही है कि आपकी कामयाबी का जो ब्यौरा है, वह सही नहीं है। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी यह भी कह रही है कि स्वच्छता मिशन लेथार्जिक है। वह यह भी कह रही है कि 15 हजार करोड़ रुपये ऐसे ही पड़े हुए हैं।...(व्यवधान) मैं कहना चाहता हूँ कि एक सवाल तथा एक अधिकार की बात है, ये दो मुद्दे हैं।...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, अधीर रंजन जी की पीड़ा अपनी जगह सही है और वह मुझसे भी एक बार मिले थे। मैंने भी कोशिश की थी कि इस पीड़ा को कम किया जाए, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2014 के बाद जब 'दिशा' कमेटी का गठन किया गया, तो उसमें अनेक और विभाग सम्मिलित किए गए और यह कोशिश की गई कि हमारे सभी सांसद केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की अपने-अपने क्षेत्र में ठीक प्रकार से निगरानी तथा मॉनिटरिंग करें।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने सभी माननीय मुख्य मंत्रीगण को भी पत्र लिखा। हमारे सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरी को बार-आग्रह किया। मैं सभी माननीय सदस्यों को भी हमेशा पत्र लिखता रहता हूँ कि इस काम को और त्वरित गति से बढ़ाया जाए। पिछले दिनों 25 से लेकर 29 तक हम लोगों ने 'दिशा' कमेटी के लिए एक सप्ताह आयोजित किया, उसकी चिट्ठी भी सभी सांसद

गण को भेजी गई। एक दिन 28 तारीख को इसी विषय को लेकर पूरे राज्यों के सचिवों को बुलाया और उनके साथ इसका डिसकशन किया। उस दिन यानी 28 तारीख को जितनी बैठकें हो रही थी, सभी जिलों में माननीय सांसदों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करके बात की। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं-कहीं अभी ऐसी स्थिति आ रही है, लेकिन मैं अधीर रंजन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से भी आग्रह करूँगा कि उनके क्षेत्र में इस कमेटी की बैठक कलेक्टर आयोजित करें और उनकी समस्या का समाधान करें।

दूसरा, जो माननीय सदस्य ने कहा है कि स्टैंडिंग कमेटी कहती है कि सारी उपलब्धियाँ ठीक नहीं हैं। मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी बात सभा में कही जा सकती है और आमतौर पर कही जाती रही है, लेकिन जब हम सदन में बैठते हैं तो सदन में जो आँकड़ा होता है, वह राज्य, जिला प्रशासन तथा केन्द्र द्वारा एक तरह से प्रमाणित आँकड़ा होता है। उसको झुठलाने की कोशिश राजनीति के स्तर पर नहीं होनी चाहिए। अगर स्वच्छता जैसे कार्यक्रम को संचालित करने में आपको लगता है कि कहीं रिक्तता तथा अभाव है, कहीं काम करने की कमजोरी है, तो स्टैंडिंग कमेटी या माननीय सदस्य हमको अवगत कराएंगे। हम उस गैप को भरने की पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे।

दूसरा, मैं आपके माध्यम से अधीर रंजन जी को कहना चाहता हूँ कि मैं उनकी पीड़ा का निराकरण करने की कोशिश करूँगा ही, लेकिन उनकी पीड़ा का निराकरण करने में हमारे माननीय खड़गे जी और सौगत राय जी, ये दोनों ज्यादा मददगार हो सकते हैं। इनके सामने भी वह अपनी गुहार करें, तो ठीक है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी । शार्ट क्वेश्चन, आंसर खूब अच्छे हो गए।

श्री शरद त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले अपने माननीय मंत्री जी और प्रधान मंत्री जी को बधाई दूँगा कि भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज, जो अक्टूबर, 2014 में 38 परसेंट था,

वह जुलाई, 2018 में 88 प्रतिशत बढ़कर आज देश के स्वच्छता अभियान में एक मील का पत्थर साबित हुआ।

एक माननीय सदस्य के द्वारा यह विषय आया कि बहुत सारे शौचालय पानी के अभाव में संचालित नहीं हो पा रहे हैं। स्वच्छता अभियान का सबसे बड़ा असर पड़ा है कि बच्चों की मृत्युदर कम हुई है और यूनीसेफ ने 2015 के अपने आंकड़े में भी इसको दर्शाया है कि बच्चे जो निमोनिया और दस्त से मरते थे, स्वच्छता अभियान से उसमें बहुत तेजी से दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि क्या प्रदेश सरकारों से कोई एक समन्वय बना करके, जैसे हमारे ही प्रदेश में माननीय विधायक लोगों को यह अवसर है कि वह अपने आधार पर बहुत सारी जगहों पर इंडिया मार्का हैंडपंप लगवा सकते हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी हम सांसदों को भी प्रदेश सरकारों से समन्वय बना करके कोई ऐसा अधिकार देंगे कि हम लोग भी इंडिया मार्का हैंडपंप लगवा सकें, जिससे शौचालय भी निर्बाध गति से चले और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की समस्या का भी निराकरण हो?

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: माननीय अध्यक्ष महोदया, पेयजल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय पेयजल ग्रामीण योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार राज्यों को सहायता करती है और राज्य सरकारें कोशिश करती हैं कि केन्द्र की जो योजना है, उसका भी लाभ लें और साथ ही वे अपने बजट का पैसा भी पेयजल के लिए लगाती हैं। मैं समझता हूँ कि जो शरद जी ने कहा, वह समस्या है। राज्य सरकार के साथ इस मामले में हम मुख्य मंत्री जी से बात भी करेंगे कि इस दिशा में और त्वरित गति से कार्रवाई हो।

(Q. 123)

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : स्पीकर मैडम, पहले तो मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने आजादी के बाद पहली बार उन क्षेत्रों को, जो वंचित पड़े थे, गांव और गरीब को प्राथमिकता थी। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना गांवों के बिजलीकरण के लिए आई। पंजाब में 40 वर्ष पहले ही बिजलीकरण हो गया था। जो यह नई योजना है, इसमें रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, पंजाब को पैसा दिया गया। मैडम, यह कहा जाता है कि जो परिवार में अच्छा बच्चा होता है, उसे मां-बाप ज्यादा इंसेंटिव देते हैं, मगर पंजाब के केस में ऐसा नहीं हुआ। 700 करोड़ रुपये की योजना हमने पंजाब की ओर से भेजी थी, मगर 250 करोड़ रुपये ही जारी किए गए। माननीय मंत्री जी ने मुझे पंजाब में योजनाओं की यह लिस्ट दी है। उसमें एचीवमेंट किसी एक की भी नहीं, केवल 11 केवी लाइन की दी है, बाकी किसी की एचीवमेंट की कोई फिगर नहीं दी। इसका क्या कारण है? मैं यह जानना चाहता हूँ। 40 वर्ष पहले पंजाब में बिजलीकरण का जो काम हुआ, उसको देखते हुए देश की सेंटर किटी में इसका ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। जितने का प्लान भेजा था, कम से कम वह पैसे तो देने चाहिए थे। यह क्या बात है?

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न हो गया है। शार्ट में पूछिए।

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदया, हमने पंजाब को चार सौ करोड़ रुपये की योजना दी है। 251.99 लाख रुपये की योजना हमने नई योजना के अंतर्गत स्वीकृत की है।

इसके अतिरिक्त पुरानी योजना में 149 करोड़ रुपये अनस्पेंट राशि थी, हमने उसका भी उपयोग करने की अनुमति दी है। यह सही है कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि पंजाब सरकार द्वारा कार्य का ठेका, जो वर्क एलॉट किया गया, वह बहुत लेट किया गया। टेंडर एलॉट होते-होते दिसम्बर, 2017 हो गया, इसी कारण प्रगति बहुत कम है। जितनी प्रगति हुई है हमने उतना ही लिखा है। जहां प्रगति नहीं दिखायी गई है, वहां प्रगति नहीं हुई है, प्रगति बहुत धीमी है। पंजाब सरकार ने और राशि की मांग नहीं की है। अगर पंजाब सरकार किसी काम के लिए और राशि की मांग करेगी तो हम उस पर विचार करेंगे।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने अस्पेंट का जो फिगर दिया है, वह गलत है। 149 करोड़ करोड़ रुपये है जबकि इसमें 250 करोड़ रुपये हैं।

श्री आर. के. सिंह : महोदया, 250 करोड़ रुपये नई योजना के लिए स्वीकृत किये थे और 149 करोड़ रुपये अनस्पेंट है, उसको भी स्वीकृत कर दिया, कुल मिला कर 400 करोड़ रुपये है।

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा : अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने कहा कि पंजाब ने और राशि नहीं मांगी। मुझे जानकारी है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि 700 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट भेजी थी, जिसमें 250 करोड़ रुपये मिले। मेरा एरिया किनारे का क्षेत्र है। पंजाब का बहुत सारा एरिया हिल एरिया से जुड़ा है। पहले किनारे के क्षेत्र में 24 घंटे लाइट मिलती थी। नई सरकार आने के बाद वहां शॉर्टेज आने लगी। सबसे पहले किनारे के एरिया को कट लगाते हैं। गांवों की लाइट से अलग करने के लिए एक अलग से प्रोजेक्ट भेजी है, उसके लिए पैसे की जरूरत है। काम स्लो हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने भी इसे माना है। इस काम को कैसे तेज किया जाए, जिससे लोगों की मुश्किलें दूर हो पाएं।

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदया, वाकई कार्य धीमी गति से हो रहा है। हम लोग राज्यों सरकारों के साथ प्रत्येक दो महीने में चर्चा करते हैं कि कैसे काम की गति तेज हो। मैं पुनः पंजाब सरकार से वार्ता करूंगा कि वे काम की गति में तेजी लाएं क्योंकि हम काम राज्य सरकारों के माध्यम से ही कराते हैं।

हमने माननीय सदस्य के क्षेत्र के लिए भी राशि स्वीकृत की है। चार सौ करोड़ रुपये की राशि पंजाब सरकार से विचार विमर्श के बाद ही स्वीकृत हुई। जिन योजनाओं की उनको जरूरत थी, उसी के लिए स्वीकृत किया गया। मैं पुनः दोहराता हूँ कि पंजाब सरकार ने उसके बाद और राशि की मांग नहीं की है। अगर वे और राशि की मांग करेंगे तो हम लोग जरूर विचार करेंगे। काम की गति तेज हो, इसके लिए राज्य सरकार से पुनः बात करेंगे। काम की गति धीमी है।

SHRI KALIKESH N. SINGH DEO : Madam, the question I wish to ask applies as much to Punjab as it does to the entire nation. The definition of

electrification of a village is, 10 per cent of the households in the village being electrified, as it stands today. When you say that the entire nation has been electrified, every village has been electrified, just electrifying 10 per cent of the entire nation does not meet the sufficient criteria. The World Bank still assesses that almost 20 crore people in the country still live without access to electricity, and almost another 30-40 crore live with access to electricity which is insufficient or intermittent. There is a lot to be done. My question to you is this. Does the Government have any plan or policy which will address these deficiencies in the long-term? Thank you.

श्री आर. के. सिंह : अध्यक्ष महोदया, जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण की बात है, माननीय सदस्य ने जो डेफिनेशन दिया है, वह सही है कि गांव में दस प्रतिशत और पब्लिक बिल्डिंग इलेक्ट्रिफाईड हो जाती है तो उसे विद्युतीकृत माना जाता है। जितने गांवों की सूची राज्य सरकारों ने भेजी थी, उन सभी के विद्युतीकरण के लिए हमने राशि दी। राज्य सरकारों ने हमें प्रतिवेदित किया कि वे सब गांव विद्युतीकृत हो गए। हम इतने पर नहीं रुके, हमारा लक्ष्य है कि हर घर तक रोशनी पहुंचाएं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, जहां तक ग्रामीण विद्युतीकरण की बात है, माननीय सदस्य ने जो डेफिनेशन दी है, वह सही है कि अगर गांव में दस प्रतिशत घर कवर हो जाते हैं, पब्लिक बिल्डिंग्स कनेक्ट हो जाती हैं तो गांव को विद्युतीकृत माना जाता है। राज्य सरकारों ने हमें जितने गांवों की सूची भेजी थी, हमने उन सभी के विद्युतीकरण के लिए राशि दी है और राज्य सरकारों ने हमें प्रतिवेदित किया कि सब गांव विद्युतीकृत हो गए। हम इतने पर ही नहीं रुके हैं, हमारा लक्ष्य है कि हर एक घर तक रोशनी पहुंचाएं। इसके लिए सौभाग्य योजना स्वीकृत की गई है। हमने इसे 10-11 अक्टूबर को आरंभ किया था। अभी तक हम 92 लाख घरों को विद्युतीकृत कर चुके हैं। 31 मार्च, 2019 तक हम सभी घरों को विद्युतीकृत कर देंगे।

राज्य सरकारों ने हमें सूचना भेजी कि तीन करोड़ 80 लाख घर विद्युतीकृत नहीं हुए हैं। हम 31 मार्च तक इन्हें विद्युतीकृत करने का लक्ष्य रखते हैं। हम प्रयास करेंगे कि इन्कलूडिड ओडिशा दिसम्बर तक इसे पूरा कर लें। बाकी जितने भी घर बचे हैं, उन्हें दिसम्बर तक पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम 92 लाख घर कर चुके हैं और इनको भी कर देंगे।

श्रीमती रंजीत रंजन : माननीय अध्यक्ष जी, यह बिजली से जुड़ा हुआ मामला है। मैं आपसे बिहार के बारे में कहना चाहती हूँ, यहां मीटर रीडिंग में बहुत ज्यादा खामियां हैं, एक तो इसे प्राइवेटाइज कर दिया गया है। जिसका 200 रुपए का बिल होना चाहिए उसका 2000 रुपए आता है, जिसका 500 रुपए होना चाहिए उसका 5000 रुपए आता है। इसका संशोधन करने के बजाय उन लोगों पर केस कर दिया जाता है, एफआईआर कर दी जाती है। वे जनप्रतिनिधि के पास भागते फिरते हैं। उनको फाइन भी देना पड़ता है। सरकार ने इसके लिए क्या प्रावधान किया है?

बिहार में कितने प्रतिशत बिजली का काम बाकी है? जहां ऑलरेडी बिजली थी, तारों के जीर्णोद्धार के लिए ठेके दिए गए थे, वहां भी बहुत खामियां हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि इसका कितने प्रतिशत काम बाकी है?

श्री आर. के. सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, हमने जो योजना स्वीकृत की है, पहला बिंदु मीटरिंग के बारे में है। दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के अंतर्गत हम मीटर खरीदने के लिए भी राज्य सरकारों को राशि दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो कहा है, बिल्कुल सही है कि मीटर रीडिंग में खामियां हैं। मीटर रीडिंग समय पर नहीं होती है। हमारी राज्य सरकारों से बैठकें होती हैं, उसमें यह चर्चा होती है। कहीं-कहीं तो बिल तीन-छः महीने बाद जाते हैं। हमने इसके लिए राज्य सरकारों से कहा है कि इसके लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लें और इसके लिए भी राशि दे रहे हैं।

हमने राज्य सरकारों से कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स की ओर जाएं, इसके लिए भी हम राशि दे रहे हैं। इसके अंतर्गत मीटर रीडिंग की जरूरत नहीं होगी। कभी मीटर रीडर रीडिंग करने जाता है और कभी नहीं जाता है। इन मीटर्स की सहायता से कन्ज्यूमर्स देख सकेंगे कि जो राशि

क्रेडिट की गई है, अगर वह खत्म हो रही है तो उसे पुनः राशि मोबाइल से रिचार्ज कर सकेंगे। इससे गरीबों को भी लाभ होगा क्योंकि अगर गरीब के पास 100 रुपए हैं तो वह 100 रुपए का रिचार्ज करेगा और अगर 50 रुपए हैं तो 50 रुपए का रिचार्ज करेगा। अगर मीटर रीडर तीन महीने तक नहीं आया, अगर आया तो अनाप-शनाप लिख दिया, तो क्या समस्या नहीं होगी? यह समस्या है, यह बिहार में ही नहीं अन्य जगहों पर भी है। इससे यह समस्या समाप्त हो जाएगी। हम राज्य सरकारों से इस बारे में बात कर रहे हैं।

जहां तक गुणवत्ता का सवाल उठा है, इसके बारे में हम राज्य सरकारों से चर्चा करते रहते हैं। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी की बहाली के लिए राज्य सरकारों को राशि दी है। इसका काम है कि हर काम की चैकिंग करे। इसके अलावा एक अलग से ऑडिट सिस्टम रखा है। हमारी टीम भी जाती है, रिपोर्ट भेजती है और इसे हम राज्य सरकारों को भेजते हैं कि यहां समुचित ढंग से काम नहीं हुआ है, इसे आप कराएं।

श्री उदय प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ऊर्जा विभाग लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है। विद्युत विभाग में निर्माण कार्यों पर क्वालिटी और गुणवत्ता पर प्रश्न चिह्न लगता रहता है, जबकि भारत सरकार राज्यों को राशि देती है। ग्रामीण विकास विभाग ने एक सेंट्रल मॉनिटर्स बनाए हैं, उनका प्रयोग बहुत सफल रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या विद्युत विभाग ग्रामीण विकास विभाग की तरह सेंट्रल मॉनिटर्स एपाइंट करेगी जो बिजली विभाग में होने वाले काम और भारत सरकार ऐडेड स्कीम्स की सीधे यहां से मॉनिटरिंग कर सके?

श्री आर. के. सिंह: मैडम, हम लोगों ने यह व्यवस्था की है और एक क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म आरईसी में रखा है। उसके अंतर्गत इंस्पेक्टर्स यहां से जाकर इंस्पेक्शन करते हैं और जहां-जहां खामियां होती हैं, उनको राज्य सरकार के ध्यान में लाते हैं कि इन खामियों को दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कहां पर कितनी खामियां मिलीं और उनमें से कितनी खामियां दुरुस्त हुई हैं, इसके

बारे में प्रतिवेदन मेरे पास है। इसके अलावा हमने मंत्रालय में आठ टीम बनाई हैं, जहां कोई विशेष शिकायत आती है तो हम मंत्रालय से भी टीम भेजते हैं और उसकी जांच कराते हैं। अगर कहीं पर गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे राज्य सरकारों के ध्यान में लाते हैं। राज्य सरकारों की अपनी टीम अलग हैं।...(व्यवधान)

(Q. 124)

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, भारतमाला परियोजना एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसमें सभी जिलों के बीच माल ढुलाई हेतु इनफॉर्मेटिव इनपुट एवं हमारे पोर्ट्स की कनेक्टिविटी के लिए सभी जिलों में से रास्ते बन रहे हैं, उनके कारण हमारा व्यापार, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार इस देश में करीब 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपये की यह योजना बनी है, यह भी एक रिकॉर्ड है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का अभिनन्दन करता हूँ, बधाई देता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सारा सदन मेरी भावना से सहमत होगा।

अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र में पोर्ट्स कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स पार्क को बढ़ावा देने हेतु 28 में से तीन रिंग रोड्स और 44 में से 12 इकोनोमिक कॉरीडोर्स महाराष्ट्र से गुजर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अभी तक कितना काम हुआ है और बाकी काम कब तक होगा?

श्री नितिन गडकरी: अध्यक्ष महोदया, स्वाधीनता के बाद देश के इतिहास में भारतमाला के रूप में यह जो प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, इसमें 84 हजार किलोमीटर नेशनल हाइवेज का हम विकास कर रहे हैं। इसमें लगभग साढ़े सात लाख करोड़ रुपये की इनवेस्टमेंट होने की संभावना है। इसमें 550 जिलों को फोर-वे नेशनल हाइवेज से जोड़ने की बात है, जिसमें नॉर्थ-ईस्ट को प्रायोरिटी दी गई है। इसके कारण दस करोड़ मैन डेज इम्प्लायमेंट जेनरेट होगा और कंस्ट्रक्शन फेज में 22 मिलियन परमानेंट जॉब्स क्रिएट होंगी। हम इस प्रोजेक्ट में दो फेजेज में काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इसे सेलेक्ट करते समय, हमने गुजरात के भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट की मदद लेकर बॉर्डर रेट, ट्रैफिक डेन्सिटी, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट, इकोनोमिक कॉरीडोर, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया आदि सभी चीजों का अध्ययन किया है। ऐसा करते समय, फर्स्ट फेज में 24,800 किलोमीटर लेंथ को एड्रेस करने का हमने निर्णय लिया है। इसकी कॉस्ट 3 लाख 85 हजार करोड़ रुपये है और एनएचडीपी का जो 10 हजार किलोमीटर बैलेंस था, उसे भी जोड़कर 34,800 किलोमीटर फर्स्ट

फेज में लिया गया है। इसकी कीमत 5 लाख 35 हजार करोड़ रुपये है। मैं सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस पर हम लगातार काफी गति से काम कर रहे हैं। इसमें अभी तक करीब 3500 किलोमीटर और एक लाख 44 हजार करोड़ रुपये के कामों का शुभारम्भ हुआ है। इस साल मार्च तक हम करीब 5 लाख करोड़ रुपये के काम और करीब 20 हजार किलोमीटर तक के काम की शुरुआत करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एक लाख 44 हजार करोड़ रुपये के काम आलरेडी शुरू हो चुके हैं और बाकी कामों की भी शुरुआत होगी।

जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, महाराष्ट्र के बारे में अलग से जानकारी अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में 980 किलोमीटर के काम की शुरुआत हुई है। सबसे महत्वपूर्ण चीज, जिसे इस सदन में बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, जैसे दिल्ली से मुंबई कॉरिडोर है, हम नया ग्रीन हाइवे बना रहे हैं, वह नया ग्रीन हाइवे बैकवर्ड एरिया से जा रहा है। यह दिल्ली से शुरू होकर जयपुर रिंग रोड के पास जाएगा, जयपुर रिंग रोड से अलवर जाएगा।

यह अलवर से झबुआ, रतलाम से हो कर बड़ोदरा जाएगा। राजस्थान, हरियाण, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के बैकवर्ड एरिया, इसके कारण हम दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बनाते तो हमारी लैंड एक्विजिशन कॉस्ट प्रति हेक्टेयर साढ़े सात लाख रुपये होती, पर बैकवर्ड एरिया को सेलेक्ट करने कारण हमारी कॉस्ट, हम दिल्ली-मुंबई के बीच जो हाईवे बना रहे हैं, इसमें 16 हजार करोड़ रुपये लैंड एक्विजिशन में बच गई है। मध्य प्रदेश का बैकवर्ड एरिया झबुआ, रतलाम, राजस्थान में अलवर और हरियाणा के बैकवर्ड एरिया से यह गुजरेगा। ... (व्यवधान)

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के एक लाख करोड़ रुपये में से 44 हजार करोड़ रुपए बड़ोदरा से मुंबई के लिए है और 44 हजार करोड़ रुपये के कार्य का भी शुभारंभ हो गया है। अब उसका भूमि पूजन करना है। हम कोशिश करेंगे कि यह इस साल दिसम्बर तक हो जाए। हम मुंबई से कोचिन जाने के लिए नया रोड तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे दो सौ किलोमीटर दूरी बचेगी। 'भारतमाला' में यह जोड़ा गया है कि कहां से कितना ट्रैफिक जाता

है, कैसे दूरी कम होती है, इसके लिए क्या होगा? ...(व्यवधान) हम उसको कन्याकुमारी तक जोड़ेंगे।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि 'भारतमाला' में काफी प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं। मैं सबसे अच्छी बात बैकवर्ड एरिया, राजस्थान के लिए कहूंगा कि 17 जगहों पर एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है – रोड कम एयर स्ट्रिप। जहां हवाई जहाज भी उतर सकता है। जहां तीन सौ किलोमीटर दूरी तक हवाई अड्डा नहीं है, वहां हम रोड का ट्रैफिक बंद करके, जैसे रेलवे का फाटक होता है, हवाई जहाज उतरेगा और चला जाएगा तो रोड ट्रैफिक शुरू हो जाएगा। जब मैं यह बात कहता हूँ तो लोगों को लगता है कि यह एक सपना है, विश्वास रखना कठिन है। मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि मैं जो बात बता रहा हूँ, वह एक-एक बात हो कर रहेगी, निश्चित रूप से होगी और निश्चित रूप से उससे देश की तस्वीर बदलेगी।

श्री संजय धोत्रे : अध्यक्ष महोदया, नेशनल हाईवे, भारतमाला प्रोजेक्ट के जो काम होते हैं, इसमें बहुत सारा मैटेरियल लगता है। उसमें सैंड, गिट्टी एवं अन्य मैटेरियल लगता है। नितिन जी की अभिनव कल्पना से महाराष्ट्र में जलयुक्त शिवार का काम चल रहा है, उसमें बड़ी अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल किया है, उसके कारण वाटर कंजरवेशन और वाटर स्टोरेज भी बढ़ गया है। यह मैटेरियल दूर-दराज से आता है, इसके कारण हमारे स्टेट हाईवे, जिले और गांव की सड़कों पर जो हेवी ड्यूटी ट्रक्स वगैरह चलते हैं, उससे रोड खराब होते हैं, उसका काम बाद में नहीं होता है।

मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि पांच लाख, 35 हजार करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है तो थोड़ा उसके लिए प्रोविजन हो जाए तो हमारे रोड्स ठीक हो जाएंगे।

श्री नितिन गडकरी : अध्यक्ष महोदया, सम्मानीय सदस्य जो कह रहे हैं, प्रोजेक्ट में वह प्रोविजन नहीं है। स्टेट के रोड वैसे भी खराब हैं। वे एनएचआई के कारण थोड़ी-बहुत खराब हो सकते हैं, लेकिन वह केवल हमारे कारण खराब हुई है, ऐसी बात सच नहीं है। स्टेट का काम विलेज और डिस्ट्रिक्ट रोड्स को ठीक करना। यदि एक-दो जगह हमारे काम के कारण खराबी हुई है, अगर ऐसा

वे मेरे ध्यान में लाएंगे तो सरकार रोड को रिपेयर करने के बारे में पॉजिटिवली सोचेगी, पर बेसिकली हमारी जिम्मेदारी नहीं है।

SHRI RAHUL SHEWALE : The Mumbai-Pune Expressway was made fully operational in 2002. But no one thought that it would face traffic congestion in just over a decade. Similar problems are being faced by the other existing national highways across the country.

So, I would like to know from the hon. Minister as to what steps have been taken by his Ministry under his ambitious Bharat Mala project to address the issue of futuristic growth of traffic and congestion and thus to make highways congestion free for longer periods.

श्री नितिन गडकरी : महोदया, माननीय सदस्य ने सही बात कही है कि ट्रैफिक डेनसिटी बढ़ रही है। इस वजह से दो लेन को चार लेन में, चार लेन को छह लेन, छह लेन को आठ लेन और आठ लेन को एक्सप्रेस हाइवे में बदलने की जरूरत है। सरकार की अप्रोच थी कि कोई नेशनल हाइवे जाहिर नहीं करना है। इसके लिए हमने 96 हजार किलोमीटर सड़क की लेंथ को 2 लाख किलोमीटर ले जाने का तय किया। मुझे समझ नहीं आता कि हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में इसके प्रति बड़ा रेसिस्टेंस है, जबकि पांच लाख दुर्घटनाएं होती हैं, डेढ़ लाख लोग मर जाते हैं। आटोमोबाइल की 22 परसेंट की ग्रोथ है और एनएच बढ़ाने के लिए बड़ा रिजर्वेशन है। जो-जो माननीय सांसद मुझसे मिले हैं और उन्होंने जो-जो बात कही, मैंने उनके एरिया की ट्रैफिक डेनसिटी को स्टडी करके एनएच घोषित किया है और अभी तक 1 लाख 70 हजार किलोमीटर सड़क बना चुके हैं, जिसमें 50 हजार किलोमीटर प्रिंसिपल हाइवे है और बाकी हमने एनएच कन्वर्ट किया है।

महोदया, एक बात यह महत्वपूर्ण है कि जहां 10 हजार पीसीयूज का ट्रैफिक है, वहां चार लेन कर रहे हैं। जहां पीसीयूज ट्रैफिक 20 हजार के ऊपर है, वहां छह लेन कर रहे हैं। देश में 12

एक्सप्रेस हाइवे बना रहे हैं। एक्सप्रेस हाइवे एक्सेस कंट्रोल, जैसे दिल्ली-मेरठ 14 लेन का हाइवे बनाया है। संसद की कार्यवाही को कवर करने वाले जो पत्रकार वहां रहते हैं, मुझे कहते हैं कि पहले दो घंटे का समय आने के लिए लगता था, अब वहां 20 मिनट का समय लगता है। अब दिल्ली से मेरठ कुल 40 मिनट का समय अगली फरवरी तक लगेगा। हम 30 हजार किलोमीटर की रोड को 4 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं और कुछ जगह 6 लेन कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम यही है कि इसके लिए मैटीरियल लगता है, एनवायर्नमेंट मिनिस्ट्री द्वारा फारेस्ट की क्लियरेंस चाहिए होती है, बैंकों से फाइनेंस चाहिए होता है। इस वजह से इसमें दिक्कत आती है और अगर यह दिक्कत दूर हुई तो इस काम में तेजी आ सकती है और जैसे-जैसे ट्रैफिक डेनसिटी बढ़ेगी, हम लेंथ बढ़ाएंगे। जैसा एनएच का नेटवर्क है, वैसे मेट्रो सिटी को एक्सप्रेस हाइवे से बंगलूरु से चेन्नई, बंगलूरु से हैदराबाद, बंगलूरु से विजयवाड़ा, विजयवाड़ा से चेन्नई, नागपुर से हैदराबाद, मुम्बई से दिल्ली, दिल्ली से कटरा आदि...(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपने बंगाल के लिए क्या किया है?

श्री नितिन गडकरी : बंगाल में भी होगा, लेकिन वहां आप लैंड एक्विजिशन करने में मदद कीजिए।

महोदया, मुझे लगता है कि इस काम को करने में और गति आएगी। ...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, क्या हमें बोलने का मौका नहीं मिलेगा?

हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी पार्टी के सदस्य का नाम लिया है। हर विषय में आप नेता लोग आगे मत आइए।

...(व्यवधान)

SHRI VINCENT H. PALA : Thank you, Madam. ... (*Interruptions*) The Minister has said that 2,000 kms. road is being considered along the international border. ... (*Interruptions*)

In my State of Meghalaya, we have 480 kms. of international border. ...
(Interruptions) After construction of fencing over there, the people in the border areas have been sandwiched as they cannot go to Bangladesh, and at the same time they cannot go to Meghalaya also. ... *(Interruptions)* We have big villages that need to be connected by roads. ... *(Interruptions)*

Will the Minister consider connecting those villages through the Bharatmala Project? He had stated that 14 lanes have been constructed on a stretch of 980 kms. I need only 50 kms. These villages in the border areas have been sandwiched because of construction of border fencing, and they do not have road connectivity in summer. Will the Minister consider this as a special case? Though it is a State road, I would request him to give special fund for the international border to connect these villages with rest of India.

श्री नितिन गडकरी : महोदया, गांवों को जोड़ने का काम हमसे जुड़ा नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत राज्य सरकार को देता है, उससे यह काम होता है। इंटरनेशनल लेवल पर मेघालय का छह हजार करोड़ रुपये का लोन हमने मंजूर किया है, जो म्यांमार तक जा रहा है। नेपाल, भूटान, इंडिया और बांग्लादेश को जोड़ने के लिए एडीबी ने 24 हजार करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स मंजूर किए हैं, जिनमें कुछ ब्रिज भी हैं। मेघालय, त्रिपुरा और विशेष रूप से नार्थ ईस्ट को हमने प्राथमिकता दी है। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार देश में तय हुआ कि नार्थ-ईस्ट पर विशेष ध्यान देना है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के इतिहास में पहली बार एक लाख करोड़ रुपये के हाइवेज़, रोड़ नार्थ-ईस्ट के लिए मंजूर किए हैं और 45 हजार करोड़ रुपये के काम शुरू हो चुके हैं। ... (व्यवधान) आप शांत रहिए, आपने 50 साल में ब्रह्मपुत्र में जितने ब्रिज नहीं बनाए हैं,

हमारी सरकार वहां पांच ब्रिजेज बना रही है। मुझे लगता है कि इसमें नार्थ-ईस्ट को प्राथमिकता मिलेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : भूरिया जी, आपके यहां से 'भारत माला' जा रही है। प्रश्न काल का समय समाप्त होने जा रहा है, आप एक मिनट में अपनी बात रखिए।

...(व्यवधान)

श्री कांति लाल भूरिया : महोदया, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह सुनने में अच्छा लग रहा है। वह मेरे क्षेत्र से गुजर रही है, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि मैं सदन में धरना दे चुका हूँ। इंदौर-अहमदाबाद रोड़ 50 किलोमीटर सिंगल रोड़ ही है। वहां 200-300 लोगों की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है। आपने कहा था कि छह महीने में इस काम को पूरा करेंगे, आज एक साल हो गया है और वहां काम भी शुरू नहीं हुआ है।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि इस रोड़ का काम कब तक पूरा हो पाएगा?

12 00 hrs

श्री नितिन गडकरी : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने एक बात साफ कही है कि आपके यहाँ से एलाइनमेंट जा रही है। आपके यहाँ काम शुरू हो गया है, मैंने यह दावा नहीं किया है। दिल्ली से मुंबई लेन में केवल वड़ोदरा टू मुंबई लेन के लिए 44 हजार करोड़ रुपये के कांट्रैक्ट्स अवार्ड हुए, मैंने केवल इतना ही कहा। अभी आपके यहाँ काम शुरू नहीं हो सकता है, उसमें अभी समय लगेगा।

मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि दिसम्बर के अंत तक, यह मैं पक्का आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन शायद दिसम्बर के अंत तक आपके यहाँ की एलाइनमेंट पक्की करके और टेंडर करके काम शुरू करने का हमारा प्रयास होगा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे इसी रेज़ीम में आपके यहाँ का काम शुरू हो जाए।

जो अहमदाबाद की रोड़ है, उसके बारे में स्पीकर महोदया आपको भी पता है, आपके यहाँ भी यह समस्या आयी थी। आपने तीन बार कांट्रैक्टर्स की मीटिंग बुलायी थी। वह प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गयी है। वही कांट्रैक्टर इनके यहाँ है। वह बैंकरप्ट हो गया है। उसके पास पैसे नहीं हैं।

एनएचएआई से 50 प्रतिशत पैसे लेकर हम उस काम को कर रहे हैं। उसमें बैंकों का एनओसी चाहिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। यह एक बहुत ही कॉम्पलीकेटेड केस बन गया है, फिर भी मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि इस संबंध में मार्ग निकालकर काम पूरा किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष : मगर उस एरिया को भी कवर करना बहुत जरूरी है। यह बात सही है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे विभिन्न विषयों पर कुछ सदस्यों से 'स्थगन प्रस्ताव' की सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं। मामले महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अन्य अवसरों पर उठाये जा सकते हैं। इसलिए मैंने 'स्थगन प्रस्ताव' संबंधी किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष महोदया, ग्वालियर-शिवपुरी-देवास फोरलेन योजना को यूपीए सरकार ने 3,900 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया था। हमने इसका शिलान्यास भी किया था। विगत 23 जुलाई को माननीय गडकरी जी लोकार्पण के कार्यक्रम में गये थे। स्थानीय सांसद होने के नाते मुझे न तो उस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया और न ही आमंत्रण कार्ड पर मेरा नाम था। शिला-पट्टिका में मेरा नाम लिखा गया था, लेकिन उस शिला-पट्टिका को तोड़कर नयी शिला-पट्टिका बनवायी गयी। श्री गडकरी साहब स्वयं उस कार्यक्रम में थे। ...(व्यवधान) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य सरकार के बहुत-से अधिकारी मौजूद थे।...(व्यवधान) यदि स्थानीय सांसदों के मामले में नियमों का उल्लंघन होगा, हमारा अपमान होगा, ...(व्यवधान) तो यह विशेषाधिकार नियम का प्रस्ताव मैं आपके द्वारा मूव कर रहा हूँ। अगर सांसदों की गरिमा का ध्यान इस सदन में नहीं रखा जाएगा, शिला-पट्टिका तोड़ी जाएगी, ...(व्यवधान) यह लोकतंत्र का गला घोटने का काम कर रही है। ...(व्यवधान) माननीय गडकरी जी यहाँ बैठे हैं, उनके साथ मेरी फोन पर चर्चा हुई है। ...(व्यवधान) उन्होंने स्वयं खेद प्रकट किया है। ...(व्यवधान) लेकिन मैं प्रिविलेज मोशन मूव करना चाहता हूँ।...(व्यवधान) मैं चाहता हूँ श्री गडकरी साहब इसका जवाब इस सदन में दें क्योंकि वे यहाँ मौजूद हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह हो गया। अब बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह तो उन्होंने प्रिविलेज मोशन दिया है।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Gadkari ji, he is talking about Privilege Motion given by him against Shivraj Singh Chauhan, not against you.

...(व्यवधान)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, पोत परिवहन मंत्री, तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री (श्री नितिन गडकरी): सम्माननीय स्पीकर महोदया, इन्होंने जो बात बताई है,

मैं वहां गया था, वह बात मेरे से संबंध में है। जब मैं वहां गया था, तो यह बात सच है कि पत्रिका में उनका नाम नहीं था। यह कार्यक्रम वहां के स्थानीय विभाग के स्तर पर आयोजित किया गया था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि मैं विभाग का मंत्री हूँ। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। फिर इनकी पार्टी के एक एम.एल.ए. मुझसे आकर मिले और उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा-ऐसा हुआ है। इस पर मैंने वहां के जिलाधिकारी को बुलाकर पूछा कि यह नाम क्यों नहीं डाला है? उन्होंने कहा कि उन्होंने इनको फोन किया, लेकिन सम्माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। ... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : नहीं अध्यक्ष महोदया, ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing will go on record.

... (Interruptions) ... *

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: What is this?

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: He is talking about Privilege Motion given by him against the Chief Minister. आप सब बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री नितिन गडकरी : स्पीकर महोदया, ... (व्यवधान) आप मुझे बोलने तो दो। ... (व्यवधान) मैं आपको बात क्लियर कर रहा हूँ। ... (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Now, you also listen to him. You have to listen to him.

... (Interruptions)

* Not recorded

HON. SPEAKER: Nothing will go on record. Only the Minister's statement will go on record.

...(Interruptions)...

HON. SPEAKER: Not like this.

... (Interruptions)

श्री नितिन गडकरी: मैंने कलेक्टर की कही हुई बात यहां कही है। मैडम, उसके बाद भी मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए या न आए, उसका नाम लिखना चाहिए था। उसका नाम पत्थर पर रखना चाहिए था। यह गलती हुई है। मैं डिपार्टमेंट की ओर से सम्माननीय सदस्य से क्षमा मांगता हूं, ताकि अगली बार ऐसा न हो। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठो। अब बहुत हो गया।

...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: What more do you want? मैंने कहा न कि मैं देखूंगी। आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : अध्यक्ष महोदया, आपको संरक्षण देना होगा।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या मुझे माफी मांगनी पड़ेगी?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मुझे मालूम है। मैंने बोल दिया है। आपको संरक्षण देने के लिए उन्होंने बोला न, और संरक्षण क्या चाहिए? आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, बहुत ज्यादा नहीं बोलना है।

...(व्यवधान)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष: आइटम नंबर-5। श्री राम कृपाल यादव जी।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम स्पीकर, इसके जनरल इश्यू होने की वजह से आपके इंस्ट्रक्शंस हर जगह जाने चाहिए। यह बात ठीक है कि गडकरी जी ने माफी मांग ली। यह अलग बात है, लेकिन बाकी सभी एम.पीज़., चाहे वे हमारी पार्टी के हों या किसी दूसरी पार्टी के हों, अगर सभी को इसी ढंग से ट्रीट किया जाएगा, तो अच्छा नहीं है। इसीलिए आपकी ओर से सख्त कदम उठाया जाना चाहिए और आपको यह कहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी गलती करता है, तो आप उनके लिए अपनी ओर से आप कुछ सजा दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं किसी को सजा नहीं दे सकती हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जहां तक मेरी जानकारी है,

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप प्लीज़ बैठिए। यहां कोई अदालत नहीं बैठी है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बहुत ज्यादा नहीं बोलना। मैं बोलूंगी तब न?

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आई एम सॉरी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बोलने नहीं दोगे, तो मैं संरक्षण कहां से दूंगी? लड्डू लेकर दूं? आप मुझे बोलने तो दो।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: यह अच्छा एटिट्यूड नहीं है।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा खान मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि ज्योतिरादित्य जी गुना के सम्माननीय सांसद हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं होती हैं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास वे बखूबी करते हैं। इसमें कहीं कोई बाधा नहीं आती है। उस दिन मैं वहां नहीं था, लेकिन मैं समझता हूँ कि नितिन गडकरी जी इस सदन के सम्माननीय सदस्य हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं। उन्होंने इस बात को स्वीकार भी किया और इसके बाद स्वीकार किया कि वहां के कलेक्टर ने आपसे बात की। उसके बाद उन्होंने आपसे सॉरी भी बोला। मैं समझता हूँ कि इसके बाद यह बात खत्म हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आप भी सांसद रही हैं, मैं भी सांसद रहा हूँ और ये भी सांसद रहे हैं। यू.पी.ए. सरकार के समय भाजपा के कौन से सांसद को बुलाया जाता था? ...(व्यवधान) जब कांग्रेस की सरकार राज में थी, तब किस को बुलाया जाता था?... (व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : हर एक को बुलाया जाता था। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं इस पर बहस नहीं चाहती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: हर चीज़ को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। ...(व्यवधान) जब नितिन गडकरी जी ने माफी मांग ली, तो मैं समझता हूँ कि यह अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। ...(व्यवधान) यह तरीका बिलकुल उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह गडकरी जी का बड़प्पन है कि उन्होंने तुरंत उठकर माफी मांगी है। मैं वास्तव में इसके लिए उनकी सराहना करती हूँ। इनके लिए मैं यह कहूंगी कि ज्योतिरादित्य जी, यह पद्धति नहीं है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह बोलने का तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

12 10 hrs**PAPERS LAID ON THE TABLE**

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid on the Table.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI R.K. SINGH): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the North Eastern Electric Power Corporation Limited and the Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9388/16/18]

(ii) Memorandum of Understanding between the THDC Limited and the Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9389/16/18]

(iii) Memorandum of Understanding between the NHPC Limited and Ministry of Power for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9390/16/18]

(iv) Memorandum of Understanding between the NHDC Limited and NHPC Limited for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9391/16/18]

(2) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the DNH Power Distribution Corporation Limited, Silvassa, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 9392/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON RADHAKRISHNAN): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2016-2017.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Maritime University, Chennai, for the year 2016-2017.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9393/16/18]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Noida, for the year 2016-2017.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 9394/16/18]

- (5) A copy each of the Notification No. G.S.R.351(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 9th April, 2018 approving the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Amendment Regulations, 2018 under sub-section (4) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963.

[Placed in Library, See No. LT 9395/16/18]

(6) A copy of the Admiralty (Assessors) Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.601(E) in Gazette of India dated 29th June, 2018, under sub-section (4) of Section 18 of the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Act, 2017.

[Placed in Library, See No. LT 9396/16/18]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब कोई नहीं बोलेगा, प्लीज, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: अब यह बहुत ज्यादा हो रहा है। प्लीज, आप सब लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठिए, अब ओवर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। आप बैठिए, मैं भी कुछ बोलने वाली थी, वह भी नहीं बोलूंगी। गडकरी जी, वास्तव में यह आपका बड़प्पन है और मैंने देखा है, इसमें यहां से बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि जहां-जहां केन्द्र सरकार का कोई भी कार्यक्रम होता है, उसमें बुलाना है, यह होता है और बुलाया जाता भी है। मगर जहां नहीं है, वहां बुलाना चाहिए।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के वर्ष 2017-18 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9397/16/18]

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): महोदया, मैं मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड तथा खान मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 9398/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (SHRI JAYANT SINHA): I beg to lay on the Table a copy of the Airports Authority of India (Conditions of Service of the Chairman and other Members) Amendment Rules, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.1577(E) in Gazette of India dated 12th April, 2018 under Section 43 of the Airports Authority of India Act, 1994.

[Placed in Library, See No. LT 9399/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Regional Institute of Water and Land Management, Tezpur, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
- (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Regional Institute of Water and Land Management, Tezpur, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9400/16/18]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Memorandum of Understanding between the National Projects Construction Corporation Limited and the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9401/16/18]

(ii) Memorandum of Understanding between the WAPCOS Limited and the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 9402/16/18]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Hydrology, Roorkee, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Hydrology, Roorkee, for the year 2016-2017.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 9403/16/18]

- (6) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Betwa River Board, Jhansi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Betwa River Board, Jhansi, for the year 2016-2017.
- (7) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (6) above.

[Placed in Library, See No. LT 9404/16/18]

- (8) A copy of the Cauvery Water Management Scheme, 2018 (Hindi and English versions) published in Notification No. S.O.2236(E) in Gazette of India dated 1st June, 2018, under sub-section (7) of Section 6A of the Inter-State River Water Disputes Act, 1956.

[Placed in Library, See No. LT 9405/16/18]

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय टम्टा): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

1. निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)---
(एक) जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 9406/16/18]

(दो) कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा वस्त्र मंत्रालय के बीच वर्ष 2018-19 के लिए हुआ समझौता ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT 9407/16/18]

2. केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 13ख की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

(एक) का.आ.2930(अ), जो 15 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा डायरेक्टर सेलीकल्चर एंड वेविंग डिपार्टमेंट, मेघालय सरकार को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(दो) का.आ.2352(अ), जो 8 जून, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 8क के अंतर्गत रेशमकीट बीज के अधिसूचित प्रकार या किस्मों के लिए न्यूनतम गुणवत्ता मानक और शर्तें अधिसूचित की गई हैं।

(तीन) का.आ.1771(अ), जो 26 अप्रैल, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा श्री नीरज शेखर और श्रीमती संपतिया उड्के संसद सदस्यों (राज्य सभा) को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

(चार) का.आ. 2184(अ), जो 30 मई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा आयुक्त और प्रधान सचिव, कुटीर और ग्रामीण उद्योग, गुजरात सरकार, गांधी नगर को 3 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 9408/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): On behalf of Dr. Satya Pal Singh, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the years 2014-2015 to 2016-2017, together with Audit Report thereon.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) on the Audited Accounts of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the years 2014-2015 to 2016-2017.
- (2) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9409/16/18]

12 12 hrs

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

30th Action Taken Report

श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी (अहमदनगर): महोदया, मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति (16वीं लोक सभा) के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर समिति का की-गई-कार्रवाई संबंधी तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी स्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12 13 hrs

STANDING COMMITTEE ON LABOUR

39th Report

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): महोदया, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित “कर्मचारी राज्य बीमा निगम-स्थापनों की कवरेज बकायों की वसूली और स्कीम के अंतर्गत अस्पतालों और औषधालयों के कार्यकरण” के बारे में श्रम संबंधी समिति का 39वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

12 14 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE

143rd to 145th Reports

DR. KAMBHAMPATI HARIBABU (VISA KHAPATNAM): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:-

- (1) 143rd Report on Action Taken by Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its 137th Report on 'Trade with Association of South-East Asian Nations (ASEAN)'.
 - (2) 144th Report on Action taken by Government on the Recommendations/Observations of the Committee contained in its 139th Report on 'Impact of Goods and Services Tax (GST) on Exports'.
 - (3) 145th Report on 'Impact of Chinese Goods on Indian Industry'.
-

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): I rise to mention in this House about a very serious incident that is happening throughout the country. The National Crime Record Bureau in its last statistical report for 2016 has reported that 1,11,569 children were reported missing that year across the country. The NCRB further reported that half of such missing children have been traced while rest are presumed abducted, remained untraced at the end of the year.

Not necessarily all of these children were abducted but there is no doubt that majority of such children were abducted, with bias towards female victims. Two third of the missing children were females which points towards the potential of sexual exploitation.

Further, there is a genuine fear of child snatchers in rural areas, particularly tribal areas, of the country and this crime is considered relatively more heinous in human minds. As a result, any rumour of presence of child snatchers in an area energizes mob to gather in greater numbers than a rumour of any other sort of criminal activity.

Recently, three Odia boys who were working in Chennai were walking back to their homes and they started giving chocolates to some street urchins whom they found on the streets. This was seen by some people on the street who mistook those three Odia boys to be child snatchers and started chasing them. These three boys ran for their lives and fortunately they were saved. They were just giving some chocolates to children out of love and that created panic on the street and they had to run for their lives.

I, therefore, urge upon the Government to take necessary steps to rein in spread of false rumours on social media which has actually affected large parts of the country. Rumours are being spread on social media like Whatsapp and this has resulted in mob lynching of a person in Assam. It is necessary that rapid prosecution of those found guilty of child trafficking is done and the local population is made aware of safety of their children particularly in remote areas where the police is ineffectual.

Hon. Minister of Women and Child Welfare is moving a very important Bill today. The problem today in the country is that child snatching rumours are creating widespread panic and they are leading to incidents of mob lynching which is actually creating problems in the country. The Government should take such steps that can not only address the issue of missing children but also the issue of mob lynching of people wrongly suspected to be child snatchers, as these two issues are deeply interconnected.

HON. SPEAKER: Dr. Kulmani Samal, Shri P.R. Sundaram, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Bhairon Prasad Mishra, Dr. P.K. Biju, Dr. Kirit P. Solanki, Shri Nishikant Dubey, Shrimati Supriya Sule and Shri Dhananjay Mahadik are permitted to associate with the issue raised by Shri Bhartruhari Mahtab.

SHRI P.R. SUNDARAM (NAMAKKAL): Madam Speaker, the common man is facing serious problems because of the truck strike in Tamil Nadu which has entered the seventh day and is causing a loss of Rs.1000 crore to Tamil Nadu and millions of crores of loss to Government of India.

The Western Districts of Tamil Nadu are badly affected as hundreds of lorry drivers have been forced to go without work and live without their daily wages and jobs. In my Constituency Namakkal, three crore eggs are produced and supplied all over Tamil Nadu, Kerala and Karnataka. More than five crore eggs were lying stagnant due to the current lorry strike. The lorry association had said that the strike was unavoidable because the fuel price hike has happened and the Central Government is not fulfilling their long-pending demands.

Sago, turmeric, steel and textile products worth of Rs.300 crore are lying stagnant in Karur, Namakkal and Salem alone. Prices of essential items, vegetables and fruits have increased steeply and they will be further affected in the next few days if the lorry strike continues. Tamil Nadu Government has ordered that farmers be allowed to take their vegetables to markets free of cost in government buses and supply milk in minivans. Yesterday, hon. Deputy Speaker Mr. Thambidurai, our party leader Dr. Venugopal and myself met the hon. Minister for Road Transport Shri Nitin Gadkari and requested him to find a solution to this issue. Hon. Minister said that he would consider our request. Hence, I request the Government of India to take immediate action to end the ongoing strike by truck operators. Thank you.

HON. SPEAKER: Kunwar Pushpendra Singh Chandel, Shri Rabindra Kumar Jena, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri K. Ashok Kumar, Shri G. Hari and Shrimati K. Maragatham are permitted to associate with the issue raised by Shri P.R. Sundaram.

भाषण नहीं करना है। सलीम जी, मैंने आपको एक ही वाक्य के लिए अलाऊ किया है।

SHRI MOHAMMAD SALIM (RAIGANJ): Hon. Speaker Madam, a very pertinent issue is raised. पूरे देश में यह समस्या है और देश में एक-साथ स्ट्राइक चल रही है। इससे कॉमन कमोडिटीज का अभाव होगा। सरकार को इस पर रेस्पॉंस करना चाहिए और ट्रांसपोर्टर्स की जो जैनविन डिमांड है, उसे मानना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के. बिजू, श्री एम.बी. राजेश, श्री इन्नोसेन्ट और श्री रवीन्द्र कुमार जेना को श्री मोहम्मद सलीम द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

हमारे यहाँ कोल इण्डिया की अनुषांगिक इकाई सीसीएल अंतर्गत कथारा एरिया के वाशरी में 117 और स्वांग वाशरी में कार्यरत 42 प्लांट क्लिनिंग मजदूर जो विगत 20 वर्षों से ठेकेदार के अंतर्गत काम कर रहे थे। 25-11-2016 से बिना कोई पूर्व सूचना दिए अचानक कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक के आदेश पर उन्हें काम से बैठा दिया गया। ये सभी मजदूर सी.एम.पी.एफ. के सदस्य भी हैं और उन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधन द्वारा हाई पावर कमेटी की अनुशंसा के तहत जून 2016 तक इन्हें वेतन का भुगतान भी किया गया है। ये सभी मजदूर आसपास के गांवों के विस्थापित हैं, भू-अर्जन प्रभावित क्षेत्रों के हैं और गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं। लगभग पाँच माह से स्वांग वाशरी में मजदूरों को बिठाकर रखा गया है। तीन माह से इन लोगों को वेतन भी नहीं दिया गया है। वहाँ आन्दोलन हुआ। हम लोगों ने भी अपने स्तर से बात की, लेकिन प्रबंधन का इस पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं है। आज की तारीख में इनके नाम पर करोड़ों रुपये का फंड कहाँ जा रहा है, यह भी समझने की बात है। जो वहाँ का कोयला स्टॉक है, उसकी सफाई करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता है। वहाँ कोयले के स्टॉक में आग लगी हुई है और मजदूरों के अभाव में करीब 5-6 टन कोयले में आग लग चुकी है और इससे सी.सी.एल. को करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है।

महोदया, आपसे आग्रह है कि इस पर कार्रवाई की जाये और मजदूरों को न्याय मिले।
धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरो प्रसाद मिश्रा को श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से पूरे देश के गौरव आई.आई.टी. कानपुर के सम्बन्ध में अवगत कराना चाहता हूँ। कानपुर आई.आई.टी. की स्थापना वर्ष 1962 में हुई थी। जिन लोगों ने वहाँ अपनी जमीन दी थी, वे लगातार उस जमीन का प्रयोग आवागमन के रूप में करते रहे थे। विगत कई वर्ष पूर्व एक बार संस्थान ने उस मार्ग को बंद करने का प्रयास किया तो इस सम्बन्ध में वहाँ के तत्कालीन डायरेक्टर से मिलकर ऐसा न करने के लिए एक लिखित समझौता हुआ। इस लिखित समझौते के बाद विगत दो वर्ष पहले एक बार पुनः ऐसा ही प्रयास हुआ। हमारी मंत्री माननीया स्मृति ईरानी जी के नेतृत्व में एक टीम गई और जाँच करके उस रास्ते को पुनः खोला गया। वह कानपुर महानगर का एक वार्ड है। वहाँ से हमारे पार्श्व भी हैं। वहाँ के एक्टिंग डायरेक्टर श्री मणीन्द्र अग्रवाल के द्वारा पुनः उस मार्ग को बंद करने का कुत्सित प्रयास किया गया है।

मेरा निवेदन है कि नये डायरेक्टर की वहाँ नियुक्ति हो गई है, पुनः भारत सरकार के माननीय मंत्री जी उन्हें निर्देशित करें और वहाँ एक टीम भेजें। वहाँ की लगभग एक लाख की आबादी इससे प्रभावित होती है। उनके लिए आवागमन का अन्य कोई रास्ता नहीं है। इससे लगातार जनाक्रोश फैल रहा है। वहाँ कोई असहज स्थिति उत्पन्न न हो, इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसका संज्ञान लेने की कृपा करेंगी। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरो प्रसाद मिश्रा को श्री देवेन्द्र सिंह भोले द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. चिंतामणि मालवीय (उज्जैन): महोदया, आपने मुझे पूरे देश में फैली अनुसूचित जाति-जनजाति की पीड़ा और विसंगति को सदन के समक्ष रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदया, हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि कानून बनाने का काम विधायिका का है और उसकी व्याख्या न्यायपालिका करती है। पिछले 21 मार्च को माननीय न्यायालय ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार अधिनियम, 1990 में बदलाव करते हुए, जो अपराध दर्ज होते हैं, उसमें गिरफ्तारी के लिए अनुमति आवश्यक कर दी है। यदि सरकारी कर्मचारी होता है तो उसके लिए अधिकारी या नियोक्ता की अनुमति और जन-सामान्य है तो उसके लिए (एस.एस.पी.) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति आवश्यक होती है।

महोदया, इससे बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई है। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों और परेशानियों को समझते हुए इसका तुरन्त संज्ञान लिया और शीघ्र सुनवाई के लिए पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की है। कोर्ट ने इसकी शीघ्र सुनवाई से मना कर दिया है।

महोदया, इसकी वजह से बहुत परेशानी हो रही है। पहले तो रिपोर्ट दर्ज कराने से पहले जाँच होती है और जाँच हो गई तो गिरफ्तारी के लिए दो-दो महीने से ज्यादा का समय लगता है। जो गाँव का गरीब व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, उसको कार्रवाई कराने के लिए एस.एस.पी. के पास जाना पड़ता है। इसके बाद कार्रवाई बहुत कम हो गई है। गिरफ्तारी नहीं होने से और अग्रिम जमानत का प्रावधान होने से अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

महोदया, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि जो सामान्य अपराध होता है, उसकी कार्रवाई तुरन्त हो जाती है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो वह उसी अध्यादेश में जाता है, उस अधिनियम में जाता है। इस वजह से गिरफ्तारी और कार्रवाई में देरी हो रही है। इससे सामाजिक समरसता का वातावरण बिगड़ रहा है। देश में जो पीड़ित और शोषित समाज है, वह अपने आपको असहाय समझ रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना

चाहता हूँ कि यदि इस याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार नहीं है तो सरकार इसके लिए एक अधिनियम लाये। अनुसूचित जाति तथा जनजाति के जो लोग हैं, सरकार उनको इस अत्याचार से मुक्ति दिलाए और उनके साथ खड़े होने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री वीरेन्द्र कश्यप, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री राजेश रंजन तथा डॉ. किरिट पी. सोलंकी को प्रो. चिंतामणि मालवीय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, Madam Speaker, for giving me the opportunity to speak in 'Zero Hour'.

I would like to bring to the notice of the Government the issue of inclusion of specific communities, namely, Sistakaranam, Sondi, and Kalinga Vysya, which are prevalent in the northern districts of Andhra Pradesh, Srikakulam, Vizianagaram, and Visakhapatnam, in the list of OBCs.

Along with the leaders of these associations, I have met the Prime Minister. He has recommended that the request be put forward to the National Commission for Backward Classes and that the Government would also look into it. On the 8th December, 2015, I had asked a Question to the Government of India, in which they had replied that they had got the request from various associations along with the request from the State Government of Andhra Pradesh.

I would like to inform that the communities mentioned have a population of around 12 lakhs. They are among the most backward communities with poor economic, social, and educational status. These communities are highly under-

developed and 90 per cent of their population is living below the poverty line. They are also not able to sustain their children's education.

The people of these communities in the State of Andhra Pradesh have been agitating since the formation of the Mandal Commission in the year 1979 for inclusion of these communities in the list of OBCs.

It is pertinent to inform here that the Government of Andhra Pradesh, after careful examination of the matter, have decided to accept the recommendation of the Andhra Pradesh Commission for Backward Classes to included them in the list of OBCs.

I strongly request and demand the Central Government to look into the matter sympathetically and advise the authorities concerned to include Sistakaranam, Kalinga Vysya, and Sondi communities in the Central list of OBCs.

Thank you very much.

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री राम मोहन नायडू किंजरापु द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व): माननीय अध्यक्ष महोदया, अभी मेरे क्षेत्र में दो घटनाएं हुई हैं, उन दोनों में महिलाओं के साथ जो हुआ, उसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। कल ही एक घटना में कांजुर रेलवे स्टेशन पर एक महिला की साड़ी ट्रेन में अटक गयी, तो रेलवे पुलिस फोर्स (आरपीएफ) के एक कांस्टेबल ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस महिला की जान बचाई। आर.पी.एफ. के उस कांस्टेबल का नाम श्री राजकमल यादव है मैं उनको बधाई देता हूं और सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि उनको सम्मान किया जाए।

इसके अलावा, दूसरी घटना के बारे में मैं क्रिमिनल नेग्लिजेन्स ऑफ कंपनी इन द सिस्टम की बात करना चाहता हूँ, उसके कारण उस महिला पायलट कैप्टन की जान चली गयी। आप जानती होंगी कि कुछ दिन पहले मेरे क्षेत्र घाटकोपर में एक प्लेन क्रैश हुआ था और वह सीधे वर्टिकल क्रैश हुआ। मैं वहां पन्द्रह मिनट में वहां पहुंच गया था। वह प्लेन 10 साल पुराना था। 10 साल पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने स्क्रेप करके उसको बेच दिया था। सात साल तक वह जुहू एयरपोर्ट पर खड़ा था। दो साल पहले ही उसका रिपेयरिंग किया गया था, उसके बाद जो फ्लाइट निकली, उसमें उसको सूरत तक जाना था लेकिन वह आधी दूरी से ही वापस आ गई और वह प्लेन क्रैश हो गई। वहाँ जो महिला पायलट मारिया द्विवेदी थी, अब वह नहीं रही। आज उसका पति दर-दर भटक रहा है। वह कल भी यहां संसद भवन में आया था। माननीय श्री सुरेश प्रभु जी से एवं सिविल एविएशन सेक्रेटरी से मैंने उसकी मुलाकात करवाई, मुम्बई पुलिस से भी मिलवाया। उसका हसबैंड प्रभात कथुरिया कह रहा है कि उसकी पत्नी को न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वह जो सिविल एविएशन कंपनी है, उसका मालिक एक बहुत बड़ा व्यक्ति है और वह कौन है? वह जो कंपनी है, उसका नाम इंडामेर एविएशन प्रा.लि. है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकाली है। आज मेरे पास उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हाजिर हैं। उस सिविल एविएशन कंपनी का हवाई जहाज 10 साल तक एक ही जगह पर खड़ा था। उस कंपनी के चार सिविल एविएशन के अधिकारी जिनमें दो पायलट एवं दो इंजीनियर थे, जो नीचे से चल रहे थे। अगर वह विमान 25 फुट इधर गिरता, तो झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 200 लोगों की जान जाती। जिस कंपनी का वह प्लेन था, उस कंपनी के मालिक का नाम... * है। आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई एफ.आई.आर. नहीं हो रही है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस कंपनी के खिलाफ एफ.आई.आर. रजिस्टर्ड होनी चाहिए- चाहे वह कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसके ऊपर जरूर कार्रवाई होनी चाहिए।

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष: मैंने बोल दिया है कि नाम नहीं लेना है और उनको भी बता दिया है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: किसी का नाम नहीं लेना है। किरीट जी, कंप्लीट करिए। नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

डॉ. किरीट सोमैया : माननीय स्पीकर महोदया, एक पति दर-दर भटक रहा है। आज तक एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं हुई है। यह कोई हद है क्या? आप एफआईआर रजिस्टर्ड करिए।...(व्यवधान) जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आई, उसमें इस कंपनी का क्रिमिनल निगलिजेंस सामने आ गया। 10 साल पहले कुछ लाख में जो प्लेन खरीदा, उसे रिपेयर करके चलाया गया। उसका कोई प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस नहीं किया गया था। मुझे उस महिला को न्याय दिलाना है, उस पति को न्याय दिलाना है। इसकी एफआईआर रजिस्टर्ड हो। कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. किरीट पी. सोलंकी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): माननीय अध्यक्ष जी, हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ, वह कोसी और सीमांचल का क्षेत्र है। 10 साल से वहां अमान परिवर्तन का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक बड़ी रेलवे लाइन नहीं आई है। तकरीबन 2 करोड़ लोग वहां रोज ट्रेन से सफर करते हैं और 90 हजार मजदूर दूसरे प्रदेशों में काम के लिए जाते हैं। वे सहरसा या पटना से ट्रेन पकड़ते हैं। सुपौल का अमान परिवर्तन का काम 10 सालों से बहुत धीमी गति से चल रहा है।

मैं कुछ ट्रेनों के बारे में कहना चाहूंगी। हम एक तरफ बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां पर बड़ी लाइन गई नहीं है और आप 10 साल से वहां काम कर रहे हैं, लेकिन वह हो नहीं रहा है। पूर्व-मध्य रेलवे के समस्तीपुर मंडल के अंतर्गत सहरसा-फारविसगंज रेलखंड पर अमान परिवर्तन का कार्य 10 साल से चल रहा है। अभी बरुआरी तक अमान परिवर्तन का काम हो चुका है, लेकिन फाइबर केबल के नहीं होने के कारण वहां पर काम पेंडिंग पड़ा है। अगर सिर्फ केबल की सप्लाई

वहां पर हो जाएगी, तो वह ट्रेन कम से कम बरुआरी तक चल जाएगी और लोग डायरेक्ट सुपौल से ट्रेन पकड़कर जा सकेंगे। यहां तक कि सहरसा से अमृतसर, पंजाब, दिल्ली या मुंबई के लिए एक भी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है। निर्मली से सकरी रेलखंड के अमान परिवर्तन का कार्य भी काफी धीमी गति से चल रहा है।

कई नई रेल लाइनों की आपने एनाउंसमेंट की। सुपौल से त्रिवेणीगंज, अररिया होते हुए गलगलिया तक नई रेल लाइन की स्वीकृति काफी पहले हुई, लेकिन अभी तक जमीन का अधिग्रहण नहीं हुआ है। सरायगढ़ भवटियाही से निर्मली रेलखंड पिछले 10 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जबकि हजारों करोड़ की लागत से पुल और पुलिया बनकर तैयार हैं। इस रेलखंड में मेगाब्लॉक भी ले लिया गया है। इसके चलते रेलवे को राजस्व की हानि के साथ-साथ आम जनता को भी परेशानी हो रही है।

बिहारीगंज से मुरलीगंज, खुर्दा, जदिया, छातापुर, बलुआ होते हुए वीरपुर तक नई रेलवे लाइन हेतु सर्वे जिसकी आपने घोषणा की थी, उसे अविलम्ब कराया जाए। सहरसा में ओवरब्रिज की घोषणा हुई। मंत्री ने 4 बार शिलान्यास कर दिया, लेकिन अभी तक ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं हुआ है। कुरसैला से बिहारीगंज रेलखंड के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, लेकिन बजट के अभाव में इस खंड का कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। मेरी रिक्वैस्ट है कि जो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां पर लोगों का सपना है कि बड़ी रेलवे लाइन शुरू हो, जो ललित नारायण मिश्रा का भी सपना था, बहुत पहले उन्होंने वहां के लोगों को ट्रैक दिखाया था। मेरा आग्रह है कि इसका काम अविलम्ब शुरू कराया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अंस्तुलन पर एक गंभीर स्थिति ग्रामीण स्तर पर पैदा हो रही है, इसके संबंध में आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं, ताकि भारत सरकार का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय उस पर उचित ध्यान दे।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला-परिषद है। पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था है, उसके प्रधान मुखिया होते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो प्रधान होते हैं, वह उसके प्रमुख होते हैं और जिला परिषद के स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं। 13वें वित्त आयोग में जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था से विकास ग्रामीण क्षेत्र में करना था, उसमें 60 परसेंट वित्तीय अधिकार पंचायत को थे, 20 परसेंट पंचायत समिति को थे और 20 प्रतिशत जिला परिषद को थे। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में दो स्तर को वित्तीय अधिकार से मुक्त कर दिया गया, उसको वित्तीय अधिकार से पंगु बना दिया गया।

अब मुखिया का चुनाव उसी तत्परता से होता है जिस तरह से पंचायत समिति के सदस्यों का होता है और जिला परिषद का चुनाव होता है। जिला परिषद और पंचायत समिति को कोई वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण उसके जनप्रतिनिधि हैं, वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आम जनता की नजरों में मुखिया से भी उनको विकास की उम्मीद है, पंचायत समिति के सदस्य से भी उम्मीद है, प्रमुख और जिला परिषद की इकाई से भी है।

देश में असंतुलन पैदा हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती व्यवस्था है, तीनों को संतुलित करने के लिए इस पर विचार करे। पहले पंचायतों में संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था थी। उसमें वेलबल सेक्शन के मुकदमे होते थे, जमीन-जायदाद के छोटे-मोटे झगड़े होते थे, परिवार के झगड़े होते थे उसका फैसला सरपंच कर दिया करते थे। वह समाप्त हो गया है। आज उसके कारण कचहरी में गरीबों के पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया है। मेरा आग्रह है कि पंचायत स्तर पर संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था करने पर सरकार विचार करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री लखन लाल साहू, श्रीमती रमा देवी, श्री हरीश मीणा, श्री राहुल कास्वां, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डॉ मनोज राजोरिया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री विष्णु दयाल राम और श्री भरत सिंह को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI BHEEMRAO B. PATIL (ZAHEERABAD): Thank you, Madam Speaker.

I would like to speak on behalf of employees of OFMK National Defence Workers Union Ordnance Factory, Medak.

Madam Speaker, recoveries are being made from the employees from July, 2017 onwards for those who have availed All India Tour LTC. That amount is higher than the minimum home taking salary which is prescribed under the Industrial Act. But, there are guidelines from OFB, MoD & DoPT to inquire into each case and submit the same for one-time relaxation to the Ministry of Defence on case to case basis.

Hence, the above act of recovery is not in line with the directives of the higher formations of OFMK. It is demoralizing the employees leading to industrial unrest.

Madam, manpower needs to be increased in OFMK in workmen cadre, since many of the employees are going on superannuation. OFMK is to reach the target of Rs. 3400 crore which is very difficult without sufficient manpower. About 600 people have lost their valuable land for the installation of prestigious Ordnance Factory, Medak. They have lost their livelihood also. Hence, appointment orders are required to be given immediately to around 151 land displaced persons. Local candidates should be considered for appointment in OFMK.

Therefore, it is humbly requested, through the Chair, to the hon. Minister of Defence to intervene in the matter and arrange to resolve the above-mentioned grievances of the employees of OFMK on priority basis.

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भीमराव बी पाटील द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): Thank you, Madam Speaker.

I wish to draw the urgent attention of this august House to the most alarming and a serious situation which has arisen across the country as a result of the use of formalin and other dangerous substances on fish meant for the human consumption.

The staple food of Kerala is rice and fish and a large consignment of fish is reaching the State from other parts of the country. Formalin is a hazardous chemical causing cancer and other fatal diseases.

Under the circumstances, I urge upon the Government to restrict the sale of formalin and take effective measures to prevent the use of hazardous chemicals in fish.

माननीय अध्यक्ष: श्री रवीन्द्र कुमार जेना, श्री राजीव सातव और श्री एन के प्रेमचन्द्रन को श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र के पूर्वी चम्पारण जिला अंतर्गत पताही प्रखंड का पदुमकेर गांव पौराणिक एवं ऐतिहासिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। लोगों की मान्यता के अनुसार प्राचीन काल में मिथिला क्षेत्र के ओइनवार वंश के राजा शिव सिंह ने पताही प्रखंड में घोड़दौर एवं इससे जुड़े हरवहिया और अन्नवहिया नामक पोखरों को खुदवाया था। एक-दो दशक पूर्व तक उक्त तीनों पोखर कमल एवं कुमुदनी पुष्पों से परिपूर्ण रहते थे जिसकी छटा काफी मनोहारी होती थी एवं आसपास के लोगों के बीच आकर्षण का केन्द्र रहता था। परंतु हाल के वर्षों में उक्त तीनों पोखर जलकुम्भियों से भरते जा रहे हैं, यहां के पेड़-पौधें नष्ट होते जा रहे हैं जो

पर्यावरण की दृष्टिकोण से चिंताजनक विषय है। इसके वृक्षों एवं बांधों को काट कर लोग अपने आधिपत्य में लेकर अतिक्रमण करते जा रहे हैं। जिसके कारण उक्त तीनों पोखरों की ऐतिहासिकता, प्राचीनता एवं पहचान समाप्त होने के कगार पर है।

अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उपरोक्त पताही प्रखंड अंतर्गत उपरोक्त तीनों पोखरों का एक कार्य योजना के तहत जीर्णोद्धार कराते हुए समग्र विकास के लिए अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट किया जाए।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्रीमती रमा देवी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): The Railways were the most convenient mode for long-distance and inter-city transport. This year, the airlines have overtaken in inter-city travel both in terms of revenues and numbers.

The other reality is that there is unprecedented rural-urban migration and rapid urbanization which is clogging Indian cities. Now our urban civic infrastructure is crumbling. Therefore, the Railways are more needed today for village to city transport than for inter-city transport.

Chevella, my Lok Sabha constituency, is half urban and half rural. Many trains which pass through the villages of this rural area do not stop there. They just zip pass. So the youths who are working in Hyderabad have to migrate to Hyderabad. The students who are studying in Hyderabad also have to migrate to Hyderabad. So, it is putting more pressure on urban infrastructure.

I would therefore request that the following trains should stop in my constituency in Nawandgi Railway Station near Tandur. They are Hubli

Express, Namded Express and Hyderabad-Gulbarga Express. Then I would request for a stoppage at Marapalli Station of Hyderabad-Bidar Intercity, Shirdi Express and Hyderabad-Bengaluru Express.

Madam, the Railways need to re-discover, re-orient and re-invent itself to meet the changing needs of the nation. It will help mitigate rural-urban migration.

HON. SPEAKER: Shri Harish Meena, Dr. Manoj Rajoria and Shri Rahul Kaswan are permitted to associate with the issue raised by Shri Konda Vishweshwar Reddy.

श्री राम टहल चौधरी (राँची): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत चांडिल में स्वर्णरेखा बहुद्वैतीय परियोजना है। मैं इस मुद्दे को कई बार सदन में उठा चुका हूँ। मैं आपके माध्यम से शून्य काल में सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूँ। मेरे गृह राज्य झारखंड में चांडिल में स्वर्णरेखा बहुद्वैतीय परियोजना 38 वर्ष पूर्व बनी थी। 38 साल पहले बनी इस परियोजना से गरीब विस्थापित परिवारों को कई कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। उनके घर और खेत बरसात के दिनों में पानी में डूब जाते हैं जो बहुत ही कष्टदायक है। हम 36 साल से उनके कष्टपूर्ण जीवन से पूरी तरह से वाकिफ हैं। वैसे तो विस्थापित परिवार के लिए कई कार्य किए गए हैं और शेष विस्थापितों के लिए पुनरीक्षित पुनर्वास नीति 2012 के अंतर्गत एक समयबद्ध कार्य योजना बनाई गई थी परंतु 36 साल में इस योजना से प्रभावित एवं विस्थापित परिवारों को पुनर्वास सुविधा एवं भूमि के मुआवजे के भुगतान से अभी तक वंचित किया हुआ है। उन्हें अभी तक विकास पुस्तिका भी जारी नहीं की गई है। गरीब ग्रामीण विस्थापित लोग भूमि के अधिग्रहण के कारण भुखमरी के शिकार हो गए हैं। इस परियोजना से प्रभावित लोगों को नियमानुसार रोजगार तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यंत खेदजनक है। विस्थापित परिवारों की आवाज को सुना नहीं जा रहा है। इस परियोजना के डैम का पानी बेकार पड़ा हुआ है, यहां लिफ्ट तकनीक से सिंचाई भी नहीं की जा रही है। इस

सिंचाई योजना के अंतर्गत बिजली बनाने की बात थी, खेतों में पानी पहुंचाने की बात थी, लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है।

मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि चांडिल की स्वर्णरेखा बहुद्वैतीय परियोजना में विस्थापित लोगों का प्राथमिकता के आधार पर पुनर्वास किया जाए, उन्हें विकास पुस्तिका उपलब्ध कराई जाए, भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान किया जाए, रोजगार प्रदान किया जाए और समुचित आवास उपलब्ध कराया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जितने भी विस्थापित परिवार के लोग हैं, अगर वे योग्यता हासिल करते हैं तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था भी होनी चाहिए ताकि भविष्य में भूमि अधिग्रहण में दिक्कत न हो। सरकार को विस्थापित परिवारों के बारे में सोचना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और डॉ कुलमणि सामल को श्री राम टहल चौधरी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, I am very grateful to you for giving me this opportunity to speak on a very important issue.

The entire Dalit community has expressed concern over the wrong message sent by the appointment of ...* as the Chairman of the National Green Tribunal. Since he is the judge who ruled against the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act, the Dalit community is demanding immediate removal of ...* from the Chairmanship of NGT.

HON. SPEAKER: You have given notice to speak about Dalit Christians.

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Yes, I am speaking on Dalit issue, Madam.

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष: किसी जज का नाम लेकर ऐसी बात कहना ठीक नहीं है।

SHRI KODIKUNNIL SURESH : ...* has been recently appointed as the Chairman of the National Green Tribunal. ... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: You did not speak about the Commission. You said something about ...* and something like that.

... (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Members belonging to SCs and STs from NDA personally met the hon. Home Minister, Shri Rajnath Singh. Shri Ram Vilas Paswan wrote a letter to Shri Rajnath Singh and his Party Chairman, his son, Shri Chirag Paswan wrote a letter to the Home Minister for immediate removal of ... *

In this regard, two judges bench in the Supreme Court was constituted. One among them was ...* . He has ruled against the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act. On 2nd April, there was a national ban against the Supreme Court judgement on the SCs and STs (Prevention of Atrocities) Act.

Lakhs and lakhs of Dalits are protesting against the judgement. In many parts of the country, thousands of Dalits were arrested and sent to jail. Twelve persons belonging to Scheduled Castes were killed due to police firing. The situation is very serious because of the judgement of ...* .

Retirement of ...* was in June, 2018. In the same month, ...* was appointed as the Chairman of the National Green Tribunal. What message is being given to the country by this?

* Not recorded

One thing is very clear. ... * His judgement against the SCs and STs is because of the pressure of the ... *

HON. SPEAKER: All these things will not go on record.

...(Interruptions) *

HON. SPEAKER: You speak on the subject for which you have given notice. I am sorry.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: No allegation like this should be made. This will not go on record.

... (Interruptions)*

HON. SPEAKER: You have given notice on a different subject.

... (Interruptions)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Throughout the country, the SCs and STs are being attacked by the people belonging to ... * All the accused against the atrocities on SCs and STs are from ...* (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shri Lakhan Lal Sahu may speak now. Nothing will go on record except what Shri Lakhan Lal Sahu says.

...(Interruptions) *

HON. SPEAKER: Shri M.B. Rajesh, Dr. P.K. Biju, Shri Mullappally Ramachandran and Shri Innocent are permitted to associate with the issue raised by Shri Kodikunnil Suresh.

* Not recorded

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): मैडम, छत्तीसगढ़ राज्य का बिलासपुर निर्वाचन क्षेत्र एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिलासपुर में बहुत से सार्वजनिक एवं शासकीय संस्थान हैं। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, रेलवे जोन, एसईसीएल का मुख्यालय, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे बहुत से व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थान वहां संचालित होते हैं। साथ ही, वहां भरनी-परसदा में, सकरी में और चकरभाठा में सैनिक छावनी है...(व्यवधान)

मैडम, जहां जवान अपने परिवार सहित रहते हैं और देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर देश की रक्षा करते हैं। ...(व्यवधान) मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पिछली बार जब आदरणीय मनोहर परिकर जी रक्षा मंत्री थे, उनका प्रवास बिलासपुर में हुआ था। उस समय वहां से एक मांग आई थी कि बिलासपुर में एक सैनिक स्कूल खोला जाए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे जवान, जो वहां से पूरे देश एवं राज्य की सेवा के लिए और राष्ट्र की रक्षा के लिए ट्रेनिंग लेकर काम करते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि उनके बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में एक सैनिक स्कूल बिलासपुर में खोलने की मैं मांग करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद, डॉ. कुलमणि सामल और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री लखन लाल साहू द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): अध्यक्ष महोदया, हमारे लोक सभा क्षेत्र में उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिविजन में कोच से एट तक एक शटल चलती है। उस रेलवे लाइन से सटा हुए एक गांव है, वहां 169सी अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है। उस ब्रिज के बनाने के कारण पूरे गांव में पानी भरा हुआ है और वहां से कोई निकासी नहीं हो पा रही है। जहां यह ब्रिज बनाया जा रहा है, वहां वर्तमान में पानी भरा हुआ है। गांव के लोगों का निकलना दुभर हो गया है। अंडर ब्रिज गलत साइड से बनाया

गया है। वहां स्वतंत्रता संग्राम देशराज की समाधि थी। वह ब्रिज उस समाधि के ऊपर से बनाया जा रहा है। किसानों की फसल को उससे नुकसान हो रहा है।

मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जो गलत अंडर ब्रिज बनाया जा रहा है, विशेष रूप से उसकी जांच की जाए। ठेकदार को जो सही साइड मिल रहा था, उस साइड से अगर रोड बनाई जाती तो गांवों से 300 मीटर पर एक नाला है जिससे गांव का सारा पानी उससे निकल सकता था। यह गलत साइड बनाने की वजह से गांवों को दिक्कत आ रही है, वहां के किसानों को दिक्कत आ रही है। इसकी जांच की जाए और किसी तरह से गांव से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए।
धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI ANANDRAO ADSUL (AMRAVATI): Madam Speaker, I would like to raise a very important matter of urgent public importance.

Madam, as per reliable sources it is learnt that the Government of India is coming under pressure to lobby Pakistan for the release of missing 54 Prisoners of War held in Pakistan since 1971 conflict. While 90,000 Pakistani troops were captured by the Indian Army at the end of the war and later released as part of the Simla Peace Agreement, 54 Indian soldiers, officers and some pilots are continued to be held by Pakistan till today.

The Government of India has not taken serious steps to get back these 54 Prisoners of War who are languishing in Pakistani jails since 1971. The Indian Government has never approached the International Court of Justice for repatriation of these 54 Prisoners of War by Pakistan. Pakistan had to return

these Indian prisoners according to Geneva Convention. However, the Indian Government had not taken up the matter according to Geneva Convention.

Madam, I would like to draw the attention of the Minister of External Affairs that this is a serious matter and the morale of the Indian Armed Forces is affected due to non-compliance of Geneva Convention by Pakistan since 1971. So, I would request the Minister of External Affairs to look into the matter seriously and raise the matter of these Prisoners of War at international forums to pressurize Pakistan to release 54 Prisoners of War without further delay.

HON. SPEAKER: Shri Shrirang Appa Barne, Shri Hemant Tukaram Godse, Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Arvind Sawant, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Rahul Shewale, Dr. Shrikant Eknath Shinde and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Anandrao Adsul.

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के महत्वपूर्ण उपनगरीय क्षेत्र गोरेगांव में वर्ष 2009 में डाकघर की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। नई बनाई गई थी, लेकिन वह बिल्डिंग वर्ष 2015 में ही जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पहुंच गई, जिस कारण इस बिल्डिंग को तोड़ दिया गया।

वर्तमान में गोरेगांव में असुविधाजनक स्थल पर किराए के भवन में डाक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसके कारण स्थानीय लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह भी अत्यधिक चिंता का विषय है कि आर.सी.सी. बिल्डिंग, जिसकी सामान्य लाईफ 50-60 वर्ष के आस-पास होती है, लेकिन वह मात्र 6 वर्ष के अंदर ही कैसे बेकार हो गई। अब स्थिति यह है कि खाली पड़ी भूमि पर असामाजिक तत्व कब्जा बना कर सरकारी भूमि का अतिक्रमण किए हुए हैं।

अध्यक्ष महोदया, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त बिल्डिंग के मात्र 6 वर्ष के अंदर ही जीर्ण-शीर्ण, बेकार होने की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के साथ-साथ डाक विभाग की खाली भूमि को असामाजिक तत्वों के अतिक्रमण से मुक्त करवा कर वहां पर भविष्य में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए, आधुनिक तकनीक युक्त नई बिल्डिंग का निर्माण शीघ्र करवा कर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष: डॉ. कुलमणि सामल, श्री शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री गोपाल शेटी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

SHRI THOTA NARASIMHAM (KAKINADA): Madam, thank you for giving me the opportunity. I would like to draw the attention to the proposed petrochemical complex project in Kakinada, Andhra Pradesh which got shelved due to the political reasons. What a pity! The capital cost of Kakinada petrochemical complex is Rs. 32,500 crore. GAIL and HPCL have evaluated the techno commercial feasibility and suggested a viable gas funding of Rs. 5,000 crore. The Central Government expects the new State Government of Andhra Pradesh, which is already reeling under the burden of revenue deficit of Rs. 20,000 crore every year to bear the full amount of viable gas funding. However, petroleum being a Central Subject, the Central Government should support the newly formed State of Andhra Pradesh in bearing the viable gas funding amount. Is it not true that the Central Government forced ONGC to buy 80 per cent holding in Gujarat State Petroleum Corporation, a sick unit, amounting to Rs. 25,000 crore in 2017?

Madam, the KG Basin is hub of future oil and gas of the country. Recently gas hydrates were found in KG Basin which can feed the country for 60 years in future without relying on imports. Almost Rs. 1,00,000 crore is being invested in this area by ONGC, GSPC and Reliance. With such a huge investment with heavy oil and gas flow, is it not a blunder to ignore the Kakinada Petrochemical complex, which is a promise made in the Andhra Pradesh Reorganization Act?

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिणी दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, आपने बहुत सेंसिटिव इश्यु पर बोलने का मौका दिया है। दिल्ली में तीन बच्चियों की मौत भूख के कारण हुई है और इसकी पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट में भी हुई है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की वह कांस्टीट्यूएन्सी है। फूड सिक्योरिटी बिल, 2015 के तहत छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, झारखंड में यदि आदिवासी क्षेत्रों में भोजन पहुंचाया जा सकता है, तो देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भोजन क्यों नहीं पहुंचाया जा सकता है? दिल्ली की सरकार केवल दोषारोपण करने के लिए बैठी है और गरीबों को मरवा रही है। इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट आफ सेल डिवाइस के माध्यम से करीब चार लाख राशन कार्ड दिल्ली में मिले थे, जिनके राशन लेने पर करीब 15 सौ करोड़ रुपयों के घोटाले का आरोप दिल्ली सरकार पर लगा था। दिल्ली में राशन की 2500 दुकानें हैं। इन दुकानों तक केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया राशन नहीं पहुंच पाता है और 19 लाख लोगों को सरकार कहती है कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से भोजन पहुंचाएंगे। ये केवल केंद्र सरकार पर दोषारोपण करते हैं और एक परिवार की तीन बच्चियां दो साल, चार साल और छह साल, जिनकी उम्र थी, उनकी भूख के कारण देश की राजधानी में मौत हो जाए, ऐसी संवेदनहीन सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

महोदया, ...* ने चारा ढोया था, यह सीएजी की रिपोर्ट में है। 1500 करोड़ रुपये का घोटाला सीएजी की रिपोर्ट में आया है। ... (व्यवधान)

12 58 hrs

At this stage, Shri Jai Prakash Narayan Yadav came and stood on the floor near the Table

अध्यक्ष महोदया, फूड एंड सिविल सप्लाय का जो राशन था, वह स्कूटरों के नम्बर पर ...* ने ढोया। ऐसी संवेदनहीन सरकार को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी अपने को बिधूड़ी जी द्वारा उठाए विषय से संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्री अजय मिश्रा टेनी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : ...* का विषय रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

12 59 hrs

At this stage Shri Jai Prakash Narayan Yadav went back to his seat.

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा (पश्चिमी दिल्ली): महोदया, कल हमें यह समाचार मिला। एक तरफ हम 'बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ' की बात करते हैं। हमें पता चला कि एक आठ साल की बच्ची, एक

* Not recorded

पांच साल की बच्ची और एक दो साल की बच्ची भूख के कारण मर गई। मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि इनके पेट में एक दाना भी नहीं मिला।

माननीय अध्यक्ष : आप एक वाक्य में अपने को इस विषय से संबद्ध कीजिए।

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा : महोदया, मैं सिर्फ एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। आज अखबार में एक समाचार और आया कि दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू पिछले साल से 41 परसेंट बढ़ गया है। दिल्ली में 1500 नए ठेके खुले हैं। गरीब लोग वहां अपना पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि दिल्ली की सरकार उन्हें बढ़ावा दे रही है। दिल्ली के उप मुख्य मंत्री का वह विधान सभा का क्षेत्र है और वहां तीन बच्चियों की मौत हो जाए। दिल्ली सरकार ने इस विषय में कोई बयान नहीं दिया है और मुख्य मंत्री चुप हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

13 00 hrs

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह जो मुद्दा उठाया गया है, वह एक संवेदनशील मुद्दा है। इन्होंने सही कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देश की राजधानी में भुखमरी से मृत्यु हो जाए, इसके लिए केन्द्र की सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है।

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपसे एसोसिएट करने के लिए कहा।

...(व्यवधान)

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली): महोदया, दिल्ली में तीन बच्चियों के मौत का जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इस मामले को मेरे साथियों ने इस सदन में उठाया। मैं उनसे एसोसिएट करता हूँ। लेकिन, मैं अभी-अभी उस परिवार से मिलकर आया हूँ। मैं आपके सामने संसद में एक सच्चाई बताने जा रहा हूँ।

दिल्ली सरकार के उपमुख्यमंत्री सरेश आम असत्य बोल रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि जिन तीन बच्चियों की मौत हुई है, वह परिवार दो दिन पहले ही उस क्षेत्र में मेहमान बनकर रहने आया था। लेकिन ऐसा नहीं है। उस परिवार के लोग वर्षों से मंडावली क्षेत्र में रह रहे हैं। इसमें राशन घोटाला सबसे बड़ी वजह है। उनको राशन तक नहीं मिलता था और मोहल्ला क्लिनिक में गलत इलाज होने के कारण उनकी मौत हुई है। इसलिए दिल्ली सरकार को बरखास्त करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : सर्वश्री भैंरो प्रसाद मिश्र, शरद त्रिपाठी, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्रीमती मिनाक्षी लेखी को श्री महेश गिरी द्वारा उठाये गये विषय से संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

13 02 hrs**SUBMISSION BY MEMBER**

Re: Circular of UGC treating respective Department of University as an unit resulting in denial of reservation in promotion to reserved category candidates

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं दो-तीन महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूँ।

हाल ही में मानव संसाधन मंत्रालय ने एक निर्णय लिया है, इस निर्णय से उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षक के पदों पर एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके तहत अब शिक्षण संस्थाओं में शिक्षक के पदों पर आरक्षण लागू करते समय पूरे विश्वविद्यालय को एक यूनिट मानकर वहाँ के विभिन्न विभागों को एक ही इकाई मानी जाएगी। यानी कुल मिलाकर, विश्वविद्यालय में जितने भी पद हैं, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को एक जगह लेकर रोस्टर सिस्टम किया जाता था। अब हाल में, एक संशोधन करके यूजीसी ने कहा है-

An amendment has been conveyed to all universities by UGC vide its Notice dated 5th March, 2018 wherein universities require to calculate reservation for SC and ST in teaching vacancies by treating each department, subject, as a unit for every level of teaching.

यदि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक-एक पोस्ट रहता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई भी हो, इसके लिए सिंगल पोस्ट रहता है, उसमें रिजर्वेशन आता ही नहीं। यदि उसमें रिजर्वेशन आएगा भी, तो वह रोस्टर सिस्टम के अनुसार 15 वर्षों के बाद आएगा।

इसमें एससी, एसटी और ओबीसी का बहुत बड़ा नुकसान है। विश्वविद्यालयों में ऐसा क्यों हो रहा है? क्या आप लोग रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं? क्या एससी, एसटी और ओबीसी को खत्म करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि अब नौकरियाँ कम की जा रही हैं। जितने भी पब्लिक

सेक्टर थे, उनमें भी नौकरियाँ गायब हो गई हैं। रेलवे की नौकरियों में भी कटौती हो गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार इसे रीस्टोर करे। पहले का जो जी.ओ. है, उसको रीस्टोर करना चाहिए।

आप जानते हैं कि हाल ही में, 'एससी/एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट' को डायलूट करने का जज़मेंट ...* ने दिया था...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप दोनों मुझे एक साथ क्यों ला रहे हैं?

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): मैडम, यह उसी से संबंधित है। इस तरह के जज़ को जीएसटी ट्रिब्यूनल का चेयरमैन बनाया गया है।

माननीय अध्यक्ष : ये दोनों मामले अलग-अलग हैं। यह आप भी जानते हैं। मैंने आपको एक मामला उठाने का मौका दिया।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अब आप बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : यह तो इशारा देता है कि आप खुद इसको सपोर्ट करते हैं। ...(व्यवधान)
जो-जो अन्याय और अत्याचार करेंगे, उनको आप प्रमोशन देंगे। जिस दिन वह रिटायर होगा, उसी दिन उसका अपॉइंटमेंट होगा। ...(व्यवधान)

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री अनन्तकुमार): अध्यक्ष जी, माननीय खड़गे साहब ने यहां एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। सरकार ने इसके बारे में बहुत गंभीरता से विचार कर के इसकी प्रक्रिया शुरू की है। यू.जी.सी. और बाकी यूनिवर्सिटीज में शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और ओ.बी.सी. को प्रमोशन देने का जो इश्यू है...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : सिर्फ प्रमोशन ही नहीं, बल्कि अपॉइंटमेंट ...(व्यवधान)

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : श्री राजीव सातव, डॉ. कुलमणि सामल, श्री धनंजय महाडीक, श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री आर. ध्रुवनारायण एवं श्री राजेश रंजन को श्री मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अनन्तकुमार : आप मेरी बात सुनिए। प्रमोशन और भर्ती, दोनों में जो रिजर्वेशन है, हमारे शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स और ओ.बी.सी. के बंधुओं के लिए उसको दूसरी तरह से करने का जो उच्चतम न्यायालय का आदेश है, इसकी जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को सरकार ने बंद कर दिया है।

इस पर पुनर्विचार करने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एस.एल.पी., स्पेशल लीव पेटिशन दर्ज की है। दूसरी बात, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज़ एक्ट पर माननीय प्रधान मंत्री जी कई बार कह चुके हैं। ...*(व्यवधान)* इसमें किंतु, परंतु, कॉमा या फुल स्टॉप का कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके ऊपर पुनर्विचार करने के लिए भी हमने एस.एल.पी. दर्ज की है। ...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष : वीरप्पा मोइली जी।

...*(व्यवधान)*

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Thank you, hon. Speaker, for giving me an opportunity to speak regarding stoppage of admission for the academic session 2018-19 in the Border Security Force Institute of Technology situated in Yelahanka in my constituency at Bangalore. It is run by the BSF Central Education Fund Society, as a welfare measure to the Force personnel. ... *(Interruptions)* In fact, it was started in the year 1992 when Shri S.B. Chavan was the Home Minister.... *(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष : ये बीच-बीच में जो चिल्लाकर बोल रहे हैं, उससे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आंखें भी काम करती हैं मेरी।

...(व्यवधान)

SHRI M. VEERAPPA MOILY : They are shifting one institution after another from Karnataka, more particularly from my constituency.... (*Interruptions*) Shri S.B. Chavan, who was the Home Minister, came there to inaugurate it. I was also Education Minister at that time from the State. In fact, the institution has trained more than 3000 students who are working across the world in various capacities in renowned companies such as Wipro, Infosys, TCS, Accenture, L&T, Seimens, Microsoft and so many other good institutions. They give training in Electrical & Electronics and other important professional and technical courses. The Institute has been recognised both by the AICTE and also by the Directorate of Technical Education (DTE). Before starting this Institute, viability study has been done. There is no reason just to wind up that institution which will affect the future of 100 employees who are in the age group of 40 to 50 years and also of hundreds of students, particularly children of BSF personnel. The idea is to provide this kind of a training to keep up the morale of the Border Security Force personnel. Also, there are increased casualties. Their family members are distressed as there is no one to guide and look after them.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Veerappa Moily ji, it should not be long.

... (*Interruptions*)

SHRI M. VEERAPPA MOILY : Madam, I am concluding. But the question is this. Where is the rationale behind shifting? ... (*Interruptions*) This is the second instance where they have shifted one more CRPF training institute at Taralu from the very same constituency. I do not know what the rationale behind it is. Of course, I have already written to the Home Minister. There is absolutely no response. Either shifting this institute or the educational institute will definitely demolish the morale of the Force personnel. ... (*Interruptions*)

SHRIMATI K. MARAGATHAM (KANCHEEPURAM): Madam Speaker, I wish to raise an important issue with regard to my Kancheepuram Parliamentary Constituency.

The only district in India with highest number of lakes is Kancheepuram. Palar river is the lifeline, as it supplies drinking water to almost all parts of Kancheepuram and for irrigation and it also supplies drinking water to some parts of Chennai.

Water is the main source for cultivation. It can be done by lift irrigation of water from bore-wells. This is possible only by harvesting rainwater.

Madam, I wish to say in this House that our hon. Leader Puratchi Thalaivi Amma was a founder in the entire country in harvesting rain water for agriculture. Puratchi Thalaivi Amma is the first Chief Minister in the country who passed a law that every building constructed in Tamil Nadu should have rain water harvesting and recharging provision.

As Kancheepuram has large number of lakes, it is very essential that steps are taken to store rain water, by which sub-soil recharging is possible and will benefit the nearby areas.

Hence, I request the Central Government and the hon. Water Resources Minister to allot sufficient funds for my Kancheepuram Parliament Constituency for deepening all the rivers and lakes for better water conservation in Kancheepuram district.

HON. SPEAKER: Dr. J. Jayavardhan is permitted to associate with the issue raised by Shrimati K. Maragatham.

श्री शेर सिंह गुबाया (फिरोजपुर): अध्यक्ष महोदया, आपने एक बहुत ही सैन्सिटिव इश्यू, जो एस.सी., एस.टी. के रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आजादी के बाद वर्ष 2002 के बाद जितनी भी कास्ट्स एस.सी., एस.टी. कैटेगरी में आई हैं, उनको तुरंत ही पूरे हक मिल जाते थे। बदकिस्मती से वर्ष 2002 के बाद जो कास्ट्स एस.सी., एस.टी. में आई हैं, 15 राज्यों में 94 कास्ट्स हैं और उनको स्टेट की असेम्बली और पार्लियामेंट के इलैक्शन में भाग लेने का पूरा अधिकार नहीं मिला है। क्योंकि इसके बाद जो पहले हुआ करता था, उसमें साथ ही साथ नोटिफिकेशन निकलता था और जो कास्ट आती थीं, उन्हें हक मिल जाता था। अभी 15 राज्यों में 43 सीट्स असेम्बली की हैं, लेकिन उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश को वर्ष 2012-13 में दो सीटों का हक मिल गया, हम इसके लिए खुश हैं, इसके विरोध में नहीं हैं। इसी तरह से सिक्किम की पांच सीटों का रिजर्वेशन का इसी सेशन में बिल आ रहा है। हम चाहते हैं कि जैसे आप सिक्किम को एस.सी., एस.टी. के रिजर्वेशन में इनक्लूड कर रहे हैं, ऐसे ही जो बाकी 14 राज्य हैं, उनको भी इसी सेशन में इसी बिल के साथ इनक्लूड किया जाए, ताकि वहां के एस.सी., एस.टी. लोगों को पूरा अधिकार मिल सके। पंचायतों और दूसरे इलैक्शंस में उन्हें हक मिला है। धन्यवाद।

श्री भरत सिंह (बलिया): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं अपने क्षेत्र बलिया का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाना चाहता हूँ। बलिया लोक सभा क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की घोषणा तत्कालीन मुख्य मंत्री,...* ने की थी।

माननीय अध्यक्ष : नाम मत लीजिए, केवल पूर्व मुख्य मंत्री कहिए।

श्री भरत सिंह : उससे बलिया के लोगों में बहुत आशा जगी थी कि पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे आएगा और बलिया का विकास होगा, उन्होंने उसको बीच में गाजीपुर तक रोक दिया। अभी 14 जुलाई प्रधान मंत्री जी ने आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का शिलान्यास किया। मैं कहना चाहता हूँ कि

* Not recorded

बलिया आजादी की लड़ाई में सबसे अग्रणी रहा। मंगल पांडे बलिया के थे, लोक नायक जय प्रकाश जी बलिया के थे। इतनी शहादत देने वाले बलिया का नाम आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि बलिया के विकास के लिए जरूरी है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लोक नायक जय प्रकाश जी की धरती से आगे तक बढ़ाया जाए। हमारा बलिया इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां कोई चिकित्सालय भी नहीं है। इसके बनने से वहां का विकास बहुत तेजी से होगा।

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Bharat Singh.

13 15 hrs**MATTERS UNDER RULE 377***

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज हम लंच ऑवर नहीं करेंगे, क्योंकि आज एक महत्वपूर्ण बिल हमको चर्चा के लिए लेना है। महिलाओं एवं बच्चों के बारे में हम बार-बार चिंता प्रकट करते हैं, उन्हीं से संबंधित बिल आज हम लेने वाले हैं। अभी हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। मगर उसके पहले मैं कहना चाहूंगी कि नियम 377 के अधीन जो मामले हैं, वे सभा-पटल पर रखे जाएंगे। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन आज अनुमति दी गई है तथा वे सभा-पटल पर रखने के इच्छुक हैं तो वे बीस मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा-पटल पर भेज दें। उन्हीं मामलों को माना जाएगा, जो सभा-पटल पर रखे गए हैं, बाकी सबको व्यपगत माना जाएगा।

* Treated as laid on the Table

(i) Regarding Improving railway connectivity in Jhalawar Parliamentary Constituency, Rajasthan

SHRI DUSHYANT SINGH (JHALAWAR-BARAN): My Parliamentary Constituency Jhalawar and Baran are promising upcoming industrial districts in Rajasthan, with a combined approximate working population of 2 million people.

With more than 7000 registered industrial units of textile and stone-cutting, this area needs direct connectivity with the main-line of the West Central Railway giving the area direct connectivity to the national capital region.

The nearest railway station is Ramganj-Mandi, about 45 minutes away and Kota, which is more than an hour away. This scenario is not allowing commerce and growth to flourish in my area.

Therefore, I request the Hon'ble Minister of Railways to take a due note of this urgent situation and provide the region with connectivity to West Central Railway Mainline and start a MEMU train service from Baran to Chhabra and further till Kota which will facilitate this area to get connected with the industrial corridors of Jaipur and New Delhi.

(ii) Need to start production and marketing of Ayurvedic medicine for Acute promyelocytic Leukemia

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया एक तरह का ब्लड कैंसर है। एक लाख में 13 लोगों को यह कैंसर होने की संभावना होती है। ऐलोपैथिक दवाओं से यह ठीक हो जाता है, नियंत्रित रहता है, परंतु पूरी तरह से खत्म नहीं होता और दोबारा हो जाता है।

उत्तराखंड के वैद्य डॉ. बालेन्दु प्रकाश ने 1997 से पहले ऐसे कैंसर के कई मरीजों का सफल इलाज किया था, जिसमें यह रोग पूरी तरह से ठीक हो गया था, लिहाजा सरकार ने उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट सौंपा। इस रिसर्च में सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एण्ड सिद्धा (सी.सी.आर.एस.) भी शामिल हुआ। 1997 में 11 ऐसे मरीजों पर पायलट स्टडी की गयी जिनके पैथोलॉजी जांचों से एम.पी.एम.एल. की पुष्टि हो गयी थी। 90 दिन के इलाज के बाद जिसमें इनको डॉ. बालेन्दु प्रकाश द्वारा बनायी गयी आयुर्वेदिक दवा दी गयी थी, न केवल यह पूरी तरह से ठीक हो गये, दोबारा इनको यह बीमारी नहीं हुई। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने इसको प्रमाणिक माना, इस दवा का यू.एस.-यूरोपियन पेटेंट भी करा लिया तथा इस रिसर्च के लिए 39 वर्ष की आयु में डॉ. बालेन्दु प्रकाश को पद्म श्री से सम्मानित किया। लेकिन इस दवा का व्यवसायिक निर्माण व व्यापक प्रयोग अभी तक प्रारंभ नहीं हो सका है।

मैं सरकार व आयुष मंत्रालय से ए.पी.एम.एल. की इस दवा के निर्माण व व्यवसायिक प्रयोग की मांग करता हूँ

(iii) Need to desilt all the dams and reservoirs in the country

श्रीमती रक्षाताई खाडसे (रावेर): हाल ही में बड़े बांध व जलाशय निर्माण करने हेतु पर्यावरण के नॉर्म्स के परमिशन, किसानों के खेत जमीन तथा अन्य योग्य भूमि अधिग्रहीत करने के लिए बड़ी मात्रा में निधि एवं समय सरकार को देना पड़ता है, जो कि आज के दौर में मुश्किल सा लगता है, इसलिए जो बनाए हुए बांध व जलाशय हैं उनके रख-रखाव व पूर्ण उपयोग हेतु अच्छी देखभाल जरूरी है जिससे इन बांध व जलाशय का निर्माण पूर्ण क्षमता से पानी भंडारण के लिए हो और उसका पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए सर्वेक्षण ये यह रिकॉर्ड हुआ है कि ज्यादातर बड़े बांध व जलाशयों में भारी मात्रा में गाद (सिल्ट) जमा हुई है जिसके चलते ऐसे बड़े बांध व जलाशयों में 50 से 60 प्रतिशत पानी भंडारण की क्षमता कम हुई है और ऐसे बांध में गाद जमा होने की प्रक्रिया लगातार बढ़ती ही जा रही है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के जलगांव जिले में स्थापित हतनूर बांध का गत वर्ष "मेरी" इंस्टिट्यूट, नासिक ने सर्वेक्षण किया था जिसकी रिपोर्ट वर्तमान में ही महाराष्ट्र सरकार को प्राप्त हुई है जिसमें हैरानी की बात यह है कि पिछले 11 साल में गाद में 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जिससे इस बांध में पानी के बदले 54 प्रतिशत गाद गत वर्ष तक रिकॉर्ड किया गया है। अगर इस गति से यह चलता रहा तो ऐसे बांध में पानी की भंडारण क्षमता घटती जाएगी और आने वाले कुछ वर्षों में इन बांध व जलाशय में पानी नहीं सिर्फ गाद होगा। यह स्थिति देश के सभी बड़े बांध व जलाशयों में नजर आ रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि ऐसे सभी बड़े बांध व जलाशय में जमा गाद को निकालने के लिए उचित तरीके/उपाय तथा टेक्नोलॉजिकल समाधान खोजने की जरूरत है और ऐसे सभी बांध जिनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा मात्रा में गाद जमा हुआ है इन सभी बांध व जलाशयों की गाद जल्द से जल्द साफ करने की कार्यवाही प्रारंभ करें जिससे देश के सभी निर्मित बांध व जलाशय को करीब-करीब उनकी निर्माण क्षमता में पानी भंडारण की व्यवस्था पुनः उपलब्ध हो और उस भंडारण पानी का आने वाले समय में उचित उपयोग किया जा सके।

**(iv) Need to address the problem of contaminated water in Sambhal
Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh**

श्री सत्यपाल सिंह (सम्भल): मैं सरकार का ध्यान अति महत्वपूर्ण विषय 'प्रदूषित पानी को पीने के लिए बाध्य होते लोगों' की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। सर्वविदित है कि जल ही जीवन है और जल का दूषित होना न केवल मानव जाति के लिए अपितु पशु-पक्षियों के लिए भी खतरे की घंटी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वाटर लेवल काफी नीचे है और जो पानी है वह भी दूषित है/जहरीला है क्योंकि दूषित जल के सेवन से कैंसर जैसे कई गंभीर रोग होते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र संभल (उत्तर प्रदेश) में सिंहपुर साहनी आदि क्षेत्र में प्रदूषित जल (पीने योग्य नहीं) है। जिसके पीने से उस क्षेत्र में लगभग हर परिवार में एक या इससे अधिक लोग कैंसर जैसे खतरनाक रोग के शिकार हो गये हैं। मैंने इस विषय को पूर्व में भी सदन में रखा था और इस क्षेत्र के पानी की जांच भी हुई थी। जांच के उपरांत काफी क्षेत्र का पानी पीने योग्य नहीं पाया गया। ऐसे दूषित पानी को पीने के लिए प्रतिबंधित भी किया गया (मना किया गया), परंतु तब से अब तक पानी प्रदूषित क्यों हो रहा है और इसे शुद्ध पीने योग्य पानी में बदलने के लिए कोई भी आवश्यक कदम नहीं उठाया गया है जिस कारण क्षेत्र में निराशा है और लोगों में गंभीर रोगों का भय भी व्याप्त है।

मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, जल संसाधन व पेयजल मंत्री और भारत सरकार से निवेदन करता हूँ कि प्रदूषित जल को पीने योग्य जल बनाने व कैंसर मुक्त बेल्ट बनाने व अत्याधुनिक संयंत्र स्थापित कर ऐसे क्षेत्रों में पीने योग्य पानी यथाशीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा करें जिससे कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आशा की नई किरण दिखे और लोगों में होने वाले गंभीर रोगों से मुक्ति भी मिले। मैं और क्षेत्रवासी सरकार के बहुत आभारी होंगे।

(v) Need to undertake renovation of approach roads to railway stations, construction of foot-over bridges and road over bridges on level crossing in Gopalganj district, Bihar

श्री जनक राम (गोपालगंज): गोपालगंज जिला (बिहार) में कई रेलवे स्टेशन हैं जैसे-जलालपुर, सिपाया, सासामुसा, नरकटिया, थावे जंक्शन, गोपालगंज, माँझा, शेर, सिधवालिया, टेकनवास इत्यादि स्टेशन तथा हॉल्ट हैं, जहाँ अभी भी फुट ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज, सम्पर्क पथ की समस्या है। स्टेशनों से गुजरने वाले रेलवे पथ की बहुत ही बुरी एवं जर्जर हालत है। पूर्ववर्ती सरकार में कई वर्षों ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, सम्पर्क पथ का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है, जिससे आम जनता एवं स्कूली बच्चों को रेलवे पथ पार कर आने-जाने में काफी परेशानी हो रही है। आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जान-माल के नुकसान का खतरा बना रहता है। इस समस्या को लेकर जनता में काफी आक्रोश है तथा रोड का जीर्णोद्धार एवं रेलवे सम्पर्क पथ नहीं बनने से समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से विनती करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के थावे जंक्शन, सासामुसा, सिपाया, जलालपुर, हथुआ, माँझा, बरौली, सिधवालिया, टेकनवास रेलवे स्टेशनों पर रेलवे स्टेशन सम्पर्क पथों का जीर्णोद्धार एवं फुट ओवर ब्रिज एवं विभिन्न रेलवे क्रॉसिंगों पर यातायात के सुगम आवागमन के लिए वहाँ रोड ओवर ब्रिज का निर्माण शीघ्र कराया जाए, ऐसी मेरी केंद्र सरकार से गुजारिश एवं मांग है।

(vi) Need to set up a Committee of Experts to study use of Formaldehyde for preservation of fish

ADV. NARENDRA KESHAV SAWAIKAR (SOUTH GOA): I would like to draw the attention of the Government towards the use of Formaldehyde to extend the shelf life of fish from production to marketing stage.

Fish is an important source of human protein and is staple diet of the people living across the coastal areas of our nation.

Considering the serious impact of use of formaldehyde, many State Governments viz. Assam, Nagaland, Goa etc. have recently initiated action in the matter by imposing ban on import of fish.

The use of formaldehyde has caused fear and anxiety in the minds of the people at large, in spite of the steps taken by the respective Governments. I would, therefore, request the Central Government to set up a Committee of Experts to conduct a study into the use of formaldehyde and spread awareness about its impact on public health.

(vii) Regarding irregularities in post office situated in Pipargawan village in Bidhnu Development block in Akbarpur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): मैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत डाक विभाग के अधिकारी द्वारा अनैतिक रूप से किए गए कथित आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले को सामने लाना चाहता हूँ जिसके कारण उक्त क्षेत्र के लोगों का आर्थिक नुकसान हुआ है।

मेरे लोक सभा क्षेत्र के अंतर्गत जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड बिधनू के ग्राम पिपरगवां के डाक विभाग द्वारा शाखा पिपरगवां के नाम से संचालित था जिसकी मुख्य शाखा नौबस्ता कानपुर नगर में थी। ग्राम पिपरगवा एवं ग्राम बघारा एवं अन्य ग्रामों के लोगों के द्वारा उक्त डाकघर में पैसा जमा किया जाता था। डाकघर पिपरगवां एवं ग्राम बघारा के खाताधारकों का लाखों रुपया फर्जी तरीके से निकाल कर हड़प कर लिया गया एवं कुछ खाताधारकों की पासबुकें तक निर्गत नहीं की गयी एवं फर्जी पासबुकों के द्वारा खाताधारकों को आश्वस्त करता रहा कि आपका पैसा खाते में जमा हो गया है जबकि उस अधिकारी द्वारा कोई भी पैसा विभागीय खातों में जमा नहीं कराया गया। उक्त के संबंध में जानकारी होने पर खाताधारकों द्वारा वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर को शिकायती पत्र प्रेषित किया गया एवं मेरे संज्ञान में आने पर मैं समस्त पीड़ितों के साथ स्वयं मुख्य डाक अधीक्षक से मुलाकात कर खाताधारकों का पैसा वापस दिलाये जाने हेतु वार्ता की एवं पत्र प्रेषित किया एवं मेरे द्वारा पुनः पत्राचार के उपरांत तक उक्त के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है जिसके कारण खाताधारकों को अपने पैसे डूबते नजर आ रहे हैं जो कि कतई न्यायोचित नहीं है।

अतः उक्त ग्रामों के खाताधारकों का जमा पैसा विभाग द्वारा वापस कराये जाने एवं दोषी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को आवश्यक आदेश निर्गत करने की कृपा करें जिससे खाताधारकों का पैसा वापस मिल सके।

(viii) Need to provide adequate compensation to villagers relocated from Sanjay National Park in Sidhi Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh.

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी के कुसुमी अंतर्गत ग्राम पंचायत मझिगवा, भदौरा व रुदा जो संजय राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा विस्थापित है, इनके विस्थापन की प्रक्रिया की शुरुआत 21 फरवरी, 2008 को तत्कालीन केंद्र सरकार के बाघ संरक्षण अधिनियम के तहत जारी आदेश से हुई एवं 13 अप्रैल, 2017 को विस्थापन की घोषणा हुई। किंतु उचित मुआवजा राशि न मिलने के कारण ग्रामीणजन विस्थापन होने को तैयार नहीं है, उनका कहना है कि वर्षों से उन्होंने इस गांव में बहुत कुछ बनाया है, पेड़, वृक्ष, घर आदि परंतु इस राशि से कहीं जमीन भी नहीं खरीदी जा सकती। शासन की कुछ योजनाओं का लाभ तो ग्रामवासियों को मिल रहा है परन्तु केंद्र सरकार की दो महत्वपूर्ण योजनाएं प्रधानमंत्री आवास व सौभाग्य योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ये तीनों पंचायतें आज भी विद्युत विहीन हैं और प्रधानमंत्री आवास तो गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है किंतु इन योजनाओं से विस्थापित पंचायतों के निवासी वंचित हैं।

मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि उक्त विस्थापित ग्राम पंचायतों में पुनः मूल्यांकन कराकर उचित मुआवजा राशि दिलाने की कृपा करें।

(ix) Need to fill up vacant posts in Government Offices and Departments and also to regularise the services of contractual/temporary employees working in Government sector

श्री हरीश मीना (दौसा): मैं सरकार का ध्यान एक जरूरी मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सरकारी क्षेत्र की नौकरियों के निजीकरण, अस्थाईकरण आदि से देश के युवाओं के बीच गंभीर निराशा है। सरकारी नौकरियों में लगातार कटौती हो रही है और पुराने खाली पड़े पदों को भरा नहीं जा रहा है। निजी क्षेत्र का तेजी से विस्तार हो रहा है। यह सच है कि निजी क्षेत्र के आने से कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना का विकास हुआ है और उनकी कार्य क्षमता बढ़ी है लेकिन निजी क्षेत्र के अनियंत्रित विस्तार से भारतीय संविधान सम्मत सामाजिक न्याय के विचार को बहुत नुकसान हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इससे देश के वंचित तबकों में निराशा और प्रतिरोध का भाव पनप रहा है। पिछलों दिनों सरकार ने अत्यंत उच्च पदों यानि संयुक्त सचिव जैसे बेहद अहम पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन निकाला है। सबके दिमाग में यही सवाल है कि सिविल सेवा से निकले एक से बढ़कर एक अधिकारियों के होते इस सीधी भर्ती की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निजीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है। यह निजीकरण सिर्फ पूंजीपतियों के लिए लाभदायक हो सकता है क्योंकि इसकी मदद से उन्हें सस्ता श्रम मिल जाता है और उनका मुनाफा बेहिसाब बढ़ता जाता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए इस तरह नौकरियों का अंधाधुंध निजीकरण उचित नहीं जान पड़ता है।

मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस ओर ध्यान दे और सामाजिक न्याय व संविधान की रक्षा हेतु समुचित उपाय कर खाली पदों पर शीघ्र नियुक्तियां की जायें तथा सरकारी महकमों में संविदा या अस्थाई तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन व अन्य सुविधायें मुहैया करायी जायें।

**(x) Regarding irregularities in operation of petrol pumps in
Thane district, Maharashtra**

श्री गोपाल शेटी (मुम्बई उत्तर): देश में, विशेषतः महाराष्ट्र राज्य, के ठाणे जिले में विभिन्न तेल कम्पनियों, विशेषकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, के ऐसे पेट्रोल पम्पों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिन्हें तेल कम्पनी से एन.ओ.सी. लिए बगैर बेच दिया गया अथवा अवैध हस्तांतरण कर दिया गया तथा जिन्हें लीज पर लिया गया था तथा लीज की अवधि समाप्त होने के बाद भी उस भूमि पर पेट्रोल पम्प अवैध रूप से संचालित है और लीज की अवधि के दौरान भूमि मालिक को भूमि का किराया भी नहीं दिया गया।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस तरह के प्रकरणों की उच्च स्तरीय जाँच करवाकर एक ऐसी नीति तैयार करे कि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति पर रोक लग सके।

(xi) Need to start skill development and entrepreneurship programme in Uttarakhand based on the potential of natural resources of the State

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): उत्तराखण्ड सामरिक रूप से महत्वपूर्ण प्रदेश है जो दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है। प्रतिदिन प्राकृतिक आपदाओं से जूझता यह संवेदनशील नवोदित प्रदेश भारी पलायन की मार झेल रहा है। प्रदेश में 67 प्रतिशत भू-भाग वनों से घिरा होने के कारण स्थिति ज्यादा दुष्कर हो गयी है। इस पलायन से हजारों गाँव वीरान हो गए हैं। जहां एक ओर यह पलायन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है वहीं दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक विषमता को जन्म दे रहा है। प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी इसमें आग में घी का काम कर रही है। दुर्भाग्य से केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न कौशल विकास योजनाएं इन क्षेत्रों में सफल नहीं हो पा रही हैं। पर्वतीय क्षेत्र की पारिस्थितिकीय, भौतिक और मानव संसाधन के अनुरूप कार्यक्रम चलाने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि उत्तराखंड सहित समस्त हिमालयी राज्यों में वन आधारित उद्योग, जड़ी-बूटी उत्पादन, फलोरीकल्चर, मशरूम उत्पादन, आर्गेनिक खेती, फल उत्पादन, सब्जी उत्पादन, जैव प्रौद्योगिकी, ईको टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म, गैर-परम्परागत ऊर्जा उत्पादन, आर्गेनिक दुग्ध उत्पादन, शहद उत्पादन आदि के क्षेत्रों में कौशल विकास उद्यम कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन क्षेत्रों में सरकार कार्य करे तो सामरिक सुरक्षा होने के साथ-साथ पलायन की समस्या से निजात मिलेगी तथा संपूर्ण हिमालय क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक उत्थान हो सकेगा।

**(xii) Need to expedite four-laning of Jammu-Akhnoor-Poonch
National Highway**

श्री जुगल किशोर (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान अपनी लोक सभा क्षेत्र जम्मू में राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर ले जाना चाहता हूँ, जो जम्मू से पुँछ तक है। इस राजमार्ग का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है यह राजमार्ग जम्मू-कश्मीर का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्योंकि यह राजमार्ग भारत-पाकिस्तान सीमा के साथ लगते हैं और तीन जिलों से होकर गुजरता है और पुँछ तक पहुँचता है। सीमा सुरक्षा बल एवं सेना भी इस पर पूर्णतया निर्भर है, क्योंकि उनकी सभी गतिविधियाँ और आवागमन इसी राजमार्ग से होता है, जिसे फोर लेन करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषित पैकेज में 5100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा गया है।

जम्मू-अखनूर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का काम एन.एच.आई.डी.सी.एल. द्वारा इस सड़क को बनाने के लिए टेंडर दे दिया गया है परन्तु इस राष्ट्रीय राजमार्ग का काम काफी धीमी गति से चल रहा है।

यह राष्ट्रीय राजमार्ग अखनूर, सुंदरबनी, नौशेरा, राजौरी और पुँछ क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए भी बहुत आवश्यक है यहाँ पर यातायात अधिक होने के कारण आकस्मिक दुर्घटनाएं होती रहती हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग (चार लेन) के कार्य को जल्द पूरा करने की कृपा करें, यह जम्मू-कश्मीर की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।

(xiii) Need to impart knowledge of Constitution of India to students in schools and higher educational institutions

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): हम भारत के लोग भारत को एक 'सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य' बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को "सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता" सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर संविधान सभा में 26 नवंबर, 1949 ई. को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। हमारे संविधान में नागरिकों के लिए मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, समता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, सांविधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य की नीति आदि का अधिकार सुरक्षित है। हम भारत के लोगों का संविधान के प्रति विश्वास व निष्ठा है। भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की जानकारी अति आवश्यक है।

अतः मैं सरकार से यह माँग करता हूँ कि देश के सभी विद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थानों में संविधान पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाए। जिससे प्रत्येक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की विस्तृत जानकारी रख सके तथा उसका अनुपालन कर सके एवं राष्ट्र की एकता-अखण्डता बनाये रखने में सहयोग प्रदान कर सके।

(xiv) Need to set up a Planetarium in Meerut, Uttar Pradesh

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): मेरठ एक पौराणिक तथा ऐतिहासिक नगर होने के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा तथा अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु है। केंद्र सरकार ने मेरठ का चयन स्मार्ट सिटी के विकास हेतु भी किया है। इसी क्रम में मेरठ महानगर में विद्यार्थियों में अनन्त ब्रह्माण्ड के प्रति जागरूकता तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु तारामण्डल (प्लेनेटोरियम) की स्थापना की आवश्यकता है। तारामण्डल की स्थापना से सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश के छात्र-छात्राओं एवं जिज्ञासुओं को लाभ होगा तथा मेरठ में पर्यटन का भी विकास होगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि मेरठ महानगर में तारामण्डल की स्थापना हेतु उचित कदम उठाए जाएं।

**(xv) Need to grant the status of state government employee to
Aanganwadi workers**

श्री मोहम्मद असरारुल हक (किशनगंज): मैं सरकार का ध्यान आंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं की खराब आर्थिक हालत की ओर दिलाना चाहता हूँ। आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारु कार्यचालन के लिए इनकी नियुक्ति की गई थी। इनके मानदेय में राज्य सरकार ने मात्र रुपए 750/- की मामूली वृद्धि की है। वर्तमान में सेविका को रुपए 3750/- तथा सहायिका को रुपए 1750/- मानदेय दिया जाता है। यह वर्ष भर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती हैं तथा अपराह्न 3.00 बजे के बाद घर-घर घूमकर जच्चा-बच्चा तथा बालिकाओं के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी भी निभाती हैं। स्वास्थ्य केंद्रों में पोलियों की दवा पिलाने तथा माताओं के टीकाकरण में सहायता के साथ ही सहायक बी.एल.ओ. के रूप में नियुक्त करके इनसे अतिरिक्त काम भी कराया जाता है। राज्य सरकार के अन्य विभागों द्वारा भी इनसे काम लिया जाता है। इसके मद्देनजर सरकार से मेरा अनुरोध है कि इन सेविकाओं/सहायिकाओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा और उचित मानदेय दिया जाए।

**(xvi) Regarding Final notification on Western Ghats relating to
Ecologically Sensitive areas**

SHRI ANTO ANTONY (PATHANAMTHITTA): I request the Government to kindly issue the final notification on the Western Ghats. People in Kerala are concerned about the grave implications of the Expert Panel reports on Western Ghats headed by Prof. Madhav Gadgil and Dr. K. Kasturirangan. Both reports ignored the ground realities in Kerala while relying on remote sensing techniques. As a result, plantations and agricultural lands were identified as Ecologically Sensitive Areas (ESAs). Today densely populated 123 villages in Kerala are identified as ESAs, and the inhabitants in these villages are deprived of their right of development. Having understood the gravity of the issue, the Government of Kerala conducted a serious study and submitted its detailed report to the Government of India. Therefore, I request the Government to issue the final notification on the Western Ghats by considering the report submitted by the Government of Kerala in this regard.

(xvii) Need to allocate funds to Kerala for construction of sea walls along the coastline

SHRI MULLAPPALLY RAMACHANDRAN (VADAKARA): The State of Kerala has a long coastline of 580 Kms and lakhs of fishermen who live in indigent circumstances inhabit the coastal areas. Kerala had an unprecedented heavy monsoon this year. The State has witnessed sea erosion all along the coast causing extensive damages. The traditional method of protecting the shore from heavy sea erosion was by constructing sea walls. The people along the coast line are living under threat of further erosion. Under the circumstances, I request the Union Government to allocate more funds to the state for constructing sea walls along the coastline.

**(xviii) Need to set up a Kendriya Vidyalaya at Kumbakonam
in Tamil Nadu**

SHRI R.K. BHARATHI MOHAN (MAYILADUTHURAI): In my Mayiladuthurai Parliamentary Constituency at the moment, there is no Kendriya Vidyalaya School. Mayiladuthurai constituency comprises the assembly segments of Sirkazhi, Mayiladuthurai, Poompuhar, Thiruvaidaimarudur, Kumbakonam and Papanasam and several small towns with a population of over 25 Lakhs. The people of this region are mostly agriculturists and they need a Kendriya Vidyalaya to provide quality CBSE education at low cost.

Though there are several Private CBSE schools in this region, they are beyond the reach of the poor agriculturists and other working community. The District administration has already identified suitable land for the establishment of Kendriya Vidyalaya in Kumbakonam.

Therefore, I urge the Government to provide top priority to establish a Kendriya Vidyalaya school at Kumbakonam in Tamil Nadu.

(xix) Need to provide stoppage of Antyodaya Express and Rameshwaram - Bhubaneswar Express at Chidambaram railway station

SHRI M. CHANDRAKASI (CHIDAMBARAM): The newly introduced Tambaram — Tirunelveli Antyodaya express (16191/16192) and the Rameshwaram — Bhubaneswar weekly Express do not have a stoppage at Chidambaram. It is really unfortunate that services of these two important train are being denied to the people of Chidambaram.

Chidambaram is a Municipal town having world famous Nataraja Temple known for its architecture. The mangroves at Pichavaram, an important natural wetland, is barely few kilometers from Chidambaram. The Annamalai University which is one of the oldest Universities in the country is also located at Chidambaram. Besides there are lots of Petrochemical companies in the SIPCOT area in between Chidambaram and Cuddalore.

Therefore Chidambaram assumes importance and there is an urgent need for the stoppage of the Antyodaya Express (16191/16192) and Rameshwaram — Bhubaneswar Express (18495/18496) at Chidambaram railway station.

Hence I urge the Government to take immediate steps to provide stoppage for Antyodaya Express (16191/16192) and Rameshwaram - Bhubaneswar Express (18495/18496) at Chidambaram railway station.

(xx) Regarding non-payment of insurance amount to farmers of Odisha by a private insurance company

SHRI NAGENDRA KUMAR PRADHAN (SAMBALPUR): The Government of India have declared Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for the welfare of farmers through which many farmers will be benefitted. The scheme was unveiled by Prime Minister on 13.012016. After declaration of this scheme, the farmers of my districts i.e. Sambalpur, Angul and Deogarh along with ten districts of Odisha were registered under this scheme by Tata AIG Company. In the year 2017 thousands of farmers (small, marginal and bhagchasi farmers) insured their crop with the above company. But in the year 2017, in Kharif cultivation most of the farmers faced natural calamities such as attack of Chokda insect leading to loss of crores of rupees. Tata AIG agreed to pay the farmers of 92 Gram Panchayats and the rest of 30 Gram Panchayats of Sambalpur was left out and same is the case with other ten districts. One year has already passed and not a single penny has been received from Tata AIG company. There is huge discontentment among the farmers of the State and Sambalpur district in particular. Road blockade, demonstration before Collector have become the order of the day. I would like to request Hon'ble Agriculture and Finance Ministers to sort out the issue immediately so that people get their insured amount.

(xxi) Need to set up fast track courts for early disposal of corruption cases

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): एक सर्वे के मुताबिक सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए 10 में 7 लोगों को रिश्वत देनी पड़ती है। दुनियाभर में करप्शन पर नजर रखने वाली संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्वत के मामले में भारत 16 एशियाई देशों में सबसे टॉप पर है। विभिन्न सर्वे से आये नतीजों के अनुसार 90 करोड़ लोगों को पिछले साल कम से कम एक बार सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देनी पड़ी है। यहाँ तक कि लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए भी घूसखोरी के मामले सामने आते रहे हैं।

जहां तक रिश्वत लेने वाले सरकारी अधिकारियों का सवाल है तो सर्वे के अनुसार घूस मांगने के मामले में पुलिस सबसे ऊपर है और इस घूसखोरी के कारण समाज का हर वर्ग परेशान रहता है।

जब कोई सरकारी कर्मचारी घूसखोरी के मामले में पकड़ा जाता है तो उस पर केस चलता है जो कि कई मामलों में कर्मचारी के रिटायर होने के बाद भी चलता है और कई मामलों में तो कर्मचारी की मृत्यु तक हो जाती है फिर भी केस चलता रहता है।

मैं इस संबंध में सरकार से अनुरोध करता हूँ कि सरकार इन मामलों को निपटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाये ताकि इन केसों की जल्दी से जल्दी सुनवाई हो सके और दोषी को उचित दंड मिल सके।

(xxii) Need to implement Land Acquisition Act, 2013 in letter and spirit in Jharkhand

श्री विजय कुमार हांसदाक (राजमहल): झारखण्ड सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 में कई ऐसे प्रावधान जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जो जनजातीय लोगों के अधिकारों का हनन कर रहा है, जिसमें पंचायत की 70 प्रतिशत की सहमति के स्थान पर केवल परामर्श लिये जाने, न्यायालय में जाने की मनाही है एवं सामाजिक मूल्यांकन अध्ययन के द्वारा इस कानून का क्या प्रभाव रहा है, इसका पता नहीं लगाया गया है। ऐसा कानून केवल झारखण्ड में है और किसी राज्य में नहीं है जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 केंद्र सरकार द्वारा लागू है एवं भूमि अधिग्रहण अधिनियम का पालन संविधान की 5वीं अनुसूची के आधार पर होता है। झारखंड के राज्यपाल के माध्यम से इस कानून में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। झारखंड में पी.पी.ई.एस.ए. कानून को पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। झारखंड में उक्त अधिनियम को मनमाने ढंग से लागू किया गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम एवं वन अधिनियमों से झारखंड के करोड़ों आदिवासी-मूलवासी का गला घोटने एवं मुट्ठी भर पूंजीपतियों को और धनवान बनाने का रास्ता बनाने के लिए लाया गया है जिसके कारण झारखंड राज्य के आदिवासी-मूलवासी काफी आक्रोशित एवं सशंकित हैं। अनेकों योजनाओं के नाम पर आदिवासी-मूलवासियों की जमीन को अधिग्रहित कर उन्हें भूमिहीन किया जा रहा है, जिससे आदिवासी-मूलवासी विनाश की ओर जा रहे हैं। कई योजनाओं के क्रियान्वयन से उन्हें बड़े पैमाने पर विस्थापित कर उन्हें रोजगार विहीन किया जा रहा है। झारखंड सरकार की नीति से लगता है कि पूरी तरह से आदिवासियों को तबाह करने के लिए बनाई जा रही है एवं झारखंड सरकार का उद्देश्य केंद्र सरकार के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को अप्रभावी करना है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि भूमि अधिग्रहीत अधिनियम के मूल प्रावधानों के साथ किसी प्रकार की छेड़-छाड़ न होने दे जिससे देश के आदिवासी-मूलवासी अपना आर्थिक एवं सामाजिक विकास निःसंकोच ढंग से कर सकें।

13 16 hrs

**TRAFFICKING OF PERSONS (PREVENTION, PROTECTION AND
REHABILITATION) BILL, 2018**

HON. SPEAKER: Now, Item No.15, the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.

Hon. Minister.

... (*Interruptions*)

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam, I beg to move:

“That the Bill to prevent trafficking of persons, especially women and children and to provide care, protection and rehabilitation to the victims of trafficking, to prosecute offenders and to create a legal, economic and social environment for the victims and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

HON. SPEAKER: Do you want to say something on this Bill?

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Yes.

This Bill attempts to create a legal, economic and social environment for victims and for matters connected therewith or incidental there. Madam Speaker, today as I stand here for introducing this Bill, I speak to you and to Parliament on behalf of the vulnerable women and children of India.

The Government of India and all of us have always firmly upheld that children are the soul of India because in them we see the culmination of our

dreams and hopes as a nation. We have defended and empowered the decisive role that women play in the growth story of India.

How then can we sit silent and let women and children be bought and sold like slaves? When an 11-year old Tara is trafficked from her village, sold into bonded labour, beaten and burnt by her owner, how do we save her? When she is sold for marriage to a 45-year old man and raped every day for months, how do we save her? We have no institutions and no processes to do so. If today we do not pass this Bill, we are choosing to deny Tara and all the millions like her the fundamental right to life and liberty. The Government's statistics show that 19,223 women and children were trafficked in 2016 as against 15,448 in 2015. Moreover, 1,11,569 children have been reported missing in the year 2016. They are presumed to have been trafficked or abducted for exploitative purposes. These figures are only reported because the reality is actually and probably much worse. The crime of trafficking is hugely organized and largely invisible. We are living in this awful reality where price tags are put on human lives; our children's future is put into jeopardy because our laws and Bills fail them.

I am asked the question, 'Why do we need the law?' The answer is simple. While the current response mechanisms focus on criminalization of offences relating to trafficking or prosecution of offenders, they fail to target the backbone of this organized crime.

Section 370 of IPC only defines and penalizes the offence of trafficking of persons, and the Immoral Traffic Prevention Act (ITPA), 1956

only deals with sexual exploitation. The new Bill addresses these gaps.

I evoke your wisdom and compassion towards ending this grave and shameful crime of trafficking. I urge upon you all to come together to pass this Bill.

Now, I will explain why this Bill is the first step towards a comprehensive solution to trafficking in persons in India, that goes beyond just its criminalization.

This Bill has been prepared after extensive consultations with a variety of stakeholders. It has been placed on the Ministry's website for comments for months. It has received over 300 suggestions from public and civil society. Regional consultations have been held in all the main cities. Over 60 NGOs, Government Departments and Police have taken part in it. We have had extensive discussions with the Members of Parliament and have benefited from their advice.

It has comprehensive and holistic provisions provided in one place – it covers prevention of trafficking; protection of victims, witnesses and complainants; and also the comprehensive rehabilitation of victims. This will only strengthen, confirm and assert our commitment to the Constitution of India, which under Article 23 expressly prohibits human trafficking.

Starting from the perspective of the victim of trafficking, this Bill is a great boon. This is the first time that the spirit of the Constitution has been captured in the Bill, as it makes relief and rehabilitation of the rescued person a matter

of right. So far it has simply been a matter of welfare. How good we want it to be.

Transformation from welfare perspective to a rights-based perspective is a blessing and support to victims. The Preamble starts with the phrase - to create a legal environment for the victims. Several Sections have been incorporated to ensure the rights of victims. Now, the victims of trafficking, who usually suffer in silence have an opportunity to be heard.

From the perspective of investigation, the major challenge today is the issue of trans-border jurisdiction and related investigation. Human trafficking is a borderless crime, but jurisdictional issues come in the way of investigation. The Bill provides for a National Bureau to effectively address this aspect. This is the need of the hour and is welcomed by law enforcement agencies in the country. Special crimes need special attention. Hence the setting up of these special Anti-Human Trafficking Units (AHTU) all over the country, as is mandated in the Bill, is an important step.

The method of trans-border cooperation, beyond the States and even beyond the international border has been, for the first time, identified and addressed. A vast area of confusion has been made clear and lucid.

The system of nodal officers and nodal police officers in States, which started in 2005 under the aegis of the National Human Rights Commission (NHRC), has seen ups and downs. This nodal system is very important to ensure that the convergence of all concerned happens to prevent and combat

human trafficking. The Bill brings a legal status to the nodal system, providing a single window approach to the response system.

As against the existing provisions of the Immoral Traffic (Prevention) Act, this Bill allows police officers to undertake rescue, as and when they receive information. There is no need for any notified police officer or rushing to the magistrate for prior approval. This provision empowers the police station and the Anti-Human Trafficking Units (AHTU) to undertake swift action as and when information is received and rescue the person at the earliest to avoid further exploitation.

The Anti-Human Trafficking Units set up in the country, starting with the first nine set up in 2007 in the MHA-UN joint project and replicated more than 300 districts, are being legitimized and institutionalized. The setting up of these special units is indeed an important step.

Prosecution of offenders starting from recruiters, harbourers, transporters, financiers, abusers, exploiters, conspirators, abettors etc. has been a daunting task for the prosecutors in the country. This Bill makes a strong positive effort in facilitating prosecution of the offenders of this organized crime. The presumption in respect of offences against children, women and physically or mentally challenged persons gives the prosecution adequate scope to ensure easy, fast and efficient disposal of crimes. This will certainly bring in certainty and celerity in the delivery of justice.

The Bill also provides for freezing and confiscating illicit assets, born out of trafficking crimes. This is a landmark addition to the trafficking law as neither

Section 370 of Indian Penal Code (IPC) nor the Immoral Traffic (Prevention) Act (ITPA) has any such provision. It is well known that the traffickers make huge profits out of the sale and purchase of human beings. Funds recovered from frozen bank accounts will be transferred to the Rehabilitation Fund under this Bill, which will further be used to support survivors and prevent re-trafficking. For the first time, the buying and selling of human beings is being made a cognizable offence.

Victims, who have been forced to commit heinous crimes under this Bill by their traffickers, now have been granted immunity to protect them from undue prosecution.

The Bill has given specific charter, shape and method to the rehabilitation process. The functions and roles of agencies have been delineated. The national, State and district level committees on rehabilitation are a strong step, providing a single-window approach to the entire process. So far one had to knock on many doors to get any relief for the victim, but no more.

The Bill also makes it clear that rehabilitation is not contingent on prosecution. This provision is another major breakthrough as it guarantees the rights of the victim in the best possible manner. Further, there would not be any pressure on the victim to speak, state or depose in any particular manner due to external pressure. The provision of setting up a rehabilitation fund and the mandate given for the utilization of the fund is timely.

It is known that the police agencies across the country, except at few places, are indeed helpless in respect of funds for extending even the minimum care to rescued persons. Therefore, this Bill provides a rehabilitation fund for this purpose. For instance, yesterday 16 girls were rescued by the Delhi Commission for Women. Now, they have come to me saying 'what do we do with them?' The Government of Nepal is phoning us, saying 'send them back to us, send them to the Embassy.' The police have no idea where to spend the money from. The Bill removes all such impediments in the law enforcement process and justice by making adequate fund support for every act envisaged post-rescue.

The Bill has brought in accountability of the rehabilitation agencies of the Government. So far, under the existing laws, a duty was cast upon the police to rescue, and yet no accountability existed on the agencies of the Government concerned with rehabilitation. By endorsing a new provision of bringing in accountability of the Government agencies, it is not only the victim who is going to be benefited, but the entire justice delivery process stands to gain. The victim, who is counselled and rehabilitated, will be in a better position to support the prosecution.

Further, a strong step by the victim in ensuring the prosecution of offenders will naturally expedite the entire process. Taking it further, effective and timely prosecution of offenders will be a great boon in the prevention of such crimes. Therefore, this provision of victim and witness care will go a long way in ensuring the rule of law.

The chapter on prevention enhances the richness of the Bill. Earlier legislations like ITPA, Bonded Labour (Abolition) Act, Child Labour Act did envisage prevention, but the body of the legislation was conspicuously silent on the steps and the procedures. The present Bill, for the first time in the Indian Statute, has not left things to imagination. Preventive measures, the role of agencies, the tasks to be performed are clearly spelt out in the Bill. This will bring in accountability of all agencies concerned. Once legislated, prevention of trafficking becomes a legal mandate of the agencies concerned and this will ensure accountability and is a constructive step in good governance.

This Bill is a path-breaking step, and SAARC and UNODC nations are looking forward to India to take lead by enacting this law. While a number of countries have different laws for this crime, our Bill is unique. All other countries mostly focus on the crime and treat the victim primarily as a witness. Our Bill is comprehensive as it focuses on prevention, protection and prosecution, and puts in place institutional mechanisms for the same. It places the victim at the centre of the law. There are no conditions on the victim to testify to get access to entitlements. Unlike any other South Asian country, rehabilitation becomes a right of the victim under this Bill.

It is an improvement over the existing laws, including Section 370 of IPC. This section of IPC defines trafficking and its derivative, but it is silent on forced labour and bonded labour. This Bill incorporates trafficking for forced labour, bonded labour, besides for surrogacy, false marriage and begging as

aggravated forms of trafficking and calls for enhanced punishment for the offenders.

The proposed anti-trafficking Bill will hit the organized nexus of trafficking by attacking the economic base that powers this vicious crime. The provisions under this Bill aim at economic deterrence by providing for attachment and forfeiture of property, as I explained, that is used for the commission of offences. It will levy heavy fines and freeze bank accounts of the perpetrators. The funds recovered, as I have said before, will be transferred to the rehabilitation fund. It covers new and aggravated forms of trafficking with an increased punishment.

As our children look to us, it is time we stand up as a country and be counted for the right decision. The proposed Bill is the right step that will provide a comprehensive solution to deal with the issue of trafficking of persons in India.

India must take global leadership for the achievement of the Sustainable Development Goals by the year 2030. Goal 8.7 pertains to the need to take immediate and effective steps to eradicate forced labour, end any form of slavery and human trafficking and secure the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, including recruitment and use of child soldiers, by 2030, and by 2025, end child labour in all its forms.

Goal 16.2 seeks to end abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence and torture of children. India has also signed and ratified the UN Protocol to prevent, suppress and punish trafficking in persons, especially

women and children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime, which requires India to formulate a comprehensive approach to eliminate all forms of trafficking.

I speak to all of you. Let us make this Bill a reality today to protect and provide for the millions of victims who have suffered silently for years. We are accountable to all our citizens, especially the most vulnerable ones, women and children. Today we have a chance to deliver to them a law which guarantees their rights and ensures that the perpetrators of crimes are brought to justice. Thank you.

HON. SPEAKER: Motion moved:

“That the Bill to prevent trafficking of persons, especially women and children and to provide care, protection and rehabilitation to the victims of trafficking, to prosecute offenders and to create a legal, economic and social environment for the victims and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration.”

PROF. SUGATA BOSE (JADAVPUR): I wanted to just correct an error in the List of Business at No. 15. It is an important Bill. It says that this Bill is being moved to ‘persecute offenders’. I am sure that this is probably a typographical error. But it could also be a Freudian slip since so many vulnerable people are being ‘persecuted’ in our country. I know that Shrimati Maneka Gandhi is a very kind hearted person and she would not wish to ‘persecute’ any one. So, before we proceed any further, I think we should make a correction at No. 15 of the List of Business to say that this Bill will ‘prosecute offenders’. There is a big difference between ‘persecution’ and ‘prosecution.’

HON. SPEAKER: It must be a typing mistake.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I did not make the List of Business.

HON. SPEAKER: It is a typing mistake.

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Some of us are conscious that this Government is not always aware of the distinction between 'persecution' and 'prosecution'. But that is another matter.

Let me just stress that there is absolutely no doubt, no two views about the need to have a strong law to deal with trafficking in people.

13 33 hrs

(Hon. Deputy Speaker *in the Chair*)

It is interesting to note that our founding fathers and mothers found the offence of trafficking so horrific that they penalised it through Article 23 of the Constitution even though constitutional provisions do not normally deal with criminal law. So, that was a very major step. As the Justice Verma Committee Report pointed out, it is a matter of deep concern in our country and across the world that lakhs of people, especially women and children, are uprooted and transmitted through illegal placement agencies and rackets as part of the trafficking and trade in human beings.

Now, we are all in agreement that trafficking must be rooted out. But we may differ on how to approach it. We must not adopt the extreme approach of saying that anyone who does not agree with this Bill is pro-trafficking. We are all, as the hon. Minister was saying, determined to fight for the vulnerable women and children of this country, but we wish to fight effectively and this Bill sadly does not do that.

I want to stress that the intent of the Minister in bringing the Bill to deal with trafficking is good. Indeed there are many good things about this Bill. I agree with her intent and the positive provisions, some of which she has

mentioned, like the interim relief for the victims, requiring cases of trafficking to be conducted by special public prosecutors, providing for compensation for victims, as well as mandating cross border repatriation of victims of international trafficking in a time-bound manner. These are to be applauded. However, the rest of the Bill raises very many serious concerns.

We already have numerous laws which deal with trafficking. There is Section 370 of the Indian Penal code; there is ITPA which the Minister mentioned; there is Juvenile Justice Act which she sadly changed couple of years ago; there is the Bonded Labour System (Abolition) Act; there is the Contract Labour Act; there is the Inter-State Migrant Workmen Act; etc. But the problem with all these laws is that they have varied approaches and parallel enforcement and institutional mechanisms to deal with trafficking. So, clearly the need of the hour is a comprehensive legislation which truly harmonises these various provisions and brings out a clear-cut strategy to deal with trafficking. This is what was promised by the Government to the Supreme Court in the Prajwala vs. Union of India case in 2015.

Sadly, however, this Bill only adds to the existing overlapping cocktail of laws, and through the creation of 10 anti-trafficking bureaucratic bodies it will also create confusion in the enforcement of these laws.

Now, the Statement of Objects and Reasons of this Bill states that the existing laws do not recognize trafficking of persons for the purposes of physical and other forms of exploitation. This is simply factually incorrect. In fact, all the new offences that the Bill creates under the term 'aggravated

trafficking' -- which the Minister also mentioned -- are already covered under the ambit of Section 370 IPC and other provisions. In other words, this is a rehash of existing laws, and we must face it for what it is.

One of the cardinal principles involved in drafting legislation is to study how the existing laws have been applied, so that the new laws can improve not only upon the old laws, but upon any unintended consequences, difficulties and failings of the previous laws.

The Bill heavily relies on the definition of trafficking provided under Section 370 of the IPC. However, a study of 125 appellate cases just in the last five years, between 2013 and 2018, shows that this provision and Section 370A have been applied liberally by the Police and the courts, going well beyond the legislative intent of those provisions, as a proxy for wrongful confinement. In a case, one case out of these many cases, where a woman left her husband and lived with another man along with her child, attracted this provision of trafficking. This provision has also been used to target sex workers -- which I have mentioned to the Minister also -- most of whom are marginalized and vulnerable women in our society.

My big critique is not just to say that there is lack of safeguards in all the provisions in the Bill. The legal system, unfortunately, conflates the fine distinction between those women who are trafficked into sex work and adult consenting sex workers. There is no doubt that our society views sex work negatively, prejudicially, and through a moralistic lens. But, as the Supreme Court has just reminded us in a different context, we, as Legislators, need to

view matters of rights and laws through the lens of constitutional morality and not majoritarian social morality.

Irrespective of our individual views, I do not think that anyone can accept the idea of harassing people who voluntarily engage in the sex trade owing to their economic condition. As it is, Section 370 of the IPC is used extensively against sex workers in conjunction with the ITPA. There are numerous instances in which the Police have threatened sex workers, and they have cited these laws to threaten them and demanded bribes and even demanding sex from these poor women. Unfortunately, this Bill has no safeguards against such misuse.

Let us keep in mind that if we want to ensure success of HIV awareness programmes, for example, and if we want to root out trafficking in sex work, then we need to cooperate with sex workers in collectives. If we fail to place enough safeguards against misuse, then the law will only drive them further underground and jeopardize our public health programmes and the larger fight against trafficking. ... (*Interruptions*)

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, why is it that only the Chair is being shown on the screen?

DR. SHASHI THAROOR : It seems that the camera is not looking at the speaker. I hope that it is hearing us. Sir, we are seeing you extensively, but not the speaker who is speaking in the House, but only for a couple of minutes.

Nonetheless, even if the Bill does not expressly mention 'sex work', phrases such as 'resulting in pregnancy' or 'causing exposure to HIV' can be

used to bring it under the ambit of the law. Similarly, the use of phrases such as 'administration of hormones' in the Bill can be used to target transgender persons since many of them take hormones during their process of gender affirmation, and since some medical practitioners are unwilling to do so, on their behalf they at-times self-administer these substances.

Transgender persons also work in collectives, and they unfortunately often have to engage in begging due to lack of opportunities available to them. This Bill criminalizes trafficking for the purpose of begging, and since Section 370 has been widely applied in the past, I fear that this provision will now be used to target transgender groups because they beg as often as they do.

The Bill uses phrases such as 'may lead to trafficking' or 'likely to be used for trafficking' in penal provisions. How can we have language like this in something that criminalises and imposes punishment - 'likely', 'maybe'? We must have a clear nexus between an Act and an offence. That is how laws are supposed to be written. These provisions can be struck down by the Judiciary even as being unconstitutional because vagueness in the definition of criminal offences can be applied arbitrarily, and will therefore, violate Article 14 of the Constitution. This is the recent ruling of *Shreya Shingal Versus Union of India* and the court has taken a clear line on this.

The Bill, as the hon. Minister mentioned, creates a new offence of aggravated trafficking. This attracts at least 10 years of imprisonment and may extend to life imprisonment. Now, this is an addition to the existing definition of Section 370 of the IPC – definition of trafficking. Therefore, it is supposed to be

more serious in nature; otherwise, what makes it aggravated. But the logical fallacy of this is completely apparent when you look at the Bill because it says that trafficking for the purposes of begging is an aggravated offence but trafficking for the purpose of sexual exploitation is a general offence. So, what is the difference? Why is begging worse than exploiting women sexually? What is aggravated trafficking all about?

It is distressing to note that Clause 16 of the Bill which allows medical examination of the victims fails to mention that the consent of the victim shall be taken as and when practical. This is particularly relevant for victims who may be suffering from HIV-AIDS because there were instances of sharing of medical results with the courts without the consent of these persons. And the court have unfortunately ruled that such persons must remain in rehabilitation homes as their families cannot take care of them, forcing them thereby to be torn apart from their loved ones. I have got details if the Minister is interested in such cases.

Now, let us look at rehabilitation which again the hon. Minister mentioned as a serious and important element. This Bill sadly reiterates the failed method of institutional rehabilitation. We need to make sure that people who do not want to be in these homes are not forcefully incarcerated in them. In fact, a recent study has revealed that out of a sample of 243 women picked up in raids in Maharashtra, 193 were adult consenting sex workers who were incarcerated in rehabilitation homes against their wishes. Some of these

women were kept in these homes for nearly three years. The only beneficiaries in this provision are the people running those homes, they are not the victims.

I understand that the Bill also empowers the Magistrate to release victims from these homes if they can apply for the same. But there is no requirement for the Magistrate to hear them in person before deciding on the merits of their case. Nor is there an appeal procedure provided if the Magistrate rejects the application. If anything, in fact, the proviso in Section 17(4) even allows the Magistrate to disregard the wishes of an adult victim, if the Magistrate is not convinced that it has been made voluntarily. This is a paternalist measure unworthy of the hon. Minister, which denies the agency of the victim. These homes can be places of mental and physical torture.

The interesting thing is that this Bill has gone through many drafts. The earlier draft, the fourth draft, had provisions which mandated monthly inspections of these homes because we clearly need regular assessment of quality of these homes. Even the Supreme Court appointed panel had stated that the type of vocational training provided in these homes fails to provide the skills necessary for basic sustenance. That draft of the Bill also had beneficial provisions such as giving the victim timely notice of trials, giving them the power to summon materials, periodic review of the protection of the victims, mandating the Government to take immediate action against anyone harassing the victims. Unfortunately, the present Bill has dropped all these provisions. Clearly some vested interests have intervened; the people involved in these homes don't want to be inspected; they don't want to be held accountable. I

urge the Minister to retain these provisions which help the victims of trafficking in the long run. They were there in the earlier draft and she can easily restore them again.

Bonded labour is a permanent form of trafficking in our country. Steps must be taken to enforce the mandate of the Bonded Labour System (Abolition) Act of 1976. Despite its poor implementation the Act of 1976 is revolutionary. It lays importance on the rehabilitation of the victims of bonded labour by recognising their agency while providing them economic assistance. However, this rights-based approach of the Act may be weakened by the institutional method of rehabilitation favoured by the present Bill. Particularly, clause 59 states that the provisions of this Bill will have an overriding effect over the provisions of any other statutes if conflict arises. So, even the more progressive language of the Bonded Labour Bill can be overridden by this retrogressive Bill. It is a disgrace.

In fact, this Government could have even used an existing model in the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013 which was passed by the then UPA Government. This Bill fails to replicate this Model even though it lays emphasis on providing assistance to victims and respecting the agency while empowering them. That is a sort of model which this Government should follow but, unfortunately, the Bill today before us fails to replicate any of these core principles.

So, we are going backwards in this Bill from progressive legislation already adopted by this Parliament in recent years.

The Bill establishes a Rehabilitation Fund for a wide range of activities, the Minister rightly mentioned, such as providing legal aid, housing, skill development and rehabilitation of victims of trafficking. Interestingly, this discarded fourth Draft of the Bill had a clause mandating the Government to allot budgetary allocations to this Fund. But this Bill mysteriously drops that request. As per the Financial Memorandum attached to the Bill, Mr. Chairman, a paltry sum of Rs. 10 crore has been allotted by the Government to the Rehabilitation Fund whereas this Government is a government that has spent Rs. 4,343 crore on publicity and advertising alone since it came to power in May 2014. For women and children victims of whom the Minister speaks so emotionally, Rs. 10 crore has been allotted. In fact, Rs. 10 crore is the same amount given to one more bureaucratic institution of which our country has too many, namely, the National Anti-Trafficking Bureau. That amount goes up to Rs. 25 crore in the second and third year for the bureaucracy whereas renewal of the Rehabilitation Fund is only assured on an 'as needed' basis.

Let me say, Sir, unambiguously to the Minister, this is a Bill of the bureaucracy, drafted by the bureaucracy and for the bureaucracy. The victims are the lowest priority in this Bill.

Now, I want to get to the very important issue of prevention because the Bill claims to place measures to prevent trafficking. It is, actually, stated as the very first in the Objects and Reasons of what this Bill is trying to accomplish. But there is only one clause in the entire Bill which deals with preventive measures. These measures are broad and very vaguely worded. I will quote

some: “Developing appropriate law and order framework to ensure prevention of trafficking...”. What is ‘appropriate law and order framework’? Are we going to give the *Sarkar* a complete blank cheque? I will quote another point: “Coordinating with corporate sector to implement various schemes and programmes for the prevention in trafficking of persons”. Are we now through the law empowering a nameless set of companies to profit from dealing with the trafficking of persons? It fails to give any vision of policy to prevent trafficking. But I suspect that this may even be deliberate on the part of the drafters because placing vague obligations in a law makes it even more difficult to hold the Government accountable.

There is a well-accepted distinction that troubles me that has been ignored by the Government in talking about the migration perspective. The distinction between human trafficking and the smuggling of migrants is well established in international law. Trafficking in persons, i.e. the kind of thing we are trying to outlaw in the Bill today, involves the use of either deception or coercion to exploit the victim either within their own country -- in this case, our country -- or transnationally (as the hon. Minister mentioned Nepal as an example) whereas in the case of smuggling of migrants, there is no coercion or deception, the smugglers are facilitating the irregular crossing of international borders with the consent of the migrant. Very often, the migrant pays money to an agent or a syndicate to smuggle him across the border to another country.

The relationship between the smuggler and the migrant, therefore, is not exploitative in nature; it is symbiotic. But the relationship between the trafficker

and the migrant is exploitative. That distinction has to be observed and is completely missing in the language and intent of the Bill.

Smuggling or migration often takes place due to dire economic conditions, we know that. The UN member states as far back as 1975 agreed to avoid the word 'illegal' in relation to migration. In fact, there is a draft Global Compact for Migration that has just been negotiated, with India agreeing to it. The negotiation finished this month and it will be adopted at the UN in December. This Global Compact makes a clear distinction between smuggling of migrants and human trafficking in judicial prosecutions policy and legislation. Even though these activities may both be offences, it will be unfair and disproportionate to club the two while imposing penal consequences.

So, again I request the Minister to look again at the Bill. Clause 31(11) of the Bill mentions trafficking by encouraging any person to migrate illegally into India or Indians into other countries as 'aggravated trafficking'. Thereby it conflates trafficking with smuggling of migrants in violation of international law and human rights principles. And once again India is just agreeing to a Global Compact and then we are passing a Bill today that will undermine what we have agreed to that we are going to ratify in December.

Let me now conclude with a few suggestions. The Bill talks about the repatriation of victims of trafficking. However, it completely ignores the fact that victims of trafficking also have families. Repatriation only means under the law that the Government would transfer the victim from one State to another, to their home State. But the Bill should have actually prescribed restoration,

which mandates the Government to help the victim reunite with his or her family from which they have been separated ,rather than merely leaving them in a limbo in the State of origin. This must only be undertaken if the adult victim wishes to return to his or her home.

We need to recognise that trafficking is not merely a law and order issue, it has its roots in socio-economic realities of our country and our neighbouring countries. By weakening our labour laws, denying MNREGA workers their wages, you make people more vulnerable. Those are the ones who end up being exploited by trafficking. So, we need to also have some sense of responsibility to improve the socio-economic condition of our women and children.

Then the safeguards against misuse are missing. One way in which misuse of this Bill can be reduced is if the Government implements the recommendations of the Supreme Court appointed panel report submitted in September, 2016 which suggested amendments to the regressive provisions of the ITPA. This will prevent enforcement agencies widening the scope of the Bill by conjointly reading it with an outdated ITPA. So, if you fix the ITPA as well, hon. Minister, then this Bill has a better chance of being applied fairly and not misused.

The Bill still follows the conventional method of combating trafficking. The Minister could have considered, but should consider still, inserting a supply chain transparency clause as done under the laws of the US, UK, France, Switzerland and Australia which will actually hold corporations liable if

there is forced labour in any of their supply chains. That too is an act of trafficking.

I agree with the hon. Minister that we should have enacted a legislation which can make us a leader in South Asia and even in the world. She mentioned that SAARC is looking at us. Many countries in the world would look at us if we took decisive action in the fight against trafficking. However, this Bill suffers from numerous problems and deficiencies.

The hon. Minister even spoke of international cooperation. I wish to draw the attention of the Minister to the statements issued by the United Nations Special Rapporteur on Trafficking in Persons as well as the UN Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery just four days ago on this Bill when this Bill became public. They said, "Trafficking in persons is primarily a gross human rights violation. However, the Bill overemphasises the criminal response and does not give due consideration to the rights and needs of victims and their effective protection and proper rehabilitation."

If I know a little bit about the UN organisation, Mr. Deputy Speaker, the Special Rapporteurs are not people who would usually comment on matters of pending domestic legislation before a law is passed. But even these top international experts have been forced to issue this warning because this Bill is so bad. It would be ill advised on the part of the Government to ignore such a public warning by the United Nations' two leading experts on the subject of this Bill.

I do agree with the hon. Minister that women and children are vulnerable because our laws have failed. Let us not have one more law that will fail despite the Minister's good intentions and certain positive features of the Bill that I had mentioned. It is very clear that my objections are fundamental and a lot more can be done. Therefore, I appeal to the Minister; I am not opposing the Bill; I am requesting that the Minister may refer this Bill to the Standing Committee, which, it is astonishing, has not been done, so that the deficiencies in this Bill can be addressed and we can really formulate a model law against trafficking which the whole of South Asia can look up to and say that India has set an example. I plead with you, hon. Minister, to seriously refer this Bill to the Standing Committee and then come back to us in the next session. We will pass it with pleasure.

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है और सदन में सरकार की तरफ से बहुत कम सांसद बैठे हैं। ... (व्यवधान) There is nobody in the House. ... (*Interruptions*)

SHRI K.C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Hon. Deputy Speaker Sir, at least the Minister should have sent this Bill to the Standing Committee.... (*Interruptions*)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): Hon. Deputy Speaker Sir, what is the problem in sending this Bill to the Standing Committee?

HON. DEPUTY SPEAKER: I cannot force the Minister to do it. You have conveyed it to her. Now it is up to her.

... (*Interruptions*)

श्री ओम बिरला (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के 70 साल बाद देश में यह विधेयक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है, जो संगठित गिरोह को रोकने में कामयाब होगा। देश और दुनिया में ड्रग्स और हथियार के बाद मानव तस्करी सबसे बड़ा व्यापार बन गया था। इस कारण जब हम दुनिया के देशों की बात करते हैं, तो 80 प्रतिशत तस्करी महिलाओं और बच्चों की होती है। देश में यौन शोषण के कारण संगठित अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो केवल मानव तस्करी की ही नहीं, बल्कि मूक पशुओं की भी चिंता करती हैं। उन्होंने इस विषय की संवेदना को समझा है। यह बिल जल्दी में नहीं लाया गया है बल्कि वर्ष 2016 से कई देशों के सुझावों, कई सांसदों, विधायकों के सुझाव, कई समितियों के सुझावों के बाद इस बिल को लाया गया है। आज के अखबार में हमने एक दर्दभरी कहानी देखी। हमारे पड़ोसी देश की 16 महिलाओं को किस प्रकार मानव तस्करी द्वारा नेपाल से भारत और भारत से दूसरे देशों में भेजा जा रहा था। यह केवल एक कहानी नहीं है। ट्रेन में सफर करने वाले एक व्यक्ति ने 25 बच्चियों को देखा और जिस तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी ने सिस्टम डेवलप किया है, तो तुरंत उस ट्रेन से मैसेज प्राप्त होने के बाद उन बच्चियों की तस्करी रोकने का काम किया।

14 00 hrs

कानून पहले भी था। पहले भी आइपीसी एक्ट, 1860 में इम्मोरल ट्रेफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 के कानून की कुछ बातें आती थीं। आइपीसी एक्ट, 1860 की धारा 370 में मानव तस्करी और यौन शोषण को अपराध की श्रेणी में रखा गया था। इम्मोरल ट्रेफिक (प्रिवेंशन) एक्ट, 1956 में यौन और वाणिज्यिक शोषण के लिए बिल लाये गये थे। लेकिन यह बिल, अपने आप में एक व्यापक बिल है। अभी तक जो कानून थे, उनके अंदर मानव तस्करी को रोकने का एकबद्ध प्रावधान नहीं था। लेकिन, इस बिल के माध्यम से हम इस देश में संगठित रूप से मानव तस्करी को रोकने में कामयाब होंगे। इसीलिए इस बिल में पीड़ितों की देखरेख, संरक्षण और पुनर्वास के प्रावधान किये गये हैं। उन पीड़ितों को ठीक से न्याय मिल सके, इसके लिए उनको विधिक आर्थिक सहायता, अच्छे सामाजिक वातावरण की व्यवस्था भी की गयी है। मानव तस्करी द्वारा लोगों को विदेशों में

भेजने का जो क्रम चल रहा था, उसे रोकने में भी यह विधेयक कामयाब होगा। इसी के साथ, इस विधेयक में मानव तस्करी से निवारण, संरक्षण, पुनर्वास और अन्वेषण के पहलू भी हैं।

जब एक राज्य से दूसरे राज्य में मानव तस्करी होती थी, तो अलग-अलग राज्यों में घटना घटित होने के कारण पुलिस इन्वेस्टीगेशन का सवाल आ जाता था। किस राज्य से बच्ची लायी गयी, किस राज्य में बेची गयी, कहाँ एफआइआर दर्ज हो, किस कोर्ट में केस चले, इसी में मामला उलझा रहता था। इसमें दो राज्यों के सम्मिलित होने के कारण तथा अलग-अलग इन्वेस्टीगेशन होने के कारण पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता था। हमने अभी तक जितने भी तस्करी के उदाहरण देखे हैं, उनमें यही पाया गया है।

जहाँ पर अपराध घटित हुआ, वहाँ पर पीड़ितों को जाना पड़ता था। पीड़ितों और साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों के संरक्षण का कानून नहीं था। पीड़ित व्यक्ति या महिला या बच्चे को नये कानून के अनुसार वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बंद कमरे में उसकी जनसुनवाई होगी और पीड़ित और साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने का प्रावधान इस कानून के माध्यम से किया जाएगा।

महोदय, भारतवर्ष 125 करोड़ जनता का देश है। अभी तक हम देश में मानव तस्करी को रोकने में कामयाब नहीं हुए हैं। दुनिया को पता है कि हमारे देश के अनेक हिस्से और प्रदेश आज भी गरीबी और अशिक्षा के कारण पिछड़े हुए हैं। इसलिए सरकार ने पहली बार पूरे देश में उन जिलों में, उन तहसीलों में, उन गाँवों में, जो शिक्षा से पिछड़े हुए हैं, स्वास्थ्य से पिछड़े हुए हैं, रोजगार से पिछड़े हुए हैं, अपेक्षाओं से भरे ऐसे 115 जिलों को माननीय प्रधान मंत्री जी ने आगे लाने की कोशिश की है। उन पिछड़े जिलों को, जहाँ गरीबी, अशिक्षा और रोजगार के संसाधन नहीं हैं, उनको किस तरीके से बेहतर किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने वहाँ सारे मापदंडों को पूरा करने के लिए वहाँ के जिला कलेक्टरों से सीधा संवाद किया है। हम 70 सालों के बाद यह देख सके कि पूरे देश के हर गांव में समकक्ष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का जो पैरामीटर है, उसको लेकर पूरा देश एक साथ आगे बढ़ सके, सब का साथ, सब का विकास की अवधारण का पालन कर सके, इसके

लिए माननीय प्रधान मंत्री जी ने प्रयास किया है। जब तक इस देश के अंदर गरीबी और अशिक्षा दूर नहीं होगी, तब तक हम मानव तस्करी को नहीं रोक पाएंगे। हम कानून जरूर बना रहे हैं, लेकिन अगर हमें मानव तस्करी को रोकना है, तो देश में गरीबी को रोकना पड़ेगा, अशिक्षा को रोकना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, हालत यह थी कि जिस देश में 70 सालों में 19 हजार गांव में लाइट नहीं हो, पीने का पानी नहीं हो, ऐसी हालत में यह देश चल रहा था। आज प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि पूरे 19 हजार गांवों में लाइट होगी। महिलाओं को रोजगार - स्वरोजगार देने के लिए स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 12 करोड़ महिलाओं को आत्म निर्भर करने का काम करेंगे। इस देश में गरीब जहां रहता था, वहां छत नहीं हुआ करती थी। छत के अभाव में वह बाहर जिंदगी गुजारता था। आज माननीय प्रधान मंत्री ने कहा है कि एक करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य के तहत हमने अब तक 36 लाख मकान बनाने का काम किया है। उन घरों में लाइट दी है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन दिया है, उन घरों की बेटियों के पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं, हम इस देश में 12 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक के माध्यम से रोजगार दे सके। उसमें हमने 50 परसेंट उन महिलाओं को देने का लक्ष्य तय किया है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास रोजगार के संसाधन नहीं हैं। इन महिलाओं को रोजगार के माध्यम से खड़ा करने का काम इस देश में अगर किसी ने किया है, तो माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया है। अब गांव के अंतिम छोर पर बैठी हुई महिलाएं भी स्वरोजगार योजना और मुद्रा बैंक के माध्यम से 50 हजार रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन लेकर अपनी गरीबी को दूर कर सकती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब इस देश से गरीबी दूर होगी, अशिक्षा दूर होगी, तब जाकर हम देश के विकास की बात कर सकते हैं। तब जाकर हम मानव तस्करी को रोकने की बात कर सकते हैं। जिस देश में करोड़ों महिलाएं शौच के लिए जाती हों, इसलिए देश में हमने छह करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया है। हमने तीन लाख गांवों में शौचालय बनाने का काम किया है। ये

इज्जतघर हमारी इज्जत है, उपाध्यक्ष महोदय। इसलिए हम देश से अशिक्षा और गरीबी को दूर करने के साथ-साथ मानव तस्करी को रोकने का कानून भी लाए हैं। मानव तस्करी का कानून लाने के साथ ही हमने मानव तस्करी और ट्रैफिकिंग रोकने की कई चीजें बनाई हैं, जिससे मानव तस्करी कराने वाला वह व्यक्ति भी अपराधी की श्रेणी में आए। इसलिए हमने कानून को व्यापक बनाया है।

हमारे माननीय सदस्य चले गए हैं। वे कह रहे थे कि इस कानून में बहुत कमियां हैं, कानून अपरिपक्व और अधूरा है। वर्ष 2016 से वर्ष 2018, दो साल तक इस कानून पर जनता के बीच में माननीय मेनका गांधी जी ने काम किया है। वे कई संसद सदस्यों और हमसे से भी मिली थीं। कई महिलाएं और एन.जी.ओ. मिले, जिन्होंने कहा कि आप संसद में बैठते हो, हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मानव तस्करी हो रही है और आप संसद में बैठकर इस पर कानून नहीं बना रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री जी और मेनका गांधी जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस कानून को बनाया। इतना ही नहीं, इस कानून में स्टेट लेवल पर एक नोडल अधिकारी बनेगा। इसमें जिला लेवल पर एक नोडल अधिकारी बनेगा। इसमें जिला लेवल पर एंटी ट्रैफिक ईकाइयां बनेंगी और लोगों को जल्दी न्याय मिले, इसके लिए हर जिले के अंदर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनेगा। एक साल के अंदर ऐसे मामलों का निपटारा हो और जल्दी न्याय मिले, इसलिए इस कानून के अंदर इसे परिभाषित किया गया है। इतना ही नहीं, इस कानून के तहत, जो लोग पीड़ित हैं, उनका पुनर्वास, रोजगार और उनके परिवार की स्थितियों को देखते हुए उनको किस तरीके से आर्थिक रूप से मजबूत करें, इसे भी इस कानून के अंदर लाने का काम किया गया है। अभी तक महिलाओं के लिए पुनर्वास क्या होगा, उसकी राशि क्या होगी, इसके बारे में माननीय सदस्य बोल रहे थे कि दस करोड़ रुपये की राशि कम है।

उपाध्यक्ष महोदय, पैसों की कमी माननीय नरेन्द्र मोदी जी के राज में नहीं है। इसीलिए संरक्षण पुनर्वास के साथ इस कानून को व्यापक बनाया गया है। मैं कह सकता हूं कि इस कानून के माध्यम से हम इस देश के अंदर मानव तस्करी को रोकने में कामयाब होंगे। अभी तक हमारे देश में

बच्चों के अंग बेचने की तस्करी होती थी। छोटे-छोटे बच्चों को बेचा जाता था, महिलाओं को बेचा जाता था। इस देश के अंदर संवेदना खत्म हो गई थी। इस कानून के बनने के बाद जो देश में समेकित रूप से मानव तस्करी का काम कर रहे थे, अब मानव तस्करी का काम करने वालों का एक रास्ता तिहाड़ की जेल में होगा या हिंदुस्तान की अन्य जेलों में होगा। कोई भी बंधुआ मजदूर या किसी भी मानव तस्करी करने वाले को गम्भीर और दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मैं माननीय मेनका गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण बिल को सदन में पेश किया और मैं चाहूँगा कि सारा सदन इस बिल को पारित करे, ताकि उनके साथ न्याय हो सके।

धन्यवाद।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYANAGAR): Sir, I rise to speak on The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.

Sir, trafficking is not only a global concern, but also it is affecting a number of South Asian Nations. It is commendable that India is taking pioneering action in formulating a comprehensive Bill. The new Bill proposes to tackle one of the most pervasive crimes affecting the most vulnerable persons. It aims at prevention, rescue and rehabilitation of the vulnerable target groups, including women and children.

This Bill, however, does not propose any new things other than what had already existed. It, however, creates a new category of aggravated forms of trafficking which carry a minimum punishment of 10 years and which may be extended to life imprisonment. Some of the aggravated forms of trafficking, included in the Bill, are trafficking for the purpose of forced labour, begging, marriage and child bearing, which have already been included under the existing law. Similarly, the so-called new offences of administering hormones or committing trafficking by administering alcohol and drugs, have already been incorporated in the existing law.

Sir, the new anti-trafficking Bill appears to be flawed as there are provisions that are problematic and also, they make no sense. For instance, gradation of offences appears to be illogical. The anti-trafficking Bill categorises offences for a certain purpose as aggravated forms of trafficking which carry a punishment of 10 years or life imprisonment. Logically, offences that are graded higher must be more serious or culpable than the acts that

constituted trafficking under Section 370 IPC, which attract punishment of 7 to 10 years imprisonment and fine. But, that is not the fact. Trafficking for the purpose of begging is considered to be aggravated, whereas trafficking for sexual exploitation is a simple trafficking. Further, still slavery and practices similar to slavery and servitude, which captures the most shocking forms of operation and bondage, under domestic and international law, are also coming under simple trafficking.

Sir, some of the provisions are also vague and impractical. The Bill criminalises a host of activities which lack culpability and criminal intent. For example, this Bill authorises closure of premises which can be used as place of trafficking. Therefore, applied in the context of labour trafficking, this law would allow factories and firms to be closed down on a simple complaint by police or any person.

The penal provisions against promoting or facilitating trafficking of persons are also vague. IT companies, travel companies and employment sites would need more clarity.

There is a provision for confiscation of properties. The properties may be attached not only when they are used for the commission of an offence but also if they are likely to be used for commission of an offence under the Act. There is no guidance as to when and under what circumstances such a likelihood would arise so as to warrant attachment of the properties.

The Bill falls back on the outdated methods of rescuing and detaining victims in the name of rehabilitation. Institutionalisation of victims in homes

apparently for protection and rehabilitation is contradictory to their fundamental rights. The victim of trafficking, especially woman who had been trafficked for sexual exploitation need to be rehabilitated in homes or shelters which have right environment for rehabilitation and integration in the society rather than providing a hostile and unsafe environment resulting in similar trauma.

Instead of streamlining enforcement, the Anti-Trafficking Bill encourages institutional bureaucracy by creating ten different agencies including Anti-Trafficking Officers, Units, Committees and the bureaus at the district and national levels to counter the problem which will result in chaos and policy indecision as well as passing the buck on the question of accountability.

Besides, none of the proposed authorities has any representation from the affected community whose participation and perspective is vital for addressing trafficking successfully. In fact, involvement of sex worker in oversight committee and Anti-Trafficking Boards was strongly recommended by the Supreme Court appointed panel in light of their effective role and contribution. This has been overlooked.

Sir, the problem of trafficking cannot be dissociated from poverty, livelihood, displacement and security. People have and will always move for work whether out of distress or for better opportunities.

Prisons cannot confine or capture the dreams and aspirations of people, especially the poor and the marginalised. Adopting an approach of imprisonment in jail to what is largely a socio-economic phenomenon, is misplaced and unwise.

Before I conclude my speech, I would like to refer to one incident which happened in an NGO based home in the district of Jalpaiguri in West Bengal where child trafficking cases happened and local and national level women ...* leaders were involved ... (*Interruptions*).

HON. DEPUTY SPEAKER: The name will not go on record. I have expunged that. Please sit down.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : They were women belonging to the ruling Party. If it is the scenario, the *beti bachao* slogan is not only vague but also a show off.

* Not recorded

SHRIMATI V. SATHYABAMA (TIRUPPUR): Sir, first of all, I convey my congratulations and sincere thanks to the hon. Minister for Women and Child Development, Shrimati Maneka Gandhi for bringing the country's first ever anti-trafficking law which is the need of the hour.

The Bill provides for the establishment of a National Anti-Trafficking Bureau to investigate trafficking cases and implement provisions of the Bill. The Bureau will comprise of police officers and other officers as required. Further, the Bureau may request the State Government to co-operate in the investigation or transfer the case to the State Government for investigation and trial.

The coordinating and monitoring surveillance along known routes, facilitating surveillance, enforcement and preventive steps, maintaining coordination between law enforcement agencies and NGOs and other stakeholders, and increasing international cooperation with authorities abroad for intelligence sharing and mutual legal assistance are the main functions of the Bureau.

Under the Bill, the State Government will appoint a State Nodal Officer and State Anti-Trafficking Committee. The Bill also provides for the setting up of Anti-Trafficking Units at the district level. The Bill provides for the establishment of Anti-Trafficking Relief and Rehabilitation Committees at the national, State and district levels. An Anti-Trafficking Police Officer or an ATU can rescue persons if there is an imminent danger to them. They will be produced before a Magistrate or a Child Welfare Committee for medical

examination. The district ATC will provide relief and rehabilitation services to the rescued persons.

The Bill requires the Central or State Government to set up Protection Homes. These would provide shelter, food, counselling and medical services to the victims. Further, the Central or the State Government will maintain the Rehabilitation Homes in each district to provide long-term rehabilitation to the victims. Rehabilitation of victims will not be dependent on criminal proceedings being initiated against the accused or the outcome of the proceedings. The Central Government will also create a Rehabilitation Fund which will be used to set up these Protection and Rehabilitation Homes.

This Bill provides for setting up designated courts in each district which will seek to complete trial within a year. The Bill specifies the penalties for various offences including trafficking of persons, promoting trafficking, disclosing the identity of the victim and aggravated trafficking such as trafficking for bonded labour and begging. For example, aggravated trafficking will be punishable with rigorous imprisonment of ten years up to life imprisonment along with a minimum fine of one lakh of rupees. Further, publishing of any material which may lead to the trafficking of a person will be punishable with imprisonment between five and ten years and a fine between Rs. 50,000 and Rs. 1 lakh.

Before I conclude, I urge the Union Government to be cautious and ensure that the provisions of the Bill after becoming an Act should not be misused or abused for personal vengeance or vendetta.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): Sir, the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 is a very interesting Bill.

Primarily, I find two headlights focussing in two directions. The Bill seems to have two main angles. First is, rehabilitation of unwanted bureaucrats either at the State level or at the Centre who will be adjusted in various Anti-Trafficking Committees. This is part A.

Then, part B is giving excessive powers to cops to search, seizure, rescue, investigation, collecting evidence etc. The very first page itself focusses on two angles. But along with that, I think all hon. Members of Parliament have received a letter from no less a person than Shri Satyarthi supporting and exhorting the MPs to support the Bill that Shrimati Maneka Gandhi will bring forth. We would have anyway done it because no matter what we say, the Bill will be passed.

But, let me, at the outset, say that although the intention of this Bill is extremely good, it is having a lot of lapses and it should have a proper review which it deserves. We are not doubting the intentions of the hon. Minister. Her intentions are good, but the Bill does not focus on human rights or it is not based on victim-centric approach. It lacks in these two things. Mostly the stress is on criminal law perspective. For example, the focus is on rescue, raids, rehabilitation, institutionalisation of victims under the garb of rehabilitation instead of protection.

None of us can claim that we are unaware of what happened in the Muzaffarpur shelter a few days ago. Even the Government of Bihar was

compelled to admit that the hapless girls, who were housed there, were being exploited physically and a lot of injustice was meted out to them and there was no quarter they could approach for help. So, this is not something one can politically wave off and we know that the Minister is not dealing with this as a political subject because if she says that, then it so happens that Bihar is governed by the party which is in power at the Centre.

I would like to refer to the case of *Buddhadev Karmakar v State of West Bengal* in which the Supreme Court constituted a panel to examine legal issues in relation to prevention of trafficking, rehabilitation of sex workers to leave sex work, conditions conducive for sex workers to live with dignity. This was exclusively for sex workers. I am not going into that aspect. But one of the key recommendations of the panel was to adopt community-based rehabilitation. Unfortunately, this Bill badly lacks on that aspect and it completely ignores it.

I read through most of the Bill. It is quite a big Bill, it took me some time to comprehend the language. It has very high levels of surveillance built into it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Is it American English?

SHRI TATHAGATA SATPATHY : As Mr. Mahtab says, the Bill is virtually a copy of an American Bill, the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956, which probably they might have thrown into the dustbin and one of our bureaucrats, who must have gone on a jaunt to Washington DC, might have picked it up and presented it to the hon. Minister. Madam Minister, this is my creation.

Sir, the language also is a little confusing. If you see Section 20 (vii), it is all surveillance in the garb of rehabilitation. The Bill says that police officers can, on mere suspicion that someone is being trafficked, conduct a raid and rescue operation. The Bill also authorises closure of premises which are to be used as a place of trafficking about which earlier speakers have also mentioned. These premises can include land, farm, home, factory and any movable property. That means, suppose there is a public transport bus, then the police officer can even seize a bus claiming that this might traffick people who have been clandestinely brought in.

I have an issue, especially with this one, because I come from the State of Odisha and in Odisha, we have a lot of migrant labour. I will give an example. The Economic Survey of India 2017 estimates that the magnitude of inter-State migration in India was close to nine millions annually between 2011 and 2016. While Census 2011 says that the total number of internal migrants in the country accounting for inter and intra-State is at a staggering 139 million people. The vague nature of the Bill may lead to the criminalization of all irregular migrants. Odisha might face acute problems because the Supreme Court also says that when you have anybody being paid less than the minimum wages, that is to be considered as forced labour. So, if you see the migrant labour, a lot of our labourers both men and women are brought to more economically advanced States like Punjab, where they do farm work and after the season is over – the cropping or the harvesting season is over – they go back home. But then there are middlemen who organize this in liaison with

the big farmers of Punjab. If this law is left to the mercy of the police and the courts, then there is a probability that we will eventually be nabbing and seizing the properties of the farmers, nabbing these middlemen and topping the flow of migrant labour, which is essential for even developed States. So, I do not know as to how it will be used because as I have said this many a time, and many learned Members have also mentioned it, that we merrily sit passing laws in this House thinking that our intentions are good and the good intentions will be telecast. Now, everybody is on to television. People also complain that why the camera is looking at the ...* and not looking at the ...*. So, let us say, it is telecast down at the grassroot level in a very weird and in a very perverted manner. So, we have to take an overall view of the issue now. This is a very sensitive issue and I will not have the courage to say that the Bill is wrong in its intentions or the motives of the Governments are wrong, but it is something that has been done, I will put it, haphazardly, without proper research. I will take the case of consulting the NGOs as an example. Now, I have my reservations about NGOs because in my constituency in one block called Gondia, there are something like 9,700 odd NGOs. So, I am very scared of NGOs. They will show all the MGNREGS work, take pictures, take videos, bring some people there and send it to an organization, I do not know which organization; and get funded for that also. So, NGOs are very creepy, are very doubtful in nature. Instead, when it concerns workers, it would have been appropriate to consult labour unions and trade unions also. But unfortunately,

* Not recorded

even the list that the hon. Minister read out had no mention of trade unions being consulted because this also concerns workers. So, labour law perspective has been missing in States like Jharkhand and Odisha, which contribute to the growth of the nation not only now, but for the last 70 years as we have been independent since 70 plus years.

So, Jharkhand, Odisha, all the Eastern States have contributed, including Bihar and Bengal. Right from freight rationalisation till today, we are only giving to the country but in case of States like Maharashtra or Punjab, they are only taking. They are very humble people.

So, I would suggest that this Bill be sent to a committee and a fresh opinion be sought on this. There should be no ego issue in this. We fully support the Bill but we would like that it be fine-tuned and it be brought back again for a speedy passage in the House.

Thank you.

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): महोदय, व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 जो यहां लाया गया है, उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। समाज में समाजघातक प्रवृत्तियां हैं। पिछले कई वर्षों से, कई कारणों से इस प्रवृत्ति का विरोध करने की जरूरत थी, उस पर पाबंदी लाने की जरूरत थी। इसके लिए कानून है, लेकिन कानून का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। इस विधेयक के माध्यम से यह सारी अपप्रवृत्ति, सारी समाजघातक या समाजविघातक जो प्रवृत्ति है, उनके ऊपर सही तरीके से पाबंदी लगाकर पीड़ित लोगों को न्याय देने का काम इस विधेयक के माध्यम से हो रहा है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय जी का फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं।

महोदय, इस विधेयक की बहुत विशेषता है। सिर्फ कानून बनाने से काम नहीं होगा। कानून बनाने के बाद उस पर सही तरीके से अमल होना चाहिए। जो अपराधी है, उसे सही वक्त पर सजा कैसे मिल सकती है, ताकि भविष्य में इस प्रकार का काम न हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी तैयारी इस विधेयक के माध्यम से करने का काम सरकार के माध्यम से हो चुका है।

महोदय, अगर आप खासकर मुंबई आते हैं, तो आपको यह दिखाई पड़ता है कि एयरपोर्ट में उतरने के बाद सीधा सीएसटी तक, चाहे रास्ते से जाइए, चाहे रेलवे से जाइए, हर एक रास्ते पर, नाके पर, रेलवे स्टेशन पर, चाहे गेट वे ऑफ इंडिया हो, चाहे कोई दूसरी अच्छी जगह हो, कहीं भी जाइए, वहां बड़ी संख्या में ऐसे भिखारी लोग और बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। असलियत यह है कि मुंबई में भीख मांगने वाले जो सारे भिखारी बच्चे होते हैं, वे कोई गरीब घर के नहीं हैं। मुंबई में ऐसे गैंग रहते हैं, जिनका काम है ऐसे बच्चों को भगाना, पकड़ना, उनको लेकर जाना और उनके ऊपर अमानुषिक अत्याचार करना, उनको पूरी तरह बर्बाद करके छोड़ना और उनको भीख माँगने के लिए तैयार करना। 10-10 भीख माँगने वाले बच्चों के ऊपर एक आदमी रहता है और इस तरह से उसकी एक टीम बनाई जाती है। 10-15 बच्चों के ऊपर निगरानी करने के लिए एक सुपरवाइजर रहता है। उस सुपरवाइजर के ऊपर एक बॉस और रहता है। मुंबई की कई झुग्गी-

झोंपड़ियों में जेबकतरों के बॉस होते हैं, भीख माँगने वाले बच्चों के बॉस होते हैं। गैंगस्टर के तो बॉस हैं ही। गरीब बच्चों को जो पैसे की मदद करते हैं, उनके पास से पैसा इकट्ठा करना उनका काम होता है। मान लीजिए 100 रुपये कमाए, तो 100 रुपये में से 2 रुपये भी ऐसे बच्चों को खाने के लिए नहीं देते हैं। सारा का सारा पैसा उनसे खींच लेते हैं उनके मुकादिम और उनके ऊपर रहने वाला बॉस। इस तरह से वे क्रूरता करते हैं। अगर मानवता की क्रूरता कहीं पर देखनी है, तो मुंबई में भीख माँगने वाले जो बच्चे हैं, अगर उनकी जाँच करें, तो आपको मालूम होगा कि भगवान की कृपा से उनको यह मानव देह मिली, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसे बदमाश लोगों की वजह से उनको रास्ते पर भीख माँगने की मुसीबत आई।

भीख माँगने पर कमाया हिस्सा नहीं मिलता है। महाराष्ट्र और देश के अन्य हिस्सों में अनाथ आश्रम हैं, बाल आश्रम हैं। सांसद अरविन्द सावंत ठाणे जिले के कई ट्राइबल एरिया में हर वर्ष जाते हैं, श्रीकांत शिंदे जी और राजन विचारे जी, हर वर्ष ट्राइबल एरिया में जाकर गरीब, आदिवासी और ट्राइबल लोगों की कुछ न कुछ मदद करने का काम करते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है। ट्राइबल एरिया में जो भी अनाथ आश्रम हैं, बालिका आश्रम हैं या स्कूल हैं, वहां जो बच्चियां हैं, उनका जीवन सुरक्षित नहीं है। मैं सभी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जब ज्यादातर बाल आश्रमों में जांच होती है तो मालूम होता है कि बारह-तेरह वर्ष की बच्चियां प्रेगनेंट हैं। बालिका आश्रम होने के बावजूद वहां पुरुष अधिकारी रहते हैं, उस पर पाबंदी लगाने की जरूरत है। इस विधेयक में इसे समाहित कर चुके हैं। आज महाराष्ट्र के सभी जिलों में ऐसी दुर्व्यवस्था है, गरीबी के कारण दलाल उनको पकड़ते हैं, गरीबी के कारण ये बच्चा और बच्ची उसके शिकार बन जाते हैं। उसे नौकरी लगाने का आश्वासन देते हैं या उनके घर के लोगों को हजार-दो हजार रुपये देते हैं। बच्चा-बच्ची को कब्जे में लेकर मुंबई लाते हैं, देश के अन्य प्रांतों में भी ले जाते हैं। कभी-कभी इन्हें देश के बाहर भी भेजने का काम करते हैं। कोई इलेक्ट्रिशियन होता है, कोई आईटी होता है, कोई इंजीनियर होता है। मुंबई में काम करने वाली एजेंसियां हैं, उसकी भी जांच करने की जरूरत है। नौकरी के बहाने परदेश भेजने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं, उसके माध्यम से पढ़े-लिखे या

टेक्नीकल लोगों को नजदीक लाया जाता है। उन्हें कहा जाता है कि होटल में नौकरी लगाएंगे, कंपनी में लगाएंगे, इतनी तनख्वाह देंगे। दुर्भाग्य की बात है कि यहां का आईटी इंजीनियर परदेश में जाकर शौचालय साफ करने का काम करते हैं। उसको खाना नहीं, पीना नहीं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं, उनका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, हिसाब का कुछ पता नहीं। यहां का जब कोई इंजीनियर वहां साफ करने का काम करता है तो इस दुर्व्यवस्था को रोकने के लिए सही कानून की जरूरत थी। इस बिल के माध्यम से कानून की बहुत बड़ी व्यवस्था हो चुकी है। मैं इस बिल की विशेषता के बारे में थोड़े शब्दों में कहना चाहता हूं कि तस्करी और दुर्व्यापार करते वक्त जबर्दस्ती मजदूरी, बाल मजदूरी के खिलाफ कानून बना। चाय का ठेला हो, वड़ापाव की दुकान हो, समोसा या कुछ खाने की दुकान हो, भाजी बेचने वाले व्यापारी हों, उनके पास आठ-नौ वर्ष के बच्चे काम करते हैं। हमारे ठाणे जिले के ट्राइबल एरिया में ईंट-भट्टा बनाने का व्यापार होता है। ईंट भट्टा बनाने वाले कारखाने में चार साल के बच्चे से काम कराते हैं, तनख्वाह पांच रुपये देते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं देते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो उन्हें चाबुक से मारते हैं, ऐसी हालत रहती है। इस विधेयक में जो लोग ऐसे बच्चों से जबर्दस्ती करके दुर्व्यापार करेंगे, जो लोग उनको सपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर भी पाबंदी लगाने का काम इस विधेयक के माध्यम से हुआ है।

अपराधियों को पकड़ने का काम हमेशा होता है। दुर्व्यापार करने वाले लोगों को जेल भेजते हैं, चार वर्ष के बच्चे से काम कराने के बावजूद ऐसे लोगों पर मुकदमा नहीं चलता, उनको सजा नहीं होती, इस विधेयक में समयबद्ध तरीके से लागू करने की व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो इसमें प्रावधान किया है। पांच से दस वर्ष तक सजा है लेकिन एक ऐसी घटना होने के बाद एक वर्ष के अंदर इसके ऊपर कानून का निर्णय होना चाहिए, न्यायालय की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए ताकि इस विधेयक का असली उपयोग हो सके। जो देश की गरीब बच्चियां हैं, बदमाश लोग उनसे दुर्व्यापार कराते हैं, उनके ऊपर कानून का जबर्दस्त दबाव रहे।

SHRI MUTHAMSETTI SRINIVASA RAO (AVANTHI) (ANAKAPALLI): Hon. Deputy Speaker Sir, I rise to support the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018. As we all know, trafficking in human beings is the third largest organised crime violating the basic human rights. There is no specific law so far to deal with this crime. Accordingly, the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill 2018 has been prepared. The Bill addresses one of the most pervasive and invisible crimes affecting the most vulnerable persons especially women and children.

First of all, I suggest there are so many laws that were enacted in this country since Independence. But our society has failed miserably to protect the rights of women and children. I feel prevention is better than cure. Socio-economic issue is the first reason for trafficking of women and children. It is because of poverty; it is because of lack of education; and lack of awareness in society that people are coming into this life. For example, there is a law prohibiting dowry. Nobody is allowed to take dowry in this country. But the majority of the people in this country are taking and giving the dowry. So, when our late Chief Minister Shri NT Rama Rao banned the consumption of liquor in the erstwhile combined State of Andhra Pradesh, unfortunately, our people used to bring the liquor from the surrounding States like Karnataka, Tamil Nadu and Odisha.

The hon. Minister is going to form a National Anti-Trafficking Bureau. What I want to say is that at least the head of this Bureau should be a strong person like Smt. Kiran Bedi. Even if you appoint a male person to head the

National Anti-Trafficking Bureau, it is of no use. The new law will make India a leader among South Asian countries to combat trafficking. Trafficking is a global concern affecting a number of South Asian nations. Amongst them, India is now a pioneer in formulating a comprehensive legislation. UNODC and SAARC nations are looking forward to India to take a lead by enacting this law.

The Bill has been prepared in consultation with line Ministries, Departments, State Governments, NGOs and domain experts. I thank the Minister for incorporating in the Bill a large number of suggestions received by the Ministry of Women and Child Development through hundreds of petitions.

Sir, recently, we have passed a Bill and formed the Nirbhaya Act. I do not know after passing the Nirbhaya Act, whether really the crimes have been stopped or not.

This Bill addresses the issue of trafficking from the point of view of prevention, rescue and rehabilitation. There are various forms of trafficking like forced labour, begging, trafficking by administering chemical substance or hormones on a person for the purpose of early sexual maturity, trafficking of a woman or child for the purpose of marriage or under the pretext of marriage or after marriage.

The Bill prescribes punishment for promoting or facilitating trafficking of persons which includes producing, printing, issuing or distributing unissued, tampered or fake certificates, registration or stickers as proof of compliance with the Government requirements or commits fraud for procuring or facilitating

the acquisition of clearances and necessary documents from the Government agencies.

The Bill provides for the confidentiality of victims/ witnesses and complainants by not disclosing their identity. Further, the confidentiality of the victims is maintained by recording their statements through video conferencing. This also helps in trans-border and inter-State crimes.

Time bound trial and repatriation of the victims within a period of one year from the time the crime is taken into cognizance is also there.

The Bill prescribes for the immediate protection of rescued victims and their rehabilitation. The victims are entitled to interim relief immediately within 30 days to address their physical, mental trauma etc. and further appropriate relief within 60 days from the date of filing of charge sheet.

Rehabilitation of the victim which is not contingent upon criminal proceedings being initiated against the accused or the outcome thereof. This is a very good provision.

Rehabilitation Fund is being created for the first time. Let this Fund also not remain unutilized like the Nirbhaya Fund. This fund would be used for the physical, psychological and social well-being of the victim, including education, skill development, healthcare, psychological support, legal aid, safe accommodation, etc.

I welcome the provision of designated courts in each district for the speedy trial of the cases. The Bill creates a dedicated institutional mechanism

at the district, State and Central level. These will be responsible for prevention, protection, investigation and rehabilitation work related to trafficking.

The National Investigation Agency (NIA) will perform the task of Anti-Trafficking Bureau at the national level present under the MHA. I have my apprehensions whether the National Investigation Agency would be able to take upon itself this much load of work.

Punishment ranges from rigorous minimum 10 years to life and a fine of not less than Rs.1 lakh. I think the fine is very less. In fact, it should be raised to Rs.5 lakh. In order to break the organised nexus both at the national and international level, the Bill provides for the attachment and forfeiture of property and also initiation of criminal proceedings.

Also, the Bill comprehensively addresses the transnational nature of crime. Of course, the National Anti-Trafficking Bureau will perform the functions of, at the international level, coordination with the authorities in foreign countries and international organisations; international assistance in investigation; facilitate inter-State and transborder transfer of evidence and materials, witnesses and others for expediting the prosecution; facilitate inter-State and international video conferencing in judicial proceedings, etc.

Since the Bill, once enacted by Parliament, would make India a leader among the South Asian countries to combat trafficking, I wholeheartedly welcome it. The intention is good and we support the Bill. But it is better if it goes to the Standing Committee to improve upon its effectiveness.

Thank you, Deputy Speaker, Sir, for giving this opportunity.

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Thank you, Sir, for allowing me to speak on the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.

As we speak, it is very sad to note that a child in this country goes missing every eight minutes and every year thousands of women, children, transgender and men are being trafficked into slavery, forced labour and prostitution on a daily basis. South Asia, with India at its centre, is the fastest growing and the second largest region for human trafficking after East Asia, according to the UN Office of Drugs and Crime. The US State Department had placed us as a tier two country in its Annual Report of 2018 because the conviction rate, investigations and prosecutions in this country are disproportionately low relative to the scale of human trafficking.

It is unfortunate this Government has been very, very silent on 1,11,569 missing children in 2016 year alone. Out of these 1,11,569 children, only 55,944 children were recovered and we have no data on the rest of the children, and the Government has never been vocal about this. I request the hon. Minister to be very empathetic to this situation and revert on that.

At this time and given the situation in this country, I truly welcome this Bill. I support this Bill on behalf of my Party, TRS for four reasons mainly. One, in our country, we never had a proper framework to prevent trafficking and we did not have a proper legal framework for protection of victims and witnesses. We did not have a framework or a time bound way to prosecute the offenders.

We also did not have a mechanism for time bound rehabilitation and repatriation of victims. This Bill promises us to provide all the four.

When we speak particularly about prevention of trafficking in persons, this really goes in concurrence with the hon. Prime Minister's idea where he has identified 115 districts and he is trying to develop the most distressed districts of the nation. So, formulating capacity building programmes can certainly empower the vulnerable population and we can prevent trafficking to a great extent. So, I certainly welcome this move.

Of course, when it comes to the protection of victims, this has never been the interest in various laws which we have.

Our learned friend, Shri Shashi Tharoor and many other hon. Members have said that we do already have certain laws which speak about the provisions of the same Bill. But they do not speak about the victims or protection of the victims as this Bill does. This Bill proposes to establish a National Anti-Trafficking Bureau which is a very, very welcome move. The National Anti-Trafficking Bureau will not only work at the national level also but will have its offices and network at the State and district level which will directly interact with the people and the vulnerable sections of society. So, this again is a very welcome move. The best part of this Bill is that the identity of the victims and witnesses will be protected with the help of the local police and officers.

Now, I come to a part of the Bill which deals with prosecution of offenders. All of us know that we have a law for each and every crime in India. We also have laws for the most heinous crimes as well. But why people are

not afraid of committing any crime is because they are never brought to justice. The cases are stuck in courts for years and year and by the time justice is rendered, it is too late. The best part of this Bill and for which I truly appreciate the hon. Minister's efforts in adding this clause in the Bill so that the offenders would be brought to justice just within one year. The designated courts are given in each and every district for this purpose. Moreover, special public prosecutors will be chosen to make sure that this process goes on very well.

Sir, a very interesting and important part is, and here the sensitive side of the Government is revealed, when the hon. Minister has allowed to provide for in-camera trial and video conferencing trial. Usually, victims and witnesses have a very sensitive kind of a situation where they cannot personally be attending the court. Allowing this trial is a true pathbreaking scenario in this Bill.

Of course, when it comes to rehabilitation of rescued victims, many of the hon. Members have said that it is again an approach of taking the victims and putting them in the State Homes. But what else can a Government do and how else does it work? This Bill has also tried to address this issue to a greater extent by involving various communities and NGOs. This is the first step. So, I believe that we should all give this Government a chance and support this Bill.

Meanwhile, I do have certain suggestions to make. The Union Home Ministry has already done a great deal of job and they do run a separate website to control this human trafficking problem. They have set up anti-human trafficking units in almost 264 districts of this country. The hon. Home Minister,

Shri Rajnath Singh is planning to increase their number to 332. So, there should be a synergy between the Women and Child Development Ministry and the Home Ministry. Since these Short Stay Homes are already set up and Anti-Human Trafficking Units are already set up, we do not need to spend more money again.

Another initiative by your honourable self is that you have also set up Short Stay Homes and Swadhar Greh across the nation and about Rs.50 crore is the budget which is given to these Swadhar Greh this year. These Swadhar Greh can also be utilized as a part of this Bill.

There is an issue, which has truly disappointed most of the people of this nation. This is a very organized crime. If they have to traffic one girl, the *mafia* lay eyes on her and waits for six to eight months to make sure that she is convinced that the boy is going to marry her and send her across. So, this is a very organized crime. So, the response of the Government should be very, very organized. It means that we have to go to the very root of the issue. Madam, I have been very disappointed because when I look at the figures, majority of the trafficked people are either sent to do laborious jobs or to the prostitution houses. Madam, your Ministry has apparently never interacted with any labour organization, where majority of the victims are sent. Madam, your Ministry has never interacted with the industry properly. So, I request that at least during framing of rules for this Bill kindly interact with the labour organizations. As Shri Tathagata Satpathy was saying, even in my city of Hyderabad I myself see a major influx of labour from various neighbouring

States like Andhra Pradesh and Maharashtra. Once this labour come in, they do not come in forcefully, they do want to come in wilfully. So, kindly look into that issue.

There is one more issue to which I want to draw your attention. Whenever a crime of drug trafficking or human trafficking occurs, many times foreign nationals are involved. This Bill does not talk about this aspect of foreign nationals being involved. So, my sincere request to the hon. Minister is to address this issue, that is, when a foreign national gets himself into this kind of a crime.

15 00 hrs

Now, I come to page number 14 – Chapter XII - of this Bill which speaks about offences and penalties. Clause 31(xi) says “by encouraging or abetting any person to migrate illegally into India or Indians in to some other country,”. This is a very draconian provision. I would sincerely urge upon the hon. Minister to kindly look into it and get it removed.

Thank you so much.

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Deputy Speaker, Sir, I support this Bill with a request to refer it to the Standing Committee for a better legislation.

Trafficking of human-beings is the third largest organised crime in the world violating the basic human rights. About ninety per cent of the trafficking problem in India is internal. Vulnerable groups are lower caste dalits, members of tribal communities, women, children and migrant workers. Home Minister, Shri Ranjnath Singh, had said on 7th October, 2015 that 'it was shocking that people are sold like cattle stock and bonded labour and it is still rampant in India.' Our Home Minister told how grave the situation is.

There are so many Acts, legislations and laws in India to combat trafficking, but every year, trafficking is increasing. Now, it has attained a multi-dimensional character. In 2012, the number of cases registered was 3,554 and in 2016, the number of cases registered was 8,132. There has taken place a big jump in the figures.

In the Statement of Objects and Reasons of the Bill, it is said that this is primarily fuelled by poverty, illiteracy and lack of livelihood options. Then, the Government must confess that poverty, illiteracy and lack of livelihood options are increasing in our country every year. At least, it exists in our country in a huge number. So, if we want to stop trafficking, we should try to eradicate poverty and illiteracy. It is a shame to our country when we are going to celebrate 75 years of our Independence in 2022.

Now, I come to some of the clauses of the Bill. The biggest lacuna in the Bill is the absence of a comprehensive definition of 'trafficking'. Trafficking for the purpose of a forced marriage is not included in this Bill. In clause 31(v), it is mentioned in the form of trafficking for a marriage, but forced marriage is not mentioned. In clause 34, it is mentioned that the owners of the places and conveyance used for trafficking will face rigorous punishment. There is a chance of misusing this clause. It is hard to prove a place used for trafficking, knowingly or unknowingly. How will the conveyance owner be liable, if it is a bus or a rented taxi? Parents' home may also be treated as a place of exploitation and be sealed. There is a chance of this kind of happening also.

In clause 10, the responsibility of anti-trafficking unit at the district level and the officer in-charge of the concerned police station is mentioned, especially in sub-clause 10(3). Here, the role of the officer in-charge of the police station is very crucial, but I am sorry to say that in many cases, role of OC or IC is not helpful. OC will register the FIR under Section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, but some of the officers misbehave with the victims and do not want to register the complaints initially. When some organisations or political parties come in favour of such victims, only then the case is registered by the police. So, in this Bill, there must be some provision of instant punishment to such police officers.

So far as protection and rehabilitation is concerned, the system of licencing the protection homes, special homes as well as placement agencies has been placed most casually. Sometimes, these homes are the sources of

trafficking and immoral work, instead of putting a check on the crime. It must be addressed in this Bill.

Women who are victims of commercial sexual exploitation may not be able or willing to come out of it, but they are not necessarily offenders. The law must protect their basic human rights in the matter of health and education of their children and civic documentation, such as Aadhar, and ration card. Acknowledge the critical role of NGOs to support and collaborate in combating trafficking.

I have two suggestions finally. There is a lack of awareness among the poor people about trafficking. Those who are trafficked are not aware of it and the children are also not aware about it fully. I have a suggestion towards this. We have to create awareness among our children at the school level through teachers and special educators. If we can do it, it will prevent trafficking. Please set up a legal assistance committee with the help of lawyers to help the victims. You can do it at least at the sub-divisional level. Then, it can be prevented.

Finally, I draw the attention of the Minister towards clauses 9 (1) and 9 (2). Both these clauses are the same. I do not know as to why we need two similar paragraphs.

With these few words, I conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you Mr. Deputy Speaker Sir. On behalf of my Party I stand here to support this Bill. Obviously, I do not think anybody in this House would oppose this Bill because it is in the interest of the nation, of our children and women.

I was going through some very alarming data from the Home Ministry. It said that the number of persons arrested for trafficking was 10,000; the number of persons chargesheeted was 7,292; and the number of persons convicted was only 159. As we are all aware, this is not a political issue. This is a social issue. I appreciate the Ministry's intervention in bringing this very important Bill. But I only have a few concerns about this Bill because it is about human trafficking. When anybody is trafficked, it is merely a compulsion on that person. It is not out of somebody's will. The intent of the Government is very noble of giving so much authority to the police, which is much appreciated. But I would like to know how this entire administration of a district will be done. In the Bill there is a talk about anti-trafficking unit. Will they use it for emotional quotient? Will this be a normal police who will be a part of anti-trafficking units? Will they be aware of the sensitivity of the issue? Women who have been through trafficking go through a lot of mental trauma. Will there be an NGO, which has been mentioned? What kind of NGOs? It is because in other issues, like adoption, a lot of wrongdoing has happened. The intent is very good. Nobody wants any child to be adopted wrongly. In adoption what has happened is in every District Committee, there are two NGOs. In that Committee, there are some NGOs who are involved in adoption. So, it

becomes a big racket. So, the person who gives children for adoption is on the Committee. So, the Collector is on his side and he is the final authority. So, a lot of wrongdoing happens in adoption. I hope the same thing does not happen here. Sitting in Delhi we make legislation for the whole country. But the implementation bodies are going to be States. So, the noble intention of the Minister and the Ministry may be very good. But on the field, is there going to be some police sensitisation being done about this? It is because the police throughout the country may not be aware of what really the intent of this Bill is.

Actually I hang my head in shame while giving this example. But in Maharashtra, when a woman went to the police station, she was exploited by one of the police officers. So, in such a ghastly situation, are they the only authorities to do this? This is an isolated example. It does not mean all the police are bad. But I think these are little loopholes that we must cover and see how more we can strengthen the trafficking laws. She has extensively talked about rehabilitation, which is a very welcome move. Only yesterday Shrimati Ranjeet Ranjan talked about what happened in a home in Bihar, what happened in Jharkhand over conversion. These are very complex social issues. What happened in Jharkhand and Patna last week are not political issues. So, how do we integrate these things because in every place a legislator cannot be there? How do we make everybody accountable? There has to be a message on top which says we are going to have zero tolerance towards trafficking and it has to be done in a very fair and transparent manner.

As regards rehabilitation, the fund that she has talked about is a very small fund for a size of this nation. Are the States going to contribute to it or will there be enough funds to get counsellors? Okay, she is confirming that there will be. So, I welcome that step if everywhere we are going to get good and qualified counsellors. But is India ready for such a good counselling? Who are going to be the counsellors? Who is going to choose them? If she could throw a little light so that we could feel more comfortable and rest assured that the intent is very good.

As regards the big issue of transgender, it is not an issue that is so easily discussed in this House. I worked very closely with transgenders for several years. Especially, in Mumbai, we have very large issues of transgenders. Now, there is nothing really openly said about them. Would the hon. Minister kindly address the issues of transgenders as to how they will be protected? I am asking this because they are completely left out.

Further, please do not call them 'others'. It is my humble request to you. It has to be a 'male', 'female' and 'tg'. It would be a little kind if you do not call them 'others' because they are not 'others'. So, I would appreciate that, and I am sure that she will look into it.

As regards the other issue of social integration, if somebody is trafficked and brought back, then you will give her a fair hearing. How will you socially integrate her or him back into the society? It is easy for 'him' to integrate in the society, but it is very hard for a woman to get socially integrated back into the society.

Why does this all happen? It only happens because of economic situations. Especially, there is a very good example in Goa. There is a very good NGO who has brought all the sex workers together in Goa, and they run a very fine laundry where they are making so much money that no woman really wants to become a sex worker any more, and no woman wants to be a sex worker. This is not something that she does out of choice. She does that either to feed her children or to protect her family. Why else would she do it? If the hon. Minister could do something even for sex workers, then I think it will be much appreciated.

The Bill talks about jurisdiction of the Magistrate inter-State. If you could kindly clarify how it would work inter-State. If somebody is caught in one State and sent back, then how will the jurisdiction work? So, there should be nothing grey left about it.

Many people have talked about how we would cover issues, which are abroad. I would not repeat them, but there is one question that I would ask the hon. Minister to kindly clarify. She has talked about surrogacy and child marriage. One question was human body exploitation. We see kidneys being robbed, and so many such things. If she could kindly clarify for our satisfaction as to what would be the thinking on this issue.

Now, adoption and surrogacy are the new trends in society today. So, when a child is adopted, will we be 100 per cent sure that the child is not trafficked from any home, any place or even abroad for that matter?

The District Administrator and the Magistrate has been given a lot of importance. Adoption is mainly done through courts so far. She has given a lot of authority so that the paperwork becomes much less. Hence, I appreciate and respect her intent, but I would like to know this. Our District Administrators already have a big administrative set up. Will he or she have enough time to devote to these issues? I am asking this because these are very sensitive issues. If the hon. Minister could give us a broad view on what you think about this issue.

Lastly, I would like to make a point where, in Maharashtra, we have a very good success story about this. Pratham is one of the largest organisations in Maharashtra, which is an NGO that the whole country refers to and we often report for education. They did a very fine programme with the Home Minister, Mr. R. R. Patil, who, unfortunately, is no more the Home Minister. We made several shelters for children and we brought down child labour and trafficking substantially in Maharashtra. So, it has been one of our success stories, and all Governments after that have followed it. Could we do a programme like this where we could call a very refined NGO to work with the Home Ministry and Ministry of Women and Child Development to really make a difference? Can we make sure that every child and woman is protected, and we feel as a proud nation where we can say that? Yes, trafficking was a history and it does not exist in our country anymore. Thank you very much.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA (ARAKU): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak on the most important legislation pertaining to human trafficking.

15 14 hrs

(Shri Ramen Deka *in the Chair*)

The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 is quite illustrative and certainly designed to curb the social evil of trafficking. I wholeheartedly appreciate the Ministry of Women and Child Development and the hon. Minister who has put in special efforts and conducted various consultations with domain experts and civil society organisations in drafting this Bill.

The Bill incorporates prevention, rescue and rehabilitation for various aggravated forms of trafficking like forced child labour, forced marriage, sexual exploitation, organ trade, forced surrogacy, forced begging, etc.

I feel that for the first time it has given clarity to the term 'trafficking' in the Indian history. This subject is very close to my heart as day in and day out we keep listening to many stories of exploitation of women and children. Sometimes I feel very upset about the current situation as the present law is not stringent. We finally end up in punishing the sufferers leaving the actual culprits.

Human trafficking is the third largest organized crime, as some of my colleagues have stated, after drugs and the arms trade across the globe. The 2016 NCRB statistics suggest that 8,132 cases of trafficking were reported across the country, with the number of victims rescued being 23,117. Sir, 45

per cent of these victims were trafficked for the purpose of 'forced labour', and 22 per cent for 'sexual exploitation for prostitution'.

At this juncture, I would like to draw the attention of the august House to an article published in "The Hindu", a full page article called "Araku Valley's Dark Secret". This is my constituency, Araku. It pertains to the trafficking of women and children from the tribal areas to New Delhi, Goa, Mumbai, Bangalore and Hyderabad. This is being done in an organised manner for a long time. Most of these women who are being subjected to trafficking are minors and their stories are heart touching. I could not stop the tears in my eyes reading their stories. I was quite anguished with the situation; I met some officers; I tried to actually address this issue but it resulted in vain. Nobody took serious cognizance of this crime which has been going on in an organised manner

This Bill goes a step further in addressing the issues of trafficking from the point of view of prevention, rescue and rehabilitation. It has also defined "aggravated" forms of trafficking, which includes trafficking for the purpose of forced labour, begging, trafficking by administering chemical substance or hormones on a person for the purpose of early sexual maturity, trafficking of a woman or child for the purpose of marriage or under the pretext of marriage or after marriage, etc.

Recently, I have attended a Conference of Survivors of Trafficking from almost six to seven States, organised by the Prayas, an NGO. The survivors have narrated their stories in the Conference; they are very heart touching;

survivors have explained their pathetic heart touching stories. They have been subdued by the people who are actually involved in these types of organised crimes, and they feel that these people who are actually involved in these organised crimes escape without any punishment. Survivors are subjected to a lot of punishment. Delivery of justice in time is one of the major issues. Some cases have been going on for years together. Victims lose their lives while attending the court proceedings. When someone wants to marry, they are not able to do so because they are subjected to court cases; they have to attend the court proceedings and nobody comes to their rescue. So, I fully appreciate the 90-day time frame for completion of investigation and strong mechanisms for rehabilitation of victims. This clause must be emphasised and ensured so that it will be implemented in true spirit.

I appreciate the move to constitute a Rehabilitation Fund which would be maintained and monitored by a high level National Anti Trafficking Relief and Rehabilitation Committee. At this juncture, I would like to request the hon. Minister, through you, this. Clause 13(2) says that the District Anti Trafficking Committee shall consist of the following, namely, the District Magistrate as the Chairperson. But I would like to request the hon. Minister that the Member of Parliament should be the Chairperson of this Committee because this is mostly a social evil. We, as the representatives of the people, will be able to take this issue forward, create awareness in the society. We will be more helpful in creating an impact.

It is also a welcome step to delink rehabilitation from criminal proceedings and enable extension of rehabilitation services to the survivors whose criminal proceedings fall through for no fault of their own and who may not wish to participate in criminal proceedings at all.

Protection of victims and witnesses is also a prerequisite to deliver justice. The Bill in its very procedure maintains the confidentiality of the victim which I truly appreciate. The designated court may record the statement of victim through video conferencing in any case where the victim is unable to appear before the court for the reasons of safety or confidentiality.

To conclude, the provisions listed in the Bill are very important and the enforcement of this legislation will curb the menace of trafficking in India which is a social evil and which is affecting the lives of millions of citizens.

SHRI DHARAMBIR (BHIWANI-MAHENDRAGARH): Sir, I have gone through the entire text of the Bill. I support the Bill in general but I have some very important basic points to make.

Sir, nobody goes into trafficking and prostitution willingly. The very fact is that one per cent of Indian corporates owns 73 per cent of India's total wealth. Every day, more and more people are being thrown into penury, exploitation and very destitute state every year. In this situation, it is this vulnerable section of the society which is compelled to go into this type of trafficking and prostitution.

If we are really to fight out this menace, we have to create a very equitable society so that nobody goes into these dirty jobs by compulsion.

Secondly, if the Government is at all sincere about tackling this problem, my first suggestion is that lakhs of children who have disappeared during last ten years should be considered as having gone into trafficking and should be investigated and the cases should be registered. Every case should be investigated on the lines of trafficking. All the inmates of brothel houses should be investigated and these gangs should be busted which buy them and bring them to the brothel houses. It is not today's problem. This problem has been there for decades.

Thirdly, as regards the implementation and rehabilitation programme, the record of the Government is not very clear. I have seen One Stop Centres and Rape Crisis Centres, they are not being taken care of properly in my city of Patiala, not much funds have been released and not proper centres have been

established. I request the Government to be sincere on rehabilitation programme.

Lastly, my point is about the unhindered powers are given to the police and the bureaucracy. There are chances that the powers may be misused for political vengeance. I think that all steps should be taken, the Bill should be sent to the Standing Committee and all precautions and measures should be taken so that this Bill is not used against any particular opponent.

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली) : महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पर बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। व्यक्तियों की तस्करी, मानवदेह व्यापार के विरोध में जो कानून बना है, यानी इसकी रोकथाम के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए तथा पुनर्वास के लिए जो कानून बना है, मैं उसके पक्ष में चर्चा करने के लिए खड़ी हूँ।

मैं माननीय मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी जी को बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने दबी, कुचली आवाजों को सुना और उन दबी, कुचली आवाजों को इस संसद के सदन तक लाने के लिए जो विधेयक पारित करने की माँग की है, वह समयानुसार बिल्कुल सही है। इस तस्करी की रोकथाम, बचाव और मानव तस्करी के शिकार जो व्यक्ति हैं, उनके पुनर्वास की देश में कोई व्यवस्था नहीं थी। यौन शोषण के व्यापार में अगर हम बुनियादी स्तर पर देखें तो जिसको मॉडर्न जिन्दगी के अंदर मॉडर्न स्लेवरी का नाम भी दिया जा सकता है, उनके साथ बिल्कुल दासों जैसा व्यवहार किया जाता है। बलपूर्वक, बहला-फुसलाकर उनको ऐसे काम करने पर मजबूर किया जाता है, जो कि वह व्यक्ति अपने होशो-हवाश में कभी नहीं करता।

अगर हम ग्लोबल आंकड़ों की बात करें तो उसके मुताबिक 70 से 80 प्रतिशत तक जिन लोगों को इस व्यापार में धकेला जाता है, उनमें ज्यादा से ज्यादा केसेज देह शोषण के हैं। Trafficking for labour, trafficking for other purposes also happens but 70 to 80 per cent cases are of sex trafficking, trafficking for the purposes of gratifying human beings through sexual offences. About 50 per cent of people who are pushed into this act are children. The House has been discussing the issue of lynching for some time. If you look at the data in detail you will come to know that there has been a rise of about 30 per cent in child abduction cases. देश में ऐसे केसेज की संख्या 30 प्रतिशत बढ़ी है। यह संख्या उन बच्चों की है, जिन्हें बहला-फुसला कर, घर से भटका कर ले जाया जाता है। इन तमाम केसेज के अन्दर जो चार्जशीट है, वह केवल 40.4

प्रतिशत केसेज में ही दाखिल होती है। उन 40.4 प्रतिशत केसेज में से भी जिन केसेज के अन्दर कन्विकशन है, वे केवल 22.7 प्रतिशत है। हर एक लाख में से 24 बच्चे इस तरीके की दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं और ऐसे में उनका बचपन खराब किया जाता है। इस प्रकार से मानव अधिकार से वंचित जो शारीरिक शोषण है, उसके खिलाफ हम सब यहां एकत्रित हुए हैं। मुझे लगता है कि इस हाउस का हर व्यक्ति इसके विरोध में है। अमानवीय यातनाओं से जो करोड़ों-करोड़ बच्चे-बच्चियां अपना खोया हुआ बचपन आज़ादी के साथ तलाशना चाहते हैं, उनके रिहैबिलिटेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं था। मुझे लगता है कि जन-प्रतिनिधियों से, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबके क्षेत्र से और पूरे देश की हम से यही इच्छा, आकांक्षा और प्रश्न होगा। उसके लिए कुछ लाइनें हैं नज़ीर अक़बराबादी की, जिसे मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ –

“किधर छुपे हो, जरा मुँह तो हमको दिखलाओ,
हमारे हाल के ऊपर भी कुछ तरस खाओ,
सबों से सुनते हो, हर एक से कहते हो आओ
हम सब लोग लोगों को इंडाइट करते हैं, पूछते हैं।

सबों से सुनते हो, हर एक से कहते हो आओ,
खुदा के वास्ते जीने की राह बताओ,
हमें भी कहनी है, कुछ तुमसे बात - कोठे पर।”

ये जो बचपन है, ये जो लड़कियां हैं, ये जो मासूमियत के चेहरे हैं, जो कोठे पर धकेल दिए जाते हैं, आज हम सब उनके पक्ष में खड़े हुए हैं, उन मासूम जिंदगियों के पक्ष में, जो मानव तस्करी की शिकार हो रही हैं। इस सदन में बैठे हुए लोग समाज के जिम्मेदार लोगों से ज्यादा कहीं अधिक जिम्मेदार हैं क्योंकि देश का कानून बनाना हमारा केवल अधिकार ही नहीं है, बल्कि कर्तव्य भी है। इसलिए हमें इसमें जहां-जहां गैप्स दिखाई देते हैं, जहां-जहां हमें लगता है कि ये सुधार समाज में होने चाहिए और समाज के सुधार को हम कानून-व्यवस्था के अन्तर्गत ले आएं। उसी गैप्स को भरने के लिए यह कानून-व्यवस्था बनी है और हम सब उसी काम के लिए यहां पर खड़े हैं और यह हमारा फर्ज बनता है। उसी फर्ज को आगे बढ़ाते हुए लॉमेकर्स होने के साथ हमें ऐसे सख्त कानून

बनाने की जरूरत थी, जिसमें जो लोग मानव तस्करी से जुड़े हैं, उन्हें सख्त-से-सख्त सजा मिले साथ ही, उनके मन में वह दर्द भी है, जो उन मासूम चेहरों को देखते हैं कि उन्हें रिहैबिलिटेड किया जाए।

शशि थरूर जी अभी सदन में नहीं हैं, लेकिन इससे पूर्व उन्होंने एक बात कही, जिस पर मुझे लगा कि मुझे उस पर टिप्पणी जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों को उनके परिवारों के साथ भेज दिया जाना चाहिए। मैं एक केस का जिक्र करना चाहती हूँ, जो कि मेरा आँखो-देखा केस है। यह आज से बीस वर्ष पूर्व का केस है। असम की एक लड़की थी और फिरोज नाम के व्यक्ति ने उसके माँ-बाप से उसे पाँच हजार रुपये में खरीदा था। उस लड़की को यह कह कर कि तुम्हारे साथ विवाह हो गया, निकाह करके उसे यहां ले आया और उसके बाद उसने उसे प्रेगनेंट कर दिया। 14 साल की बच्ची प्रेगनेंट हुई और उस लड़की को दो बार बेचा गया। पहले उसके तथाकथित पति ने खरीदा। उसके बाद उसने मेवात ले जाकर उस लड़की को बेचा। उसके बाद एक और व्यक्ति को वह हरियाणा में बेच दी गयी। उसके बाद उसका रेस्क्यू किया जाता है, उसे रिकवर किया जाता है। वह केस आया, क्योंकि वह लड़की तीन महीने से ज्यादा की प्रेगनेंट थी। जब उससे एबॉर्शन की बात की जाती थी तो वह अपने पेट पर हाथ रख कर कहती थी कि यह मेरे स्वामी का है, इसे एबॉर्ट नहीं करना है। उस लड़की ने खाना-पीना एवं सब कुछ बंद कर दिया था। जहाँ पर देह व्यसन के व्यवसाय की बात होती है, सब इसकी करते हैं; गरीबी, मजबूरी ऐसी स्थिति है जहाँ पर परिवार शामिल होता है और जब परिवार शामिल होता है तो उन परिवारों के पास उन बच्चों को कभी भी नहीं भेजा जा सकता है। ऐसे में जिस निगरानी की आवश्यकता है, उन्होंने एक और बात कही, इस देश में ब्यूरोक्रेटिक सेटअप खड़ा कर दिया है, आपने उस ब्यूरोक्रेसी को और बढ़ा दिया है। भाई, आप मुझे एक बात बताइए कि देश की सरकारी कानून-व्यवस्था क्या ब्यूरोक्रेसी के बिना चल सकती है? क्या आप और हम उनको अपने घर में रखने की जिम्मेवारी ले सकते हैं? ब्यूरोक्रेसी को तो साथ लगना ही पड़ेगा, बिना ब्यूरोक्रेसी के इन चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं है और जब ब्यूरोक्रेसी को साथ रखा जाएगा तो आपको एक व्यवस्था खड़ी करनी होगी जिसमें संसद

सदस्यों के अपने कर्तव्य होंगे, राज्य सरकारों के अपने काम और कर्तव्य हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटीज के अपने काम और कर्तव्य हैं। अगर आप आज का अखबार उठा कर देखें तो नेपाल की 16 लड़कियाँ को मुनिरका गाँव से रिकवर किया गया है, जो कि मेरे क्षेत्र में आता है। आप अंदाजा लगाइए कि वे लड़कियाँ नेपाल से चली हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस किया, झारखंड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्य को पार करते हुए वे लड़कियाँ दिल्ली पहुँची होंगी। दिल्ली उनकी फाइनल डेसटिनेशन हो सकती है और हो सकता है कि कमाटीपुरा, मुम्बई उनकी फाइनल डेसटिनेशन हो या गोवा हो। इतनी सारी इंटर-स्टेट एजेंसिज और इंटरनेशनल एजेंसिज हैं, जब तक आप उनके पीछे एक एजेंसी के रूप में खड़े नहीं होंगे, तब तक आप उस पर किसी तरीके का नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। आज उसी एजेंसी को खड़ा किया गया है, क्योंकि इसमें एनआईए और होम मिनिस्ट्री डायरेक्टली इनवॉल्वड हैं और वे डायरेक्टली इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज हैं और पैरलल सिस्टम की बात हुई तो आपको पैरलल सिस्टम इसलिए खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आज का जो सिस्टम है, वह चरमरा रहा है।

अगर देश में लेबर लॉज, जैसा उन्होंने वर्ष 2010-11 के कानूनों का वास्ता दिया कि ये सब कानून उपस्थित हैं, इसलिए आपको नए कानून की आवश्यकता नहीं है। अगर वर्ष 2010-11 का कानून तथा व्यवस्था काम कर रही होती तो वाकई इसकी आवश्यकता नहीं थी। परंतु देश के सामने आँकड़े हैं, देश के सामने समस्या है, जाहिर तौर पर आँकड़े बताते हैं कि वह व्यवस्था काम नहीं कर रही है और वह कानून अपने आप में काफी नहीं है क्योंकि कभी भी आज तक रिहैबिलिटेशन की बात नहीं हुई और इस कानून के माध्यम से स्किल ट्रेनिंग की भी बात हो रही है। आप जब तक किसी को स्किल ट्रेनिंग नहीं करेंगे, मजबूरन बहुत लोगों को इस तरफ जाना पड़ जाता है, क्योंकि उनको एक विक्टिम के तरीके से नहीं, बल्कि परपेट्रेटर के तरीके से देखा जा रहा है। अगर आप उनको विक्टिम के तरीके से देखें और उनको आल्टरनेट जॉब या आल्टरनेट एक्टिविटीज के लिए तैयार करें, तो शायद इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। यही कारण है कि इस कानून को उन सारी व्यवस्थाओं की दृष्टि से लाया गया है। इन सभी को अंजाम देने के लिए

और उन सभी दरिंदों के हौसले पस्त करने के लिए, जो इस तरीके के देह व्यवसाय में लगे हैं, इस कानून को लाया गया है।

महोदय, यह दुनिया का तीसरा ऑर्गनाइज्ड क्राइम है। उपयुक्त कानून, अनुकूल तंत्र, समर्पित पुलिस, कोर्ट की व्यवस्था जिसके तहत एक साल के अंदर इन मुकदमों को सुन कर खत्म करने की ट्रायल की व्यवस्था है और तहकीकात को भी समयानुसार सात दिन के अंदर पूरा करने की व्यवस्था है। अतः, मुझे खुशी है कि श्रीमती मेनका गाँधी जी के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पर गहन विचार किया है और विशेषज्ञों की राय लेकर एक रास्ता ढूँढने की कोशिश की। इसके लिए रास्ता ढूँढना इसलिए आवश्यक था, क्योंकि लीगलाइजेशन ऑफ सेक्स ट्रेड के लिए जो ऑर्ग्यूमेंट्स दिए जाते थे, उन्हीं ऑर्ग्यूमेंट्स को ध्वस्त किया है। आपको एचआईवी का ट्रीटमेंट करना है, आपको लीगलाइजेशन ऑफ सेक्स ट्रेड की जरूरत नहीं है। आपको रिहैबिलिटेड करना है, लीगलाइजेशन ऑफ सेक्स ट्रेड की जरूरत नहीं है। Ultimately, it cannot be a profession. Nobody wants their children to go into sex trade. If I do not want my children to go, how can I tell some body else's children to go? It is not a trade; it is not a profession and the country thinks very strongly that this is not a profession.

जहां पर यकीन होता है, कुछ काम करने का जज्बा होता है, अगर यकीन हो तो कोई न कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी तो चिराग जलता है। यह ओट लेकर चिराग जलाने की कोशिश है, रिहैबिलिटेड करने की कोशिश है।

अंत में, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जितने इसके प्रावधान हैं कि कंप्लेनेंट का नाम, विटनेस का नाम, विक्टिमस का नाम, सबकी आपको सीक्रेसी मेनटेन करनी पड़ेगी। नेशनल, इंटरनेशनल एलायंसेज को खत्म करने के लिए जिस तरीके की एक कवायद की जरूरत थी, उस पर गृह मंत्रालय ने बहुत अच्छे से काम किया है। प्रोटेक्शन, रिहैबिलिटेशन की बात हो रही है। सख्त कानून के साथ-साथ इंसानियत की गर्मजोशी मुझे इसे कानून में दिखाई देती है। इन दोनों का

सामंजस्य इस कानून में सफलतापूर्वक बैठाने की कोशिश की है। इसके लिए हम सभी एक सामूहिक प्रयास करें, तो प्रभावी हो सकेंगे।

My hon. Friend Shrimati Geetha said that it is a social evil. I completely agree with her that it is a social evil. Since it is a social evil, all of us have to combine our efforts to deal with this menace. The law will do its own job; the police will do its job; the politicians need to do their job and give a firm voice to the voices which are not heard.

Thank you very much.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity.

I will take only three or four minutes. I know the intention may be noble but the contents in the Bill are huge. It looks like an umbrella Bill but at the same time there are a lot of lacunae in the Bill. Therefore, I join hands with a lot of other hon. Members that this Bill should be sent to the Standing Committee and have an appropriate examination before being brought to the House. I am saying this because I have seen the experience of a very rich friend of mine in my own constituency.

A young lady and a woman came to his house. With the drawing of a Church, they came to ask him for some donation. As everybody knew, being a generous man, he gave them Rs. 2,50,000 for building the Church. He gave the money, tea and all in his house and sent them back home. Since they came by a taxi, he told his driver to drop them at the station. Later on, this lady and the girl were caught from a hotel. When they were caught in the hotel, interrogation started. They found that they came from his house. So, his car was seized, his driver was arrested, his house was also raided, and he was almost in jail but he got a bail. Even the DG had to resign. This is the best example of how the law can be misused. So, the knowledge which comes with examination by a Standing Committee is not there and based on this example the Minister should consider my request.

In my constituency, I have gone to many rehabilitation centres. I have found that a majority of the victims do not want to go back but many of them,

who came out of the problem and tried to work for four or five months, have been compelled to go back because of poverty and other problems. So, I think, the concerns of the victims should also be considered.

Those are the few things which I think the Minister will look into. I know, this Bill will become an Act but you would be making rules after that. The rules and regulations should be framed in consultation with the State Governments and stakeholders so that this Bill could be implemented in good spirit.

Thank you.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir.

I rise to support this Bill. While introducing this Bill for consideration, in her opening remarks Madam Minister has specifically stated that this is a historic Bill as far as prevention of trafficking of persons is concerned. It has also been suggested that this is a comprehensive Bill dealing with this matter. Madam has also made a statement in the House that wider consultation has been done.

She has said that 60 NGOs, a number of stakeholders and even Members of Parliament were consulted. We are having a parliamentary system of governance in legislation and as per the Rules of Procedure as well as the convention of this House there is a concerned Standing Committee. When the Government is consulting the NGOs, stakeholders and even MPs individually why is the Government hesitating to refer the matter to the Standing Committee so as to have a close scrutiny of the entire provisions of the Bill? This is the first question that I would like to ask to the hon. Minister through you.

This is an original Bill having 58 clauses. It is a big Bill. In one sense it is good also and I support it. A historic Bill having comprehensive legislation in respect of trafficking of persons, original Bill having 58 clauses is being consulted in the public domain but is not being consulted in the Standing Committee means that you are undermining the authority of the parliamentary Standing Committee. Why has it not been sent to the Standing Committee?

My first suggestion to the hon. Minister, through you, Sir, is that this Bill may be sent to the Standing Committee for having a close scrutiny of the entire provisions of the Bill.

Coming to the Bill, I do accept that trafficking of human beings is one of the largest organised crimes violating the human rights. To root out and eradicate the human trafficking, I definitely agree with the hon. Minister that a comprehensive legislation is absolutely essential. So, the first question which I would like to highlight is whether this Bill is sufficient to meet the situation. Mr. Chairman, Sir, my answer is, the Bill is neither comprehensive nor clear. This is the first point which I would like to make.

What does the Bill intend to do? The Bill intends to prevent the trafficking of persons, to prosecute offenders, to provide care, protection and rehabilitation to the victims of trafficking. As per the Bill, what are the forms of trafficking? Different forms of trafficking are; trafficking of persons for sexual exploitation, trafficking for physical exploitation and other forms of exploitation like forced labour and bonded labour. According to the hon. Minister and the Statement of Objects and Reasons of the Bill, in order to meet, combat or to arrest the situation, the Bill creates a conducive, legal, economic and social environment for the victims of trafficking and provides an institutional mechanism at district, State and national level for prevention, protection, investigation and rehabilitation. It also provides for the Rehabilitation Fund for the welfare of the victims of trafficking. Unfortunately, the fund earmarked in the financial memorandum is just Rs.10 crore. As Dr. Shashi Tharoor has

said, the intention and the sincerity of the Government is very clear out of it. Finally, we have the penal provision thereof, for those who commit or attempt to commit or abet the offences. This is the crux of the Bill.

Sir, my first concern with regard to the Bill is, the legislation lacks clarity as there are multiplicity of institutional mechanisms to coordinate various agencies to prevent, investigate, prosecute and provide care and protection.

Sir, I may be given time so that I can substantiate my point with regard to the multiplicity of organisations. It is within the purview of the Bill. The first institutional mechanism is the National Anti-Trafficking Bureau. Clause 3 of the Bill says that the Central Government may, by notification, establish a National Anti-Trafficking Bureau. I may be allowed to quote Clause 3 (2) and I quote:

“The Bureau shall have police officers and other officers of such appropriate rank as may be necessary. ”

Who are the other officers? It is not clear. We are talking about the National Anti-Trafficking Bureau and how vague, ambiguous its structure would be, is very clear from the ill-drafting of the Bill.

Coming to the functions, they are explicitly explained in Clause 4 of the Bill. Sir, 25 functions are earmarked and if you see there is no specific function. We have only general functions of coordination, monitoring and surveillance. If you go through the functions of Anti-Trafficking Bureau, 25 functions are earmarked but ill-drafting of clause 4 is evident. A lot of repetition is there. I am not going to explain it.

Another officer is the State Nodal Officer. We have the State Anti-Trafficking Committee, the State Police Nodal Officer, District Anti-Trafficking Committee, District Police Nodal Officer, Anti-Trafficking Police Officer, Anti-Trafficking Unit, National Anti-Trafficking Relief and Rehabilitation Committee, etc. These are full of bureaucrats. There is no clear and distinct responsibility earmarked for each agency, except saying about the coordination and assisting all these agencies.

So, my point is that there are already so many existing legislations. Most of the hon. Members have already cited about it. I am not going into it. But, one point that I would like to make here is this. There is Sections 370 to 373 of Indian Penal Code, including Section 370A which was introduced in 2003, pursuant to the recommendations of J.S. Verma Committee and it was taken from the UN Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially women and children.

HON. CHAIRPERSON : Please conclude.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : There are so many provisions. Most of the provisions in this Bill are just repetitions. I will conclude with two points in two minutes.

Sir, what is the logical basis of distinction between simple form of trafficking and aggravated form of trafficking? To me, there is no logical basis. Since there is no time, I cannot substantiate and explain.

Now, finally, I come to the general criticism about the Bill. Madam, kindly take it in a positive and in a constructive way. The Bill does not speak of a

provision where the customer or the client is punished for such trafficking. It mentions only about the party and the victim. As far as the customer or the client is concerned, there is no mention about it. The Bill is more crime-centric than human rights centric. Instead of streamlining the enforcement, the Bill intends to build institutional bureaucracy, bureaucracy by creating more than ten agencies. So, the Bill over-emphasises criminal response and does not give due consideration to the rights and needs of victims and their effective protection and proper rehabilitation.

So, once again, I submit to the hon. Minister that this Bill may be sent to the Standing Committee for having a close scrutiny. With these words, I conclude.

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): सभापति महोदय, आपने मुझे व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक पर बोलने की अनुमति दी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मैं माननीय मंत्री श्रीमती मेनका गांधी जी को बधाई देता हूँ कि इन्होंने एक अच्छा बिल समाज के लिए, देश के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए लाने का काम किया है। इससे अपराधियों पर नकेल कसेगी और उन पर कानूनी शिकंजा भी बढ़ेगा। माननीय श्रीमती मेनका गांधी जी समाज सुधारक होने के साथ ही मंत्री भी हैं। मानवों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, अधिकारों पर हमला हो रहा है। अभी तीन दिन पहले बिहार के मुजफ्फरपुर की घटना जबर्दस्त मानव तस्करी की घटना है। वह घटना हमारी बहनों-बेटियों के साथ हुई है, जिस पर सभी का सिर झुका हुआ है। बिहार में कोई शासन और सुशासन का नाम नहीं है। वहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। पन्द्रह साल और बीस साल की बेटियों के साथ सामूहिक रूप से बलात्कार किए गए, यहां तक कि उन्हें मार डालने का भी काम किया गया। जैसे कभी महाभारत में दुश्शासन के द्वारा महिला का चीरहरण हुआ था, वैसे ही लगता कि आज मां-बहनों की अस्मत् लूटी जा रही है। मुजफ्फरपुर की घटना से हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जब बिहार में ...* का राज था, ... * का राज था, ... * कहते थे, लेकिन आज वहाँ ... * और ... * साबित हुआ है। स्थिति बहुत ही नाजुक है। बिहार के सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर में नेपाल के रास्ते से बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। बेटियों ने इसे उजागर करने का काम किया है, अखबारों ने भी इसे उजागर करने का काम किया है। ऐसी जानकारी मिली है कि बड़े पैमाने पर लड़कियों को देह व्यापार के लिए जबर्दस्ती लाया जाता है, आर्केस्ट्रा के नाम पर लाया जाता है और उन्हें बेचने का काम किया जाता है। इसके इंटरस्टेट लिंक बने हुए हैं। बिहार से झारखण्ड, झारखण्ड से दिल्ली, दिल्ली से छत्तीसगढ़ तथा अन्य जगहों पर लिंक बने हुए हैं। इस तरह से यह एक राज्य में, राज्य के बाहर और राज्य से देश के बाहर तक जा रहा है।

* Not recorded

सभापति महोदय, यह बहुत ही शर्मनाक बात है। सोशल अत्याचार बढ़ रहा है, देह व्यापार बढ़ता जा रहा है, तस्करी हो रही है, घृणित अपराध हो रहे हैं। बचपन बचाओ, बेटी बचाओ, हमें बच्चों का बचपन और बेटियों को बचाना होगा। मानव तस्करी हो रही है, बाल मजदूरी कराई जा रही है, इसके लिए गरीबी भी कारण है, अशिक्षा भी कारण है, जीविका का उपार्जन भी कारण है। दिल्ली में भी भीख मांगी जा रही है, उसकी आड़ में भी गड़बड़ी हो रही है। बच्चों को विकलांग करके, अंधा करके, छोटे-छोटे बच्चों की आंख फोड़ दी जाती है, उन्हें हाथ-पैर से विकलांग बना कर लाल बत्ती के पास भीख मंगवाने का धंधा किया जाता है। मानवाधिकार हमारा अधिकार है, हमें इसे बचाना है। आज इसके लिए पुनर्वास, कानूनी सहायता देने, शिक्षा एवं अन्य तरह की व्यवस्थाएं करना बहुत जरूरी है। खासकर एससी, एसटी और ओबीसी के जो बच्चे और बच्चियां हैं, उन्हें अशिक्षा के कारण गलत ढंग से प्रताड़ित किया जाता है। उन्हें परेशानी में डाला जाता है, इसलिए आज लड़कियों की तस्करी हो रही है, लड़कों की तस्करी हो रही है। हमें बचपन को बचाना है। बाल मजदूरी अपराध है। बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में मानव तस्करी और देह व्यापार की जो शर्मनाक घटनाएं हुई हैं, उसे सदन मजबूती से विचार करे और इस पर रोक लगाए।

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I thank you for giving me this opportunity.

I rise to support the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018. This Bill is actually the need of the hour and I congratulate the hon. Minister for having brought this Bill.

Human trafficking is a deplorable human rights violation that occurs worldwide. Trafficking in persons for labour and for sexual exploitation is a form of modern-day slavery and a human rights violation that constitutes a crime against the individual and the State.

I would like to share some figures with the House here. In India, almost 90 per cent of trafficking occurs domestically in the State, inter-State and 10 per cent outside the country. As per the Crimes in India Report, 2015, which was released by the National Crime Records Bureau, there are 8132 cases reported related to human trafficking in 2016. Some States have highest reporting which include, West Bengal, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Karnataka and also Maharashtra, the State from which I come. I think this was a concern of each and every person sitting here in Parliament. Human trafficking is a very serious issue which needs to be looked at. The Government has introduced this Bill. It is really commendable and I again congratulate the Minister.

Some really good steps have been taken. One of them is setting up of a National Anti-Trafficking Bureau. The Bill seeks to establish a National Anti-Trafficking Bureau for the prevention and investigation of the trafficking of

persons' cases and protection of the victims of trafficking. Even though, law and order is under the State supervision, trafficking is intra, inter and trans-national issue. Cases consisting of different source, transit and destination points, create difficulty in providing timely justice to the victims. Thus, cases involving multiple States will be dealt with by the National Bureau only if approved by the State Police Nodal Officer. The Bureau consists of a team of police officers and other experts to ensure effective discharge of their duties. In addition to this, the Bureau would develop and monitor a database related to trafficking, traffickers and other offenders connected with trafficking or persons, which can only be accessed by the State Governments and District level Committees.

The State Anti-Trafficking Committees will be constituted to oversee the implementation of the Bill to see whether it is happening properly or not. The District Anti-Trafficking Committee would exercise the power and perform functions in relation to prevention, rescue, protection, medical care, psychological assistance, need based rehabilitation of victims and redressal of grievances.

Coming to the State and District Police Officers, one very good initiative in this Bill is that a dedicated team of police officers will be working on this issue. There is a wide range of issues that police officers will have to look at and sometimes, these issues remain side-lined. I think this is a very good step that the Government has taken in this Bill.

There are certain specific offences which are mentioned in this Bill. They are trafficking leading to mental illness or disability, trafficking for the purpose of bearing child, trafficking leading to serious injury amounting to grievous hurt or death including suicide, trafficking of a pregnant woman or resulting into pregnancy, giving narcotic drugs or psychotropic substances or alcohol for the purpose of trafficking, administering chemical substance or hormones for the purpose of attaining sexual maturity and exploitation, punishment for keeping a place of exploitation or allowing premises to be used as a place of exploitation.

Regarding Rehabilitation Fund, this Bill makes a provision to create a Rehabilitation Fund for the welfare and rehabilitation of the victims of trafficking children. Either Central or State Governments will make adequate budgetary allocation towards the Fund. Voluntary donations, contribution under CSR may be credited to the Fund and this would be made available to the State and District Anti-Trafficking Committee.

At this point, I would request the hon. Minister one thing. When we are specifying about the Rehabilitation Fund, we are not specifically saying as to how much will be the budgetary allocation for this. When we are talking about donations, we are not sure as to how much donations we will be getting. I think, we must be very specific about how much will be the Government's contribution in the Rehabilitation Fund like we have the Nirbhaya Fund which is disbursed by the Government.

One very good step is that speedy courts for speedy trials are going to be established and a stipulated time will be given even to the courts to come to a decision in such cases.

For child victims, a special procedure is going to be followed. The Bill provides for plea bargaining as per the procedure given in Chapter XXIA of the Criminal Procedure Code, 1973.

Regarding confiscation, forfeiture and attachment of property, if a person is accused of having committed an offence and possesses or owns any property, and if he is convicted, the property shall be confiscated and stands forfeited and the same may also be used by way of auction.

I would specifically give some suggestions here. I already mentioned about the Rehabilitation Fund. Secondly, the Bill is silent on prevention of re-trafficking. Trafficking is basically a syndicate and we are tackling this on case to case basis. We have also to think about this aspect. If a syndicate is being run and we are able to get hold of one person, the entire syndicate should also be looked into.

Every provision in the Bill is very good. I once again congratulate the hon. Minister of the NDA Government and I whole-heartedly support the Bill.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। यह बहुत अहम बिल है। मैं मंत्री जी को बधाई दूंगा कि इसे कानून के तौर पर देश में लाने का काम किया है, क्योंकि गैर कानूनी ढंग से तीसरी सबसे बड़ी एकटीविटी के तौर पर ह्यूमन ट्रेफिकिंग मानी जाती है। इस बिल के माध्यम से सरकार की इस विषय पर गंभीरता सामने आती है। छोटे बच्चों की सबसे ज्यादा ट्रेफिकिंग होती है। अस्पताल से, रेलवे स्टेशन और पब्लिक प्लेसेज से छोटे बच्चे ज्यादा उठाए जाते हैं और इस कानून के अंदर आप लोकल पुलिस आफिसर्स के साथ यूनिट्स क्रिएट करने की बात करते हैं। जब तक हम लोकल पुलिस को इनवाल्व रखेंगे, मेरा मानना है कि उन क्रिमिनल्स के साथ हैंड इन हैंड हो कर पुलिस आपके कदम को कमजोर करेगी।

16 00 hrs

आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि यदि हम यूनिट्स सेटअप कर रहे हैं, तो हमें ऐसे यूनिट्स सेटअप करने पड़ेंगे, जिनमें डिस्ट्रिक्ट्स से बाहर के लोग आकर इनवेस्टीगेशन करें। इसके साथ, सबसे बड़ी चिन्ता उन बच्चों की सिव्योरिटी की आती है, जो कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रहते हैं। हमने हरियाणा में देखा है, जिन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में बच्चियों के साथ निरन्तर रेप हुए हैं, उनके दोषियों को सीबीआई इनक्वायरी के बाद अब उम्र कैद की सजा हुई है। कल श्रीमती रंजीता रंजन जी ने बिहार का मामला उठाया, जहाँ उसी प्रकार के रिहैबिलिटेशन सेन्टर 'अपना घर' की वारदात मुजफ्फरपुर में देखने को मिली। आप कहते हैं कि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में मंथली विजिट्स होंगे, उनकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है।

देश में अनेक रिहैबिलिटेशन सेंटर्स एनजीओज द्वारा चलाए जा रहे हैं और उनकी गतिविधियाँ निरन्तर संशय में रहती हैं। मैं आपको बधाई दूँगा कि आपने इस काम को टाइमबाउंड करने का काम किया है। एक साल के अंदर इस विषय में फैसला दिया जाएगा।

मंत्री जी, जहां आप पैनल्टीज की बात करती हैं, आपके इस बिल का सेक्शन-40 दर्शाता है कि जो भी बच्चे का एम्प्लॉयर होगा, चाहे वह नौकर के तौर पर घर में रखने की बात हो या वर्कर के

तौर पर पब्लिक प्लेस में रखने की बात हो, ट्रैफिकिंग करने वाले आदमी को अलग से सजा दी जाएगी।

कल इसी सदन में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पास किया गया। जो रिश्वत देगा या जो रिश्वत लेगा, सभी को बराबर सजा होगी। ऐसा ही होना चाहिए। सरकार को यदि इस बिल को कारगर ढंग से लागू करना है, तो बराबर अधिकार मिलने चाहिए क्योंकि एक तरफ तीन साल की सजा देने की बात आप कह रही हैं और दूसरी तरफ दस साल सजा देने की बात कह रही हैं। यह जो डिसपैरिटी बीच में आ रही है, वह कहीं न कहीं इस कानून को कमजोर करने का काम कर रही है।

आपने सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की बात कही है कि आपके जो एटीयूज होंगे, वे सर्च एंड रेस्क्यू करके उनको चाइल्ड वेलफेयर आर्गेनाइजेशन या मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके रिहैबिलिटेशन होम में भेजेंगे। आज भी यही कार्रवाई होती है। यदि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कोई बच्चा या बड़ा व्यक्ति पकड़ा जाता है, तो उस पर इसी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होती है। जैसे आपने देश में निर्भया सेन्टर्स बनाए हैं, क्यों न इस बिल में भी ऐसे सेन्टर्स बनाने के प्रावधान किए जाएँ ताकि इस तरह की गतिविधियों को रोकने में हमारी मदद करने का काम करें।

सभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय सभापति महोदय, आपने 'व्यक्तियों का दुर्व्यापार निवारण (संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

वर्तमान में इस अपराध को रोकने के लिए कई कानूनों का सहारा लेना पड़ता है। वे कानून भी पूर्णरूपेण सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए इस प्रस्ताव के द्वारा कानून को कठोर बनाया जा रहा है, जिससे देश के अन्दर और बाहर, दोनों स्थितियों में मानव तस्करी अनैतिक व्यापार, शारीरिक शोषण को रोका जा सके। अभी हाल ही में, 46 बच्चों को अनैतिक तरीके से बेचने का समाचार मदर टेरेसा संस्थान के एक कर्मचारी द्वारा प्रकाश में आया। कुछ दिन पहले, मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर 50 से अधिक बच्चे छुड़ाए गए। देश के अन्दर यह एक आम बात हो गयी है।

इसी प्रकार से, विदेश भेजे जाने के नाम पर ठगी और तस्करी की जा रही है। यह एक संगठित गिरोह द्वारा किया जा रहा है, जो विशेषकर मुम्बई, दिल्ली, पंजाब आदि राज्यों में सक्रिय है। उसी प्रकार से, कबूतरबाजी के समाचार भी आते रहते हैं। अतः यह कानून बनने से व्यक्तियों के दुर्व्यापार पर लगाम लगेगी और पीड़िताओं की देखरेख और उनका पुनर्वास भी संभव होगा। पीड़ित व्यक्तियों के लिए सामान्य आर्थिक और सामाजिक वातावरण के साथ-साथ राहत एवं उनके कल्याण के प्रावधान हैं। विदेशों में भी ऐसे अपराध होने पर यह कानून सक्षम रूप से कार्य कर सकता है। इससे कठोर दण्ड के साथ ही, जल्द-से-जल्द मामले का निपटारा भी संभव होगा। इसमें गोपनीयता के प्रावधान भी हैं। यह कानून राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित सांठगांठ को तोड़ने में भी प्रभावी कार्य करेगा।

यह देखा जाता है कि स्थानीय स्तर पर मानव तस्करी के मामले में दलालों की मुख्य भूमिका होती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि इसके लिए एक निगरानी तंत्र बनाया जाए, जो उन दलालों पर नजर रखे और विशेषकर दलालों को कठोरतम दण्ड दिये जाएँ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ

SHRIMATI SATABDI ROY (BIRBHUM): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.

Sir, to showcase our commitment to combat human trafficking, I request the Government of India to ensure the following:

1. Time-bound procedures for rescue of victims of trafficking;
2. Empowerment of AHTUs across districts in India with authority to take on powers of rescue and investigation throughout a case cycle, to rescue, filing and registration of FIR, arrest, seizure of evidence, investigation and prosecution.
3. Protocols and funds for coordination of inter-State cases of forced labour should be made available to support officials, survivors and NGOs in inter-State transfers, including lodging and food for survivors and their dependents. Adequate police protection should also be ensured in these transfers.
4. Acknowledge the critical role of NGOs to support and collaborate in combating trafficking, including labour trafficking and bonded labour;
5. allocate adequate funding and resource for the enforcement of the new law on trafficking;
6. On 31st May, the Walk Free Foundation released its 2016 Global Slavery Index, which claimed that there were 45.8 million 'modern slaves' around the world, of whom 18.3 million were in India
7. The proposed law does little to remove India's shame of 'modern slavery'. It is a photocopy of a western approach.

मैंने स्टैंडिंग कमेटी की वजह से दो-चार जेलों में विज़िट की। वहां मुझे बहुत सारे बांग्लादेश के लोग मिले। वहां जेलों में बच्चे छह साल की उम्र तक अपनी मां के साथ रह सकते हैं। उसके बाद वे वहां नहीं रह सकते। उस समय बहुत सारी माएं मेरे पास आई थीं, जिनके बच्चे पता नहीं कहां हैं। वे बच्चे किस एन.जी.ओ. के पास हैं, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं मालूम। उनके पास कोई सपोर्ट नहीं है, जिससे वे आपके पास आ कर अपनी बात बता सकें। यदि आप कभी जेल में जाएंगे, तो डिप्रेशन में आ जाएंगे। वहां सात साल, दस साल से ट्रायल ही चल रहे हैं, जिनका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। वे लोग आपके पास नहीं आ सकते हैं।

मैं एक बात और बताना चाहूंगी। आप सबको मालूम है कि, it is a very big racket. एन.जी.ओज़. होम्स और पुलिस भी इनके साथ जुड़े होते हैं। एक बच्चे को लाने से इन लोगों को 700 रुपये मिलते हैं। ये लोग इसके लिए ये सब करते हैं। मैं अडॉप्टेशन के बारे में भी एक बात बोल सकती हूँ। इसके लिए रूल्स एण्ड रेग्युलेशंस बने हुए हैं, लेकिन जो लोग क्राइम करते हैं, वे निकल जाते हैं। जो लोग सचमुच इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, वे लोग इतनी फाइल्स और रूल्स के कारण पहुंच नहीं पाते हैं। जब बच्चे बड़े हो जाएं, तो उनके अडॉप्टेशन का कोई मतलब नहीं है। कितने लोग बच्चों के लिए तरसते हैं। ये रीहैबिलिटेशन की बात बोल रहे हैं। चाहे वे बच्चे पांच महीने के बाद घर आए या पांच साल बाद घर आए, घर उन बच्चों को सोसायटी की वजह से एक्सैप्ट नहीं करते हैं।

मैं यह मानती हूँ कि रूल्स, लॉ और कानून में से कुछ भी सोसायटी को बदल नहीं सकते हैं, नहीं तो इतने क्राइम्स ही नहीं होते। मैं यह रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके इस नए लॉ के साथ भगवान करे कि सोसायटी चेंज हो जाए और इसके साथ ही हम इस सोसायटी में उन लोगों को एक्सैप्ट करें, जो सचमुच प्रॉब्लम में हैं। हम इस सोसायटी चेंज के लिए अपील करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह) : धन्यवाद सभापति महोदय।

मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सब से पहले तो मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जो ये बिल लेकर आई हैं और उससे पहले मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि साढ़े चार सालों में जितनी भी पूर्व की सरकारें रहीं, जो नियम-कानून बने, उसमें समय-समय पर बदलाव लाने का काम आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने किया है। इसी कारण आज इस स्तर पर हम लोग आए हैं, जब हमें इस मानव तस्करी की बात को देखना है।

सभापति महोदय, आप देखेंगे कि जब कोई घटना घटती है, तो दो-तीन दिनों तक मीडिया और बाकी सब जगहों पर उसकी चर्चा होती है, चाहे वह लोक सभा हो या कोई विधान सभा हो। तीन-चार दिनों के बाद वह विषय पूरी तरह वॉश-आउट हो जाता है। मैं झारखंड प्रदेश से आता हूँ। वहां जो मेरे आदिवासी भाई हैं, जो गांव-देहात में रहने वाली महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको एक रैकेट के द्वारा वहां से दुबई या किसी अरब कंट्री भेज दिया जाता है। उसके बाद वे लोग वहां से वीडियो बनाकर भेजते हैं। उन्हें पैसा कमाने का प्रलोभन भी दिया जाता है, जैसे आप साल भर में ही राजा हो जाएंगे और आपकी सब चीजों की डबलिंग हो जाएगी। वहां से वीडियो बनाकर वे लोग यहां भेजते हैं।

फिर बाद में हमारी सरकार द्वारा कई बार प्रयास करके उन्हें वापस भी लाया गया है। हमारा कहना यह है कि खासकर स्टेशंस, बस पड़ाव और एयरपोर्ट्स पर कुछ ऐसी निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए, जहां हम देखकर समझ सकें कि यदि बीस की संख्या में लोग जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं। कहीं बारात वगैरह में तो नहीं जा रहे हैं और उन्हें ले जाने वाला आदमी गाइड करके समझा-बुझाकर ले जा रहे हैं। उसे वहीं पर यदि हम ब्रेक देंगे, तब कहीं जाकर इसमें सुधार होगा।

दूसरा मेरा यह कहना है कि जो एनजीओ की बात हो रही है कि ऑल इंडिया में ये एनजीओज हैं, उन्होंने बच्चियों को पकड़ा और उन्हें सुधार गृह में ले जाया गया। मैं समझता हूँ कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वे पंचायत के मुखिया हों, एमएलएज या एमपीज हों या राज्य सभा के सांसद हों, उनके पास मंत्रालय के द्वारा एक पत्र जाना चाहिए कि आपके जिले में ये-ये सुधार गृह

हैं और ये-ये एनजीओज लोग चला रहे हैं। आप यहां समय-समय पर जाकर देखिए कि इनमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं। तब कहीं जाकर उन लोगों को डर लगेगा कि ऊपर के लोग भी देखने और समझने के लिए उनके यहां आ रहे हैं।

मेरा आपसे निवेदन है कि आज की तारीख में जो भी हमारी बच्चियां इस कुचक्र में फंसकर कष्ट को प्राप्त होती हैं। चार दिन पहले झारखंड की एक न्यूज आई कि वहां से एक बच्ची को ले जाया गया और यहां एक बड़े आदमी के यहां नौकरानी के रूप में उसे रखा गया, फिर उसके साथ रेप हुआ, उसके बाद डिलीवरी हुई, ऐसी नाना प्रकार की बातें आईं। लेकिन दो दिन के बाद वह सारा मामला शांत हो गया। हमारे गिरिडीह लोक सभा क्षेत्र से बगोदर, डुमरी, गुमियां, नावांडीह आदि क्षेत्रों से लोग दुबई जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है इन चीजों पर ध्यान दिया जाए।

मैं माननीय मंत्री महोदया को इस बिल को लाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।
धन्यवाद।

SHRI PRASANNA KUMAR PATASANI (BHUBANESWAR): Chairman, Sir, let me congratulate the hon. Minister today. I adore her because she is protecting the lives of animals. But she has failed in protecting the lives of human beings. It is not her fault. She is fighting for everybody. So, I congratulate the hon. Minister. Children are blooming in God's Garden. They are not only blooming but also blossoming. The fragrance of knowledge is also structured in consciousness. We are not conscious of our own consciousness. Shri Kailash Satyarthi was conferred the Nobel Prize for protecting the children, the bonded labour, who were labouring hard. He was brutally beaten for his kind work, despite the fact that he is being honoured by the world. He has given some proposal about protecting the children. We should consider the proposal made by the Nobel laureate Kailash Satyarthi ji about protecting the children and the women. Practically, the kidnapping cases are everyday exhibited on television. You can see how a woman is being tortured today. We are promulgating the law in this august House. But, what happened to the dowry? It starts from the house; it starts from the family and then it covers the entire country. How is the human being so brutal today? मिट्टी जन्म से उर्वरक, मानव जन्म से बर्बर. The soil by birth is fertile whereas human being by birth is brutal. Why is it happening? One should see it. One should ask about it. One should know it. Sir, I know, there is not much time. I can just make some points. Today, I would like to draw the attention of this House towards a prominent law which cannot be rooted out.

You know, what happened in Delhi. You are setting up fast track courts. Rapes are occurring at a raster rate. How many people have been punished? So, this law should protect the humanity. Therefore, I pray to this august House to make the law very strong. If one mother is guilty, it means our motherland India is also guilty.

SHRIMATI BUTTA RENUKA (KURNOOL): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the Bill concerning trafficking of persons. As a woman, I am pained on seeing the violations and the loopholes giving scope for human trafficking. Trafficking, as far as our country is concerned, is mostly in women and children. Trafficking is a violation of human rights.

Poverty and illiteracy are the main root causes of human trafficking. This Bill apart from specifying the penal provisions should have dealt with handling the root causes. We must also note that trafficking is more among rural women and children who fall prey to anti-social elements. Vulnerable sections shall be identified and they shall be offered various welfare schemes so that they do not fall into the trap of traffickers.

Trafficking is usually promoted, encouraged and handled by pimps, brokers and traffickers. The law should ensure that trafficked victims are prevented from being prosecuted, detained or punished for they are victims of circumstances beyond their control. Protection to such victims should be provided with any conditionality.

I would like to give a few suggestions. Mainly we are talking about the rules and we are bringing laws, Bills and all such things. But, we all have witnessed, especially at traffic junctions and places, where we see small children begging. In spite of knowing that, we are unable to help these children. At every common place, we see child labour and child abuse. In spite of that, we are unable to help them. Practically, we have to go to the ground level and see how we can help these children. Basically, for the

children who are victims, we need to bring this law. With this new Bill, I hope, positive changes will definitely take place into our society and system. I appreciate and I really support this Bill. Thank you.

SHRI E.T. MOHAMMAD BASHEER (PONNANI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity. I would like to say that this is a most welcome move. Hon. Minister is in the process of making a divine law. I congratulate her for this. It is a bold initiative. The situation is very alarming. About 20,000 women and children were victims of human trafficking in India in 2016, a rise of 25 per cent from the previous year. The Minister of Women and Child Development stated in the Parliament itself that 19,223 women and children were trafficked last year as against 15,448 in 2015.

Our country, which is the centre point of South Asia, is one of the fastest-growing regions for human trafficking in the world. It is a matter of shame. Thousands of people – largely poor, rural women and children – are lured to India's towns and cities each year by traffickers who promise good jobs but sell them into modern day slavery.

We all know that some of the domestic workers are forced to work in small industries such as textile workshops, farming or even small kinds of works. They are exploited like anything. They are not getting any kind of remuneration. We are all saying that India is a country where child labour is eradicated. That is not a fact. In rural areas, you can see a lot of children who are doing heavy work. Bonded labour is one thing. They are exploited in many ways. Our brothers, sisters and kids are exploited in a ruthless manner.

What is the main reason? The main reason is poverty. We all know that. Using this, they are exploiting them in all kinds of activities. It is a bold initiative

on the part of the Minister. That is why, I said that this legislation is very important.

I would like to say only one thing. Stringent action should be taken. One should not have any kind of lenient attitude against the offenders. It is a very serious offence. They are spoiling the generation and they are bringing shame to the nation.

I once again wholeheartedly congratulate the hon. Minister for taking such an initiative for a noble cause.

With these words, I conclude.

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): Sir, I rise to support the Bill. I also congratulate the Minister. But I have some differences of opinion and I want to mention these things in the august House.

The biggest lacuna in the Bill is the absence of a comprehensive definition of trafficking, which should not only include trafficking for the purposes of labour and prostitution but also for forced marriage.

The draft Bill needs to take cognizance of the Immoral Trafficking Prevention Act, 1956, Juvenile Justice(Care and Protection of Children) Act, 2015, IPC Section 370 and various protocols and SOPs which are already in existence to address gaps in existing legislations and to uphold best practices. Merely overriding existing laws will compound the confusion.

The 'District Anti-Trafficking Committee' proposed as the major instrument of implementation is grossly inadequate and incapable of executing the functions vested in it. The important role of the police and the Home Department has been minimised. The Bill is silent on the existing provision in ITPA for a special police officer and an advisory body as also on search, rescue and custody matters. The provision that the rescued person has to be first produced before the Member Secretary of the proposed district committee unnecessarily complicates the matters.

So many other differences of opinions are also there. But I am shortening my speech. So, Sir, I request the Government and the Minister that the Bill be sent to the select Committee. Then only, the Bill will become perfect and practical.

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा) : महोदय, आपने मुझे व्यक्तियों का दुर्व्यापार (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2018 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ।

मानव तस्करी पर सभी सम्माननीय सदस्यों ने बोला है और विस्तार से चर्चा की है। मानव तस्करी मानव अधिकारों का सबसे बुरा उल्लंघन है और दुनिया भर में दवाओं और हथियारों के व्यापार के बाद तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। हम बच्चों को भारत का भविष्य कहते हैं, लेकिन ट्रैफिकिंग के जरिए उन मासूमों का बचपन रौंदा जा रहा है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के मुताबिक भारत भर में मानव तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं।

16 24 hrs

(Shri Kalraj Mishra *in the Chair*)

अभी मेरी सहयोगी मीनाक्षी लेखी जी ने अपने भाषण में उनका जिक्र भी किया है। मानव तस्करी के कुल मामलों में 60 प्रतिशत मामले बच्चों के हैं यानी 60 प्रतिशत मामलों में बच्चों की तस्करी हुई है। बच्चों की ट्रैफिकिंग के बाद कुछ कहा नहीं जा सकता कि वे बच्चे चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं, उनकी चाइल्ड मेरिज हो रही है, उनका यौन शोषण किया जा रहा है या उनसे भीख मंगवाई जा रही है। इन अपराधों से निपटने के लिए अभी तक कोई विशेष कानून नहीं है। इसको देखते हुए व्यक्तियों की तस्करी (रोकथाम, सुरक्षा तथा पुनर्वास) के लिए हमारी कर्मठ महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका संजय गांधी जी यह विधेयक लेकर आई हैं, मैं इनकी सराहना करती हूँ। मैं इस विधेयक की सराहना करते हुए इसे समयोचित माँग की परिपूर्ति बताती हूँ।

इस विधेयक की कई सारी प्रमुख विशेषताएं भी हैं। इस विधेयक में सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित का पुनर्वास मुकदमे के फैसले पर निर्भर नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से पहली बार पुनर्वास कोष बनाया गया है। यह सबसे सराहनीय कदम है। मुकदमों की तेजी से सुनवाई के लिए

प्रत्येक जिले में विशेष अदालत/फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने का प्रावधान भी किया गया है और इसके बारे में मंत्री जी ने बताया है।

खासकर, जिला, राज्यों तथा केन्द्रीय स्तर पर समर्पित संस्थागत ढांचा बनाता है। उससे ये सारे केसेज जल्द-से-जल्द निपटाए जा सकेंगे, यानी उसकी मॉनिटरिंग भी होगी और केसेज सुलझेंगे।

यह विधेयक अपराध के पारदर्शिय स्वभाव से व्यापक रूप से निपटता है। राष्ट्रीय तस्करी विरोधी ब्यूरो, विदेशी देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के अधिकारियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय तालमेल भी करता है।

सभापति महोदय, ट्रैफिकिंग का प्राथमिक कारण हम सब जानते हैं। इसमें गरीबी है, अशिक्षा है। इसके कारण दुर्व्यापार किया जाता है। हमारी सरकार ने इसे रोकने के लिए कई सारे कदम उठाए हैं और योजनाएं भी बनाई हैं। ट्रैफिकिंग और यौन शोषण के शिकार मासूम चेहरे उम्मीद भरी निगाहों से इस कानून की तरफ देख रहे हैं क्योंकि यह कानून देश के हजारों बच्चों की सिसकियों को मुस्कुराहट में बदल सकता है।

महिलाएं, जो देश की आधी आबादी हैं और बच्चे, जो देश का कल हैं, भविष्य हैं, उन्हें इससे बचाने के लिए यह विधेयक कारगर साबित होगा।

महोदय, मैं इस विधेयक के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री मोदी जी को और आदरणीय मेनका जी का तहे दिल से अभिनन्दन करती हूं। मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करती हूं।

धन्यवाद।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): सभापति महोदय, मैं ऐसे बिलों के प्रति बहुत आभार प्रकट करता हूँ और इसका समर्थन करता हूँ। ऐसी परिस्थितियों का, ऐसे सवालों का सबसे बड़ा कारण गरीबी है। गरीबी अभिशाप बना हुआ है। हमारे जीवन में सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हम समाज को आर्थिक रूप से काफी प्रगति की ओर नहीं ले जाएंगे, तब तक हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।

देश में चार ऐसे राज्य हैं, जिनमें एक बिहार भी है, जहां मानव तस्करी के सबसे ज्यादा अड्डे हैं। नेपाल से लगातार सेक्स वर्कर्स को लाया जाता है। अभी सीतामढ़ी में नेपाल के कई बच्चों की हत्या की घटना भी उजागर हुई है। आज हमारे बिहार राज्य की तरफ से इसके लिए सी.बी.आई. जांच की बात आ गयी है। मैंने इसे कई बार अंकित किया है कि जैसे ही माँ की नजरें गयीं, वैसे ही उसके बच्चों का शोषण शुरू हो जाता है। चाहे वह परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो, इसे हमारी बड़ी बहन भी जानती हैं। हमने इस पर कई बार चर्चा भी की है कि जब किसी के माता-पिता मर जाते हैं तो उसकी क्या स्थिति होती है। भ्रूण-हत्या भी इसका सबसे बड़ा कारण बनता चला जा रहा है।

दूसरा कारण बंधुआ मजदूर की स्थिति है। देश में 14 वर्ष के बच्चे, चाहे वह आर्थिक, भौगोलिक या सामाजिक कारणों से हों, किसी भी परिस्थिति में हम उन मजदूरों को मजदूरी करने देना नहीं चाहते हैं। फिर उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? यदि हम उन्हें रोजगार नहीं देंगे, शिक्षा नहीं देंगे, स्वास्थ्य की सही सुविधा नहीं देंगे तो फिर वह बच्चा कहां जाएगा? फिर तो वह किसी-न-किसी बंधुआ मजदूर के शोषण का कारण बनेगा। जब हमारे परिवार में हमारे मां-बाप भूखे होंगे तो वह बच्चा कहां जाएगा?

कानून आवश्यक है, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाता है। बहुत सारे एन.जी.ओज, बहुत सारी एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। आप भी जानते हैं कि हिन्दुस्तान में इस विषय पर कितनी एजेंसियां काम कर रही हैं।

मैं एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस मजदूर को हम फैक्ट्री से लाते हैं और लाने के बाद उसे हम यदि कोई रोजगार नहीं देते हैं, एजुकेशन नहीं देते हैं, उसे जीने का कोई रास्ता नहीं देते हैं तो फिर वह पुनः उसी फैक्ट्री में चला जाता है। चूंकि परिवार और माता-पिता की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो उसे मजबूरन काम करना पड़ता है।

मैं आग्रह करूंगा कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, जिसमें भ्रूण-हत्या, गरीबी जैसे अभिशाप से निपटने की बात और सामाजिक-सांस्कृतिक चीजों का समावेश हो। कानून का कार्यान्वयन इसलिए नहीं हो पाता है कि थाना, पदाधिकारी और नेता के बीच का जो सम्बन्ध है, वह बहुत मजबूती के साथ नहीं हो पाता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था और राजनेताओं का बहुत योगदान है। अभी भी इसमें बहुत लोगों का नाम आया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि राजनीतिक व्यवस्था और राजनेताओं द्वारा एक बेहतर रास्ता दिया जाए, जिससे मानव तस्करी को रोका जा सके।

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): I would like to thank all of you for having taken part in the discussion. Many of the hon. Members have read this Bill very carefully. I appreciate all the suggestions that were made.

Before I start, I would like to say, whatever lacunae that you perceive, and whatever I have learnt from you, we will incorporate that in the rules, and when we put the rules in, I would request all of you to look at them. This Bill has been on the website for the last one year and every draft has been put on the internet. It would have been good, if everybody had read it before and have given us suggestions.

I am going to start from Pratima Mondal ji. I would like to say that I am not creating ten institutuins. It is only the National Anti-Trafficking Bureau and everything comes under that. The rest is already there. We are just legitimising it, putting in money and making it stronger. We have proposed committees headed by the existing officers to ensure the required focus. So, it is not a bureaucrat employment device, as Tathagata ji said.

Then, I would like to thank Shri Om Birla ji for helping with the formulation. Smt. Pratima ji has asked for the places where the offence is being committed, and the participants in the committee should be defined. These are certainly being specified and defined in the rules.

I also thank Smt. Sathyabama ji for her comments. I always enjoy the interventions of Shri Tathagata Satpathy and I especially enjoy interventions that are prompted by Shri Mahtab in his own quiet manner. Unfortunately, he is

not correct this time. The Bill is very victim-centric. That is the only reason that I have brought it. Otherwise, there is absolutely no reason for me to reintroduce the laws that already exist.

This is a Bill that has a compassionate view of people who become victims in the sex trade. What is happening at the moment? We get a sex worker and we put her into jail, whether the trafficker goes in or the person, who has sheltered her, makes money from her, does not matter. The woman is always penalised; the child is always penalised. In this Bill, we ask them if they are there on their own volition. So, there is no question of penalising them or putting them in jail. We are just after the traffickers and not the victims.

Then, Tathagata ji said that we used NGOs. Yes, we used NGOs but not the 7800 that exist in his constituency. We actually use very specialised NGOs, which have been involved in preventing trafficking for many, many years. We used police people; we used sex workers; we used people who are involved in rehabilitation; we used dozens of lawyers, who have been fighting trafficking cases. So, we did use a lot of NGOs.

I appreciate the point raised by Shri Vinayak Rao, who pointed out the reality of begging. It has been repeatedly asked as to why begging is considered an aggravated crime. It has been considered an aggravated crime because it involves extreme violence and extreme suffering. As many of you pointed out, when you stop at traffic lights, you see these little babies. All of them have been given drugs to make them sleep. All of them have that *nakli* bottle which supposedly shows that milk has been given to them. All of them

actually are hired out for hours, for days. For me nothing could be worse than this. So, it is an aggravated crime.

I want to thank Shri Srinivasa Rao for participating in the debate. One of the points that has come up again and again is why only it has been capped at Rs.10 crore. It is not Rs.10 crore. When the Nirbhaya Fund was created, it had, I think, Rs.1000 crore in it.

Over the last few years, we have increased it to Rs. 6,000 crore and this amount of Rs. 6,000 is also being spent. This amount of Rs. 10 crore is just a notional amount of money. It will be increased and it will be increased hugely. Hopefully, it will never be needed, but of course, it will be done. Therefore, we have put in money as is needed so that there is no cap on it.

Shrimati Kavitha asked how we prevent trafficking and what this Government has done about prevention, before we even got to this Bill. I would like to tell her a few things that my Ministry has done. The Home Ministry has done a lot as well, so has the Labour Ministry, but I am going to tell you what we have done. As soon as I became Minister, I realised that the railways were the main reason behind why one could get away with trafficking because thousands of women and children were coming through railways. So, the first thing we did was that we immediately put posters in every single compartment or coach saying that if you can see a woman or a child that you believe is being trafficked, or has come against his or her will, please call any of the three numbers we have given. I have to tell you that this has been extremely

successful. Our rescue rate is very high. Literally, if you phone, at the next stop, you will have police waiting.

We have got an institution called Childline which is internationally one of the best. It gets about four crore calls a year. Since I came, we have doubled it. Our response time to picking up a child or woman or anybody in trouble is one hour.

Then, we have started something new called Railway Childline. We took the 100 most vulnerable railway stations where children, who are trafficked, usually come. Where are they trafficked from? It is from villages where the train stops for one minute. I cannot patrol those areas, but I can patrol the areas to which they arrive. We have given training, and people are stationed at every railway station which is vulnerable. Again, thousands of children have come in. In fact, we gave a Naari Shakti Award to one woman who in Mumbai alone, as part of the Railway Police, has rescued over 900 children herself.

Then, there are two more things. We have something called Track Child which was done by the UPA Government. What it consisted of was that all police stations should have the facility where they could put a child's face into a computer. Unfortunately, this did not work because the places where children disappeared from do not have electricity or computers or they are not involved. So, we started something called Khoya-paya where anybody in India can put in the face and name of a child or a woman who has disappeared, along with his or her details. Anybody else, who thinks that he has seen them or may have

seen them, can also put information into this. So far we have saved about 50,000 people through this initiative.

One of the things that bother me a lot is that it is difficult when it is a sexual crime, which children and women get trafficked for. How do you take action when your forensics cannot prove anything? So, we decided to strengthen the Forensics Department. We found, to our dismay, that after so many years, there were capabilities of only 1,500 sexual crimes' forensic investigations. Immediately, we have put in money into six forensic centres at Kolkata, Mumbai, Pune, one in Tamil Nadu, and Chandigarh which has already started working. They have put up an advertisement and are hiring 5,000 people who have qualifications in chemistry and physics to be trained as forensic experts. Once I can get the forensics in place, justice will come that much faster.

16 39 hrs

(Hon. Speaker *in the Chair*)

We are also putting in kits. Though it is not relevant to this subject, but I would like to tell you what else we are doing. Every police station and district hospital will have rape kits. These are simple small boxes in which there are test tubes, places for cloth, places for cotton wool, blood, semen etc. and a list of what is to be done and they are lockable. They go from there straight to the forensic lab so that they cannot be tampered with.

So, that would make collection of evidence so much easier. These are some of the things we have done. Shri Dushyant Chautala asked as to why we do we not use One Stop Centres. One Stop Centres are completely new for

India. Some of them are working very well. In fact, I am really sorry that Shri Gandhi has said that his is not working well because he was one of the first people to ask for one. He asked me so many times. I am very happy he has got one but it is not working well. Perhaps you could let me know what is wrong with it and I can correct it. But these One Stop Centres could also be used for rescue and keeping the women if they want to. You had also talked about foreign nationals. This Bill covers and is applicable to foreigners as well. Some Member asked about taking over buildings. This is very simple to do and can be misused by the police by just saying that this is the centre of trafficking and so take it over. No building or premises can be taken over without giving notice and hearing the person or the owner. It has to go through the due process. These are very strong safeguards. If you believe that these safeguards are not enough, please tell me after reading the Bill and I will put them in the Rules. I am also equally frightened about misuse because I am not going to be in Government forever and by instinct I am an NGO. So, I need to protect the rest of India. So, if there is something left out let me know.

Officers and persons in-charge of homes are punishable if they do not discharge their duties. Until now we can have a Muzaffarpur and we can have things like this happening only because there was no law saying that somebody in-charge of a home can be penalised. Now, they can be penalised. I would like to tell Shri Badaruddoza Khan that marriage is certainly mentioned. He said that somehow we should make this Act known. What we have done is something new. I can look at this and push it a little further in response to his

suggestion. We have started something new, that is, every exercise book of every school should have the POCSO Act behind it which says what is good touch, what is bad touch, what will happen if you are molested, etc. His suggestion was that we should also have this anti-trafficking law. We will request the HRD to put this as well in some of the exercise books.

Trafficking for the purpose of marriage or on the pretext of marriage is an offence. You were saying it is not there. It is not true. It is a frequent crime and girls are taken away pretending to be married and forced into prostitution. The Bill is gender neutral. Shrimati Supriya Sule had brought up many good points. The District Committee will have NGOs and people who are aware of the issue. Rules will ensure that proper ones are chosen. The sensitisation of the officers, as she said, is the most important thing. There is no point sitting here and wasting the whole day passing this Bill if it is never going to percolate down. But we have already started that process. In fact, this Bill was made with the help of a large number of police people who aimed it at sensitisation of their own cadre. Accountability has been built in the law. States will contribute to the Fund. But there are other ways to top up this Fund. The Bill is applicable to all persons, not men and women. I apologise. In future we will remember to put it properly.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: Thank you Madam.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Regarding adoption, you said that sometimes adoption can lead to trafficking. What happens in the CARA form of adoption? There are two or three things which happen with adoption. One is

adoption where people are just taking the baby and pretending that they found the baby somewhere. These are people that you cannot do anything about because they never come anywhere for certification.

Then there is another Act called HAMA Act whereby people adopt children. It applies to the Hindu Adoption. The CARA is now very strict and it may take a long time but all children are kept under watch after adoption for a long time both here and abroad. Periodic assessments are done until the child is fully integrated with the adopters.

Regarding these Homes, I have written to MPs again and again requesting them to take charge of all the Homes in their areas. I would like to repeat it today. If they could visit all the different homes in their areas whether they are Homes for adoptions, Swadhar Greh, Juvenile homes or anything, and give me an independent assessment. I would be very grateful for that. Every time I have got independent assessment, work has been done immediately. The problem is that we do not have enough Members of Parliament who actually go and visit these places. So, I would request all of them to do that.

You had asked for a Member of Parliament to be made a part of the Committee. An MP will be made a part of the Committee. We will just put it into the Rules.

What is completely new Supriya ji is buying and selling humans is being covered as a crime for the first time. Then, trafficking for the purpose of buying

and selling organs is already covered under Section 370 of the IPC which deals with trafficking.

Regarding National Anti-Trafficking Bureau, you were worried that if you find it in one State, you do not have to go to another State. It is 'National Anti-Trafficking Bureau' because it covers all the cases involving inter-State; the problem of jurisdiction of Magistrates is clearly addressed in this Bill.

Geetha ji, you wanted to know the people involved in the making of this Bill. Sunitha Krishnan, who comes from your State has done work in anti-trafficking for decades and also in rescuing rehabilitating victims; Prayas; the Nobel Prize Winner, Kailash Satyarthi; the Tata Institute of Social Service; and Shri Nair, are some of the sixty different groups who have helped draft the Bill.

You were worried about conviction and the low rate of conviction. I am saying that the provisions of designated courts in this Bill will hopefully improve the conviction rate and speed up the judicial process.

Many Members have expressed their concerns about sex workers and the inability of existing systems to stop organised crime in this area. Once the provisions relating to confiscation of property under this Bill are implemented, the hell holes of Kamathipura and G.B. Road, will all be a thing of the past because these will directly come under confiscation of property.

Meenakshi ji, thank you for that brilliant speech and for understanding the spirit and also the technicalities of the Bill.

Vincent ji, consent of the victims is very much a part of the Bill. If you believe that it is not enough, we will reinforce it through the Rules.

Mr. Premachandran, it has been two years already for this Bill. It has been long overdue. Almost everybody in this area has been consulted. You were saying that the misuse of the law is possible. There are thousands of laws and you can misuse anything that you want to misuse but the point is that we need to have a law to begin with. If you do not have a law, then you can do what you want to. I do not think that it should prevent us from making the law. This law is victim-centric as I keep repeating and full protection is given to the victims. It provides a singular structure of institutional frameworks at national, State and district levels. Trafficking is complex. It involves enforcement, supervision, rehabilitation and investigation. So, you have to have people at different levels doing different things. We are not proposing ten bodies. The only new body proposed is a National Anti-Trafficking Bureau.

All the others are the existing bodies of serving officers who will discharge additional functions. I would like to thank you, Shri Yadav. Begging is, as I said, an aggravated crime as it involves continual and extreme violence. Dr. Heena, thank you for your comments. The budgetary allocation would be increased as per the need. You had talked about re-trafficking. It is covered under Sections 32 and 33 and attracts imprisonment for life. So, we take it as seriously as you do. Dushyant ji had suggested the one-stop centres. I do agree with him absolutely. Kaushalendra Kumar ji, thank you for your support.

I would like to respond to Shrimati Satabdi Roy that we have been making changes for women in jails. In fact, that is the next thing. I would be

happy to share that with you. We finally reached after one and a half years of sending it to law schools; we prepare a manual for women prisoners, and for children. I agree with what you are saying that after six, if the child is taken away, where does the child go? It is a great concern. I am not going to leave this. It never occurred to me before. I am going to put this into the Rules.

Then, you said that we can't change society. We actually can change society because when this Government came in, when the Prime Minister suggested that we do, 'Beti Bachao, Beti Padhao', I myself was very sceptical and frightened. I said the same thing. We have been killing girl children for years, for decades and centuries. Why would we stop now? But, the campaign did take off. It didn't take long to change the Indian society for the better. We have a hugely patriarchal society in States like Haryana, Punjab, where the sex ratio at birth of girls had come down to 830 per thousand boys. These are the societies that change the fastest.

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): I would like to say a few words about the girlchild. In my Dharmapuri district of Tamil Nadu whenever a girlchild is born, they kill by giving poison or something. That has been happening. Seeing this, our former Chief Minister expressed serious concern, and said that her Government would come forward and adopt the girlchild. She introduced 'Cradle Baby' Scheme due to which many children were saved; they were educated and they are well placed now. Even before 'Beti Bachao, Beti Padhao' programme, the Government of Tamil Nadu had already implemented and had also succeeded in that.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Absolutely. We learn a lot from you. Seeing the success of `Cradle Baby` scheme, we have implemented it all over India. So, thank you.

We can change the society in one year. Every State got involved; every District Magistrate got involved; every MP got involved, and we did change society. Haryana went up from 830, which was shameful, to 950 in less than two years. So, did most districts. Initially we took 100 districts wherein it went up is 61 districts. In regard to others, we worked on to see what mistakes we made. Now, they are doing extremely well. Now, the `Beti Bachao, Beti Padhao` scheme is all over India. So, we can change society; we need to have a desire to do it.

As Supriya ji said that we have zero tolerance for something; and then, we work backwards. The point is, we have had tolerance for beggars; we have tolerance for sex workers; we have tolerance for women, children and labour. When we decide to have zero tolerance, it is gone.

Then, Shri Pandey spoke. As I explained, railway childline operates in 100 stations and has rescued thousands of children. As I said before, I had sent letters to Members of Parliament giving the names of institutions in their constituencies, as you suggested. If you have not received it, I apologise. I will send it again.

Shri Patasani, thank you for your inputs. Shrimati Renuka, you want to tackle first poverty, and then do anything else. If I could, wouldn't I do it? But this Bill, if I spread it and I diffuse it so much that I first root out poverty, then I

root out inequality, then I root out something, then, I would never be able to save whatever little I can save.

So, I kept it more to the point. It also includes skill training which hopefully will work backwards so that they do not come back again into the same problem.

I will tell you what we did. For instance, the Government of Chhattisgarh rescued the girls and for all of them, the District Magistrate opened up bakeries for them and she put ten-ten girls who had been rescued in those bakeries, sent them to Pune where they learnt cooking and now, each bakery makes just wedding cakes. They were given a loan for each bakery and, now, in the first month itself, they have started repaying it to the tune of Rs. 8000 a month which means they are selling a lot of cakes. So, we gave them a Nari Shakti Puraskar for that.

Mr. Basheer, thank you for your appreciation. Shreemathi Teacher, marriage is specifically mentioned and there is a very comprehensive definition of it which I would request you to go through. Mr. Patel, thank you for your appreciation.

Mr. Tharoor made certain points. I have known Mr. Tharoor since I was in college. It is a pity that the hon. Member did not give us the benefit of his great wisdom during the two years when the Bill was being shaped. It was only after it was introduced in Parliament that he came to see me about this and did not mention a single thing of what he has said today. As you can see now, I am very happy to take suggestions. I do not know everything. All of you are as

committed as I am. So, if he had done that, I would have been happy to take note of it.

There are two types of people. I am now going to be very wicked. During the consultation of the Bill, we received comments from two groups. One was representing the victims and another was representing sex workers. Dr. Tharoor represents the second group and has come to me repeatedly in their defence. As Meenakshi ji said, we do not tolerate this.

HON. SPEAKER: He represented sex workers!

... (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: He represented officially. I am just coming to it.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: There is nothing wrong in that.

... (*Interruptions*)

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: There is nothing to attack or defend. He came to me officially with the representatives of sex workers and he asked for them not to be harassed if they were voluntarily in the profession to which I have said, "Absolutely, there is no question of harassing them". The Bill focusses on a victim. If a voluntary sex worker is not a victim, has not been trafficked, has no one to blame for his or her problem; or other ones like TGs, then there is no question of my harassing them or the police having anything to do with them. The Bill is not intended to facilitate or to harass sex workers.

So, I would like to thank you all for this and I would be deeply grateful if you pass this Bill.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): While commencing the legislative document, hon. Minister in her introductory speech referred to two bodies – UNODC and SAARC – which are waiting to see India taking a lead in enacting a legislation against the invisible but pervasive crime across the world.

17 00 hrs

In this regard, I would like to refer to the observation of United Nations Independent Rapporteurs – Mariz Grazia, Via Marinero, Special Rapporteurs on Trafficking in Persons; and Urmila Bula, Special Rapporteur on Contemporary Forms of Slavery. They were greatly concerned about the Bill as presented by the Government to the Indian Parliament last week. I am drawing your attention to the observation made by the United Nations officials. They urged the Indian Parliament to revise the Bill in accordance with human rights laws. They raised two, three issues in regard to the Bill which seem to conflate trafficking with the smuggling of migrants, and social integration of those victims. They expressed their concern that this may lead to criminalisation of all irregular migrants including victims or potential victims of trafficking who because of a lack of safe, orderly and regular migration channels are forced into the hands of smugglers or traffickers. Simply I am drawing the flagging of the Minister to this.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam Speaker, I believe laws and institutions cannot be perfect instruments of doing justice in one go. There

is always room for improvement in any law and that is how they evolve. But we cannot keep arguing hoping for a Utopian legislation.

In this Bill, Madam, I would like to refer to two aspects on which clarifications can be given here. We have State Nodal Officers. The State Government is also involved. District-level Committees are to be formed. The Bill was introduced in the House last week and we have taken it up because of its urgency. Ultimately, all of us will be supporting this Bill. But the question arises, have State Governments been consulted or are being consulted? Ultimately, they have to do the work. The hon. Minister has not mentioned anything either in her speech now or at the time of introduction about the State Governments being consulted. This deals with Chapter 3.

I am reading this out from the Bill. On page 16, clause 39, sub-section 2, it says, "Whoever solicits or publicises electronically taking or distributing obscene photographs or videos, or providing material for soliciting or guiding tourists, or using agents or any other form which may lead to the trafficking of a person, shall be punished." The intent of this is not clear. This needs to be clarified in the rules as the Minister has accepted a number of suggestions. This is so wide, but the intent is missing. That intent needs to be clarified.

SHRIMATI MEENAKASHI LEKHI : Madam Speaker, aggravated form of offence is what was pointed out in the case of begging. जो भीख माँगते हैं, वह एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ ऑफेंस है, इसलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर वह जोड़ा जाना चाहिए। Maiming and blinding और जो उनके साथ फिजिकली किया जाता है, उसको डिफाइन किया जाना चाहिए।

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA : Madam Speaker, I just wanted the hon. Minister to clarify if the labour organisations were taken into confidence while designing this Bill.

Secondly, Clause 19 specifically refers to mentally retarded children and crimes related to them. In that clause, I think the parents of mentally retarded children should be relaxed. That is not mentioned in the Bill. If it can be put in the rules, I think it will be good.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL : Hon. Speaker Madam, I would request the hon. Minister that the repatriation process should be taken care of in this Bill so that girls trafficked especially from Bangladesh and other neighbouring countries may go to their homes as early as possible. I was the District President of South 24 Parganas and I personally experienced the scenario of girls being detained in homes for years. So, the repatriation process should be taken care of.

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, please speak only in one sentence if you have any query; no *bhashan* at all. I will not permit that.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Speaker, Madam, actually I have stood up to commend the hon. Minister for her excellent answer. I have seldom heard a Minister reply point by point to every Member who have spoken. I think other Ministers will follow her example and reply in such detail. I have only two small points. The first one is: I do believe that this offence of trafficking is not known to people in general. I saw a Hindi film called 'Mardaani' starring Rani Mukherjee which really brought out this problem of child trafficking. Would the Minister please consider promoting a film or films in different languages by noted directors to highlight the problem of trafficking, particularly child trafficking? The second point is: at the national level, the Minister has given the task of investigation to the National Investigation Agency. The National Investigation Agency is already overburdened with crimes concerning terrorism. I would like to ask her whether she would consider setting up a different national body for investigating crimes regarding trafficking? That

would be very proper instead of burdening the already overburdened National Investigation Agency. Let me again commend the Minister for an excellent reply and a good Bill brought in the Parliament.

माननीय अध्यक्ष : वे मन से बिल लेकर आई हैं।

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Madam, in our country, girls are facing a big challenge. Most of the girls are first mentally exploited and then physically exploited. Cybercrimes are also increasing all over India. The aspect of cybercrimes, especially against girls, should be included in the Bill. ...

(Interruptions)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Madam, please give me one minute. ... *(Interruptions)*

HON. SPEAKER: No. Everybody has something to ask. Now, the Minister will reply.

... *(Interruptions)*

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Madam, Shri Adhir Ranjan Chowdhury quoted what Dr. Shashi Tharoor also said, which is that two people from the UN Rapporteurs have asked for a better Bill. While I appreciate their concern, on the other hand when we went to Argentina for Global Conference on the Sustained Eradication of Child Labour, Shri Kailash Satyarthi took along this Bill in its final form and he read it out to 30 Ministers from different countries. I have to say that every one of them thought that it was a better Bill than they had in their own countries. As Shri Bhartruhari Mahtab mentioned, I am not saying that it is the best Bill in the world but what I will try into is that

whatever concerns have arisen now which you believe are not in the Bill will go into the Rules, so that we will try and see what the rapporteurs want because I think it is a good Bill. A lot of people from across the world have written to say that they are amending their Bills to come to conformity with this. But we will still try and make it better. Shrimati Meenakashi Lekhi has brought out that we should put in blinding and other such things. We have actually got it; it is in the Bill as body harming. In response to the query whether we consulted the States, yes, we did. Otherwise, I could not get a Bill.

The Prime Minister always insists that the States should be consulted; besides, every other Ministry and the GoMs are there. So, it goes through a very long process.

Only those electronic forms are criminalised which are abetting trafficking; otherwise, there are a lot of qualifiers to prevent misuse of free speech. However, if you believe that there is still a need, we will try to get it together in the Rules and show it to you.

Thank you again.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018 be taken into consideration.”

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: The House will now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clause 2 Definitions

HON. SPEAKER : Shri N.K. Premachandran, are you moving your amendment Nos. 6, 7, and 8 to clause 2?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 2, line 2, --

for “referred to in”

substitute “designated under”. (6)

Page 2, line 19, --

for “referred to in”

substitute “designated under”. (7)

Page 2, line 21, --

after “Sub-Divisional Magistrate”

insert “designated to discharge the duties and functions
under the provisions of this Act”. (8)

I am moving the amendment because it is the designated authority which has to make the Bill better.

HON. SPEAKER: I shall now put amendments No. 6, 7, and 8 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, are you moving amendment No. 25?

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER (KANNUR): I beg to move:

Page 3, for lines 7 and 8, --

Substitute '(w) "trafficking of persons" shall mean recruitment, transportation, harbouring, transfer or receiving of a person using threat, force or any other form of coercion, abduction, fraud or deception, abuse of power or position, inducement, including the giving or receiving of benefits, in order to achieve the consent of any person by anyone having control over such person recruited, transported, harboured, transferred or received, for the purpose of exploitation.

Explanations: 1. The expression "exploitation" shall include any form of physical or sexual exploitation, including the exploitation of the prostitution of others, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs:

Provided that the consent of the victim shall be immaterial in determination of the offence of trafficking;'. (25)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 25 moved by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher to clause 2 to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 2 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4

Functions of the Bureau

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 9 to clause 4?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 4, *after* line 39, --

insert “(xxvi) facilitate establishment of protection homes, rehabilitation homes, rehabilitation and all other activities beneficial to the victim”. (9)

This is an additional function of the National Anti-trafficking Bureau. It is a harmless proposal.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 9 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 4 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 4 was added to the Bill.*

Clause 5 Investigation by the Bureau

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 10 to clause 5?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 5, line 9, --

for “other”

substitute “similar”. (10)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 10 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 5 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.
Clause 5 was added to the Bill.*

Clause 6**State Nodal Officer**

HON. SPEAKER: Shri Premachandran, are you moving amendment No. 11?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): I beg to move:

Page 5, line 22, --

after "relief"

insert ", legal aid". (11)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 11 to clause 6, moved by Shri Premachandran, to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 6 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 6 was added to the Bill.

Clauses 7 to 9 were added to the Bill.

Clause 10**Anti-Trafficking Unit**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 12?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving this amendment.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 10 was added to the Bill.

**Clause 11 National Anti-Trafficking Relief and
Rehabilitation Committee**

HON. SPEAKER : Shri Rabindra Kumar Jena, are you moving amendment No. 1 to clause 11?

SHRI RABINDRA KUMAR JENA (BALASORE): Madam Speaker, the Minister has already assured the House that she will take this into account in the rules. So, I am not moving my amendment.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 13 and 14 to clause 11?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : I beg to move:

Page 6, line 30, --

for "Member"

substitute "Co-Chairperson". (13)

Page 6, line 38, --

after "victims"

insert "out of which one shall be a woman". (14)

There are four representatives from civil society out of which one should be a woman. That is my amendment. Kindly carry this amendment.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 13 and 14 moved by Shri N.K. Premachandran to clause 11 to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 11 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 **State Anti Trafficking
Committee**

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, are you moving amendment No.2 to Clause 12?

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Madam, I am not moving amendment No.2 to Clause 12.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos.15, 16 and 17?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:

Page 7, line 17,-

for "Director General of Police"
substitute "Secretary, Law Department". (15)

Page 7, line 23,-

for "Secretary, Law Department"
substitute "Director general of Police". (16)

Page 7, line 26,-

for "Two"
substitute "Four". (17)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 15,16 and 17 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 12 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 12 was added to the Bill.

Clause 13 District Anti-Trafficking Committee

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, are you moving amendment No.3?

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Madam, I am not moving amendment No. 3 to Clause 13.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment Nos.18 and 19?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving amendment Nos. 18 and 19 to Clause 13.

HON. SPEAKER: Shrimati K. Kavitha, are you moving amendment Nos.26 and 27?

SHRIMATI KAVITHA KALVAKUNTLA (NIZAMABAD): Madam, I am not moving amendment Nos.26 and 27 to Clause 13 as the hon. Minister has assured that she will make it a part of the rule.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 13 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 13 was added to the Bill.

**Clause 14 Powers of District
Anti-Trafficking Committee**

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 20?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:
Page 9, line 4,-

after "protection"
insert "education". (20)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 20 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 14 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 14 was added to the Bill.

Clause 15 was added to the Bill.

**Clause 16 Rescue and Medical
Examination of Persons**

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, are you moving amendment No.4?

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : Madam, I am not moving amendment No.4 to Clause 16.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.21?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving amendment No. 21 to Clause 16.

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy – Not present.

The question is:

“That clause 16 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 16 was added to the Bill.

**Clause 17 Safety, care and protection
of person rescued**

HON. SPEAKER: Shri Rabindra Kumar Jena, are you moving amendment No.5?

SHRI RABINDRA KUMAR JENA : I would request the hon. Minister to please look into the last amendment of mine which proposes to give an opportunity to the victim to appear before the magistrate. That is the point I am trying to impress. I am not moving amendment No 5 to Clause 17.

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No.22?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving amendment No. 22 to Clause 17.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 17 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 17 was added to the Bill.

Clauses 18 to 22 were added to the Bill.

Clause 23**Registration**

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy – Not present.

The question is:

“That clause 23 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 23 was added to the Bill.

Clauses 24 and 25 were added to the Bill.

Clause 26**Repatriation of victims**

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, are you moving amendment No.28 to Clause 26?

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Madam, I beg to move:

Page 12, for lines 7 to 10,-

substitute “(4) The repatriation of the victims shall be done after taking care of the social, economic and psychological needs of the victim and after providing assistance to all the urgent and long-term needs including housing, food and nutrition assistance, cash assistance, medical assistance including physical and psychological counselling, legal support, support for securing jobs and support for seeking remedies for rights violations.”. (28)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment No. 28 moved by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 26 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 26 was added to the Bill.

Clauses 27 to 30 were added to the Bill.

**Clause 31 Aggravated form of
Trafficking of persons**

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, are you moving amendment Nos. 29 and 30 to Clause 31?

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Madam, I beg to move:

Page 14, line 5,-

after "bonded labour"

insert "or sexual exploitation". (29)

Page 14, *after* line 31,-

insert "(xii) for the purpose of sexual exploitation by use of weapons to threaten or coerce, or physical beatings, violence and torture.

(xiii)for the purpose of sexual exploitation based on caste-based exploitation or in the name of "tradition". (30)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment Nos. 29 and 30 moved by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher to the vote of the House.

The amendments were put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

"That clause 31 stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 31 was added to the Bill.

Clauses 32 and 33 were added to the Bill.

Clause 34 **Punishment for keeping or allowing
premises to be used as place of
trafficking of persons**

HON. SPEAKER: Shri Tathagata Satpathy – Not present.

The question is:

“That clause 34 stand part of the Bill”.

The motion was adopted.

Clause 34 was added to the Bill.

Clauses 35 to 38 were added to the Bill.

Clause 39 **Buying or selling
of any person**

HON. SPEAKER: Shrimati P.K. Shreemathi Teacher, are you moving amendment No. 31?

SHRIMATI P.K. SHREEMATHI TEACHER : Yes, Madam, I beg to move:

Page 16, *after* line 29,-

Insert “(2)Whoever buys or attempts to buy sexual favour from another person, or hires services of a victim of trafficking, making or agreeing to make payment in cash or kind, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but may extend to two years and shall be liable to fine which may extend to twenty thousand rupees:

Provided that on second or subsequent convictions, the rigorous imprisonment shall not be less than two years but may extend to five years and fine may extend to fifty thousand rupees.” (31)

HON. SPEAKER: I shall now put amendment no. 31 to Clause 39 moved by Shrimati P.K. Shreemathi Teacher to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 39 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 39 was added to the Bill.

Clauses 40 to 46 were added to the Bill.

Clause 47

Special Public prosecutors

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No. 23?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I am not moving amendment No. 23.

HON. SPEAKER: The question is:

“That clause 47 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 47 was added to the Bill.

Clauses 48 to 51 were added to the Bill.

Clause 52

Cognizances of offences

HON. SPEAKER: Shri N.K. Premachandran, are you moving amendment No 24 to Clause 52?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Madam, I beg to move:

Page 19, line 14,-
for “guilty”

substitute “interfering with investigation.” (24)

Madam, there is a very strong legal error. At the time of moving the bail application, it is written that “Where the Special Public Prosecutor opposes the application and the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of such offence.” Madam, how can the Magistrate or the court find that he is not guilty at the time of moving the bail application? This is a very strong legal error on the part of drafting. Kindly look into the matter. I am moving it.

HON. SPEAKER: I shall now put amendment no. 24 to Clause 52 moved by Shri N.K. Premachandran to the vote of the House.

The amendment was put and negatived.

HON. SPEAKER: The question is:

“That Clause 52 stand part of the Bill.”

The motion was adopted.

Clause 52 was added to the Bill.

Clauses 53 to 59 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

HON. SPEAKER: The hon. Minister may now move that the Bill be passed.

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: I beg to move:

“That the Bill be passed”.

HON. SPEAKER: The question is:

“That the Bill be passed”.

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, we will take up Item Nos. 16 and 17 together.

SHRI K.C. VENUGOPAL: Are you taking it up now?

HON. SPEAKER: Why not? We will take it up. Let it be started and we will continue up to 6 o'Clock.

17 24 hrs

Announcement By The Speaker
Cancellation Of the Sitting of the House

DR. M. THAMBIDURAI (KARUR): Madam, the hon. Members from my Party are also requesting for a holiday on Guru Purnima. I would like to know whether the Government is agreeing to it or not. That is what we want to know.

HON. SPEAKER: It is not a Government holiday. All of you have to decide.

DR. M. THAMBIDURAI : We have no objection at all.

HON. SPEAKER: Some hon. Members have requested me for a holiday tomorrow on Guru Purnima. The House has to decide. Then only I will declare it.

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): The Lunar Eclipse is also taking place tomorrow. You can get the sense of the House and have a holiday tomorrow. We have been working for a whole week and at least, two Bills are being passed per day. That is the reason, why I am requesting on behalf of others and on my own behalf, that we can have a holiday.

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Last Friday, because of the No-Confidence Motion, we could not take up the Private Members' Business. Let there be a holiday tomorrow. But, my suggestion is that kindly spare some time for the Private Members' Business in the next week. This has to be compensated. That is my only suggestion.

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ANANTHKUMAR): Madam, if that is the sense of the House, we are with the sense of the House.

HON. SPEAKER: Tomorrow, there is Guru Poornima. Everybody has some Guru in his/her mind. It is needed also to guide us for good behavior. I am also with you because I also need some Guru to guide me to run the House. So, I declare tomorrow as a holiday. But today, we can work for half-an-hour more up to 6 o'clock.

17 26 hrs

**STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF
HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2018
AND
HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL (AMENDMENT)
BILL, 2018**

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I beg to move:

“That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.4 of 2018) promulgated by the President on 18th May, 2018.”

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): I beg to move:

“That the Bill further to amend the Homoeopathy Council Act, 1973, be taken into consideration.”

महोदया, आयुष मंत्रालय आयुष चिकित्सा पद्धतियों और शिक्षा के समग्र विकास हेतु कार्य करता है। इस मंत्रालय के दो सांविधिक विनियामक निकाय हैं, जिनके नाम हैं केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद। ये निकाय अन्य बातों के साथ-साथ क्रमशः आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, सोवा रिग्पा और होम्योपैथी शिक्षा को विनियमित करते हैं।

महोदया, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के गठन का प्रावधान है, जो होम्योपैथी चिकित्सा की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करती है, होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर का अनुरक्षण करती है और उससे संबंधित मामलों पर कार्य करती है। यह अधिनियम एलोपैथी कॉलेजों में शिक्षा से संबंधित कार्य करने वाले भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956, और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा कॉलेजों में

शिक्षा से संबंधित कार्य करने वाले भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (आईएमसीसी) अधिनियम, 1970 की तर्ज पर बनाया गया है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि होम्योपैथी को पूरे विश्व भर में स्वीकार्यता मिल रही है और उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में होम्योपैथी को एक चिकित्सा पद्धति के रूप में काफी महत्व प्राप्त हुआ है और उसे पूरे देश में लोकप्रियता मिली है। तदनुसार, भारत सरकार हमारी पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ-साथ उनकी अपनी-अपनी क्षमता के आधार पर होम्योपैथी के विकास को उच्च अग्रता प्रदान कर रही है।

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने और केन्द्र सरकार द्वारा अनुमति देने के तरीके में भी ज्यादा सतर्कता बरतने की प्रक्रिया में होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 का संशोधन, उसमें धारा 12(क) को जोड़ते हुए किया गया था, जिसमें कोई नया कॉलेज खोलने अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने अथवा कोई नया पाठ्यक्रम जोड़ने के लिए केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने का प्रावधान है। यह संशोधन इसलिए किया गया था कि अवमानक कॉलेज खोलने अथवा इस प्रकार के पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा अतिरिक्त सीटें बढ़ाने पर रोक लगाई जा सके।

यहां यह उल्लेख भी किया जा सकता है कि यद्यपि वर्ष 1983 की विनियमावली का अधिक्रमण करके बनाई गई होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विनियमावली, 2013 में यह अपेक्षा की गयी थी कि सभी होम्योपैथिक कॉलेजों को अपनी मान्यता के नवीकरण हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होगी तथापि पूर्वोक्त अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार को उक्त अधिनियम के अधीन इस स्वायत्त कानून में एक विशेष शक्ति शामिल करने की आवश्यकता है।

वर्तमान होम्योपैथी कॉलेजों की मान्यता के नवीकरण हेतु इस अधिनियम में सक्षम प्रावधानों के न होने के कारण कुछ ऐसे अवमानक कॉलेज कार्य कर रहे हैं जो इस विनियमावली के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदंड पूरे नहीं करते हैं। इसलिए इसमें जो डिग्री प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा लेते हैं, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसको मान्यता देने में कठिनाइयाँ हैं। इसके कारण उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार ने महसूस किया है कि सीसीएच अधिनियम में

संशोधन करके तत्काल धारा 12ग जोड़ना आवश्यक है जिसमें सभी होम्योपैथी कॉलेजों के मानकों का सत्यापन करने के लिए केन्द्रीय सरकार की भूमिका का प्रावधान हो और तदनुसार इस उद्देश्य से बनाई गई विनियमावली के अनुसार कॉलेजों को मान्यता दी जा सके।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद शीर्ष विनियामक निकाय के रूप में वांछित सीमा तक होम्योपैथी चिकित्सा शिक्षा में आवश्यक मानकों को प्रदान करने में सफल नहीं हुई है। कई होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज अभी भी गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, इसीलिए सीसीएच और उसके आचरण में गंभीर कदाचार के उदाहरण सामने आए हैं और परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता के साथ समझौता हुआ है। मंत्रालय ने परिषद के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और परिषद के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। तथापि, सीसीएच मंत्रालय की ऐसी सभी पहलों को रोक रहा है।

महोदया, जिस तरह से इल्लैगल कॉलेज होते हैं, उनके मामले में मंत्रालय के पास अधिकार नहीं है। वे कॉलेज एक रूम में भी चलते हैं, वहाँ हास्पिटल भी चलता है, वहाँ कॉलेज भी चलता है। इसके लिए एक अधिनियम लाना हमारे लिए आवश्यक है।

महोदया, मंत्रालय ने परिषद के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए और परिषद के मामले में पारदर्शिता लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। तथापि, सीसीएच मंत्रालय की ऐसी सभी पहलों को रोक रहा है।

सीसीएच के तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह बहुत वर्षों से अध्यक्ष रहे और उनके खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 19 दिसम्बर, 2016 को सीबीआई ने उनको 20 लाख रुपये लेते हुए पकड़ा। उनके ऊपर सीबीआई के द्वारा मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वे लगभग डेढ़-दो महीने जेल में भी रहे। इन परिस्थितियों में शीर्ष केन्द्रीय विनियामक निकाय के अध्यक्ष के रूप में डॉ. रामजी सिंह को पद पर बनाए रखना होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के हितों के खिलाफ है।

सीबीआई ने अपने दिनांक 31.03.2008 के पत्र में सीएचसी के तत्कालीन सचिव डॉ. ललित वर्मा के खिलाफ भारी जुर्माना लगाने के लिए नियमित विभागीय कार्रवाई शुरू करने की सिफारिश की थी।

सीएचसी में होने वाले भ्रष्टाचार के लिए 54 माननीय सांसदों ने शिकायत की थी। उसके आधार पर एक कमेटी का गठन किया गया और उसकी जाँच की गई और कमेटी की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और विधि कार्य विभाग की सहमति से डॉ. ललित वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया गया था। इसके बाद भी, यह केस खत्म नहीं हुआ। जब वे रिटायर हुए, तो मंत्रालय ने कहा कि उनके रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं दिए जाएँ, लेकिन जब केस खत्म हो जाए, तो यह दे दिया जाए। इसे भी नहीं माना गया और रिटायरमेंट के वक्त उनको सभी लाभ देते हुए घर भेजा गया।

यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि डॉ. रामजी सिंह, पूर्व अध्यक्ष, सीसीएच सहित परिषद् के कई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वहाँ बैठे रहे। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पाँच वर्ष का टर्म पूरा होने के बाद केवल तीन महीने तक वहाँ रह सकते हैं। लेकिन वे डेढ़ वर्ष तक वहाँ बैठे रहे और जो चुनाव करना था, वह नहीं कर पाए।

इसी अवस्था में होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों में गुणवत्ता का मामला भी चिन्ता का विषय बन गया। आयुष कॉलेजों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और गुणवत्ता तथा कार्यकारिणी में सुधार लाने के लिए मंत्रालय ने कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देने सहित कई महत्वपूर्ण उपाय किए थे। इस संदर्भ में, मंत्रालय ने सभी होम्योपैथी कॉलेजों के अध्यापन स्टाफ, गैर-अध्यापन अस्पताल स्टाफ और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आधार आधारित जियो लोकेशन सक्षम उपस्थिति प्रणाली हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गये थे।

सीसीएच द्वारा मंत्रालय के निर्देशों का आज तक अनुपालन नहीं हो रहा है। इसी तरह से मंत्रालय ने प्रयास किए कि इसमें ठीक तरह से पारदर्शी व्यवहार हो। जो-जो हमने कहा, वह उन्होंने नहीं माना। इसलिए आज हमें इस नियम को लाने की कोशिश करनी पड़ी।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि सीसीएच द्वारा किए जाने वाले सहयोग और भरोसे का सीसीएच के पूर्व अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह द्वारा पूरा उल्लंघन किया गया, जब उन्होंने आयुष मंत्रालय को यह उल्लेख करते हुए लिखा कि परिषद मंत्रालय को कोई भी सिफारिश नहीं करेगी।

अतः परिषद को बचाने और इसके सही उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसकी कार्यकारिणी बहाल करने तथा प्रवेश से संबंधित समयबद्ध मामलों के निपटान हेतु तत्काल उपाय किए जाने आवश्यक हैं। परिषद के लिए किसी सुधारात्मक उपाय का एकमात्र विकल्प ऐसे व्यक्ति को इसका कार्यभार सौंपना है, जिनके पास शुद्ध ईमानदारी सहित अपेक्षित अर्हताएं तथा अनुभव हों और जो पारदर्शी रूप में परिषद की कार्यकारिणी सुनिश्चित कर सके।

इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी बहत महत्वपूर्ण है कि मौजूदा होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 में परिषद के सदस्यों / अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रयोजन के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में केन्द्र सरकार ने यह अध्यादेश प्रस्तावित किया है और माननीय राष्ट्रपति जी ने 18 मई, 2018 को प्रख्यापित किया है। तदनुसार मंत्रालय ने परिषद का पुनर्गठन होने तक परिषद का कार्यभार संभालने के लिए एक विख्यात अर्हता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सकों वाला शासक मंडल नियुक्त किया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त शासक मंडल द्वारा मौजूदा परिषद का अधिक्रमण किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि अथवा केन्द्रीय परिषद के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए परिषद की कार्यकारिणी के लिए जिम्मेदार होगा।

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 2018 के मुख्य प्रावधान निम्न अनुसार हैं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा एक वर्ष की अवधि अथवा परिषद के पुनर्गठन, जो भी पहले हो, तक के लिए शासक मंडल की नियुक्ति द्वारा सीसीएच को अधिक्रमित करना है।

दूसरा, केन्द्रीय परिषद द्वारा बनाई गई विनियमावली के प्रावधानों के अनुसार एक वर्ष की अवधि के अंदर केन्द्रीय सरकार द्वारा मौजूदा सभी होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेजों की मान्यता का नवीकरण।

तीसरा, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त विख्यात अर्हता प्राप्त होम्योपैथी चिकित्सकों वाले शासक मंडल को परिषद का कार्य सौंपा जाना।

मैं विश्वास के साथ यह बताना चाहता हूँ कि शासक मंडल ने मई, 2018 में अपनी पहली बैठक आयोजित की और अधिनियम द्वारा 12क के अंतर्गत मौजूदा सभी 223 होम्योपैथी कॉलेजों के नवीकरण का निरीक्षण शुरू किया है तथा 45 आवेदन प्राप्त हुए हैं। शासक मंडल शीघ्रता से निरीक्षण कर रहा है और कॉलेजों को अनुमति प्रदान करने के लिए मंत्रालय को सिफारिशें प्रस्तुत कर रहा है, ताकि शैक्षणिक सत्र में बाधा न आए। इसके अतिरिक्त शासक मंडल होम्योपैथी केंद्रीय परिषद अधिनियम के उद्देश्यों के अनुसार परिषद का कार्य संभाल रहा है।

उपर्युक्त प्रस्तुतियों के साथ मैं सदन से होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक, 2018 पर विचार करने और होम्योपैथी के विकास के लिए प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु इसे पारित करने का अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद।

HON. SPEAKER: Motions moved:

“That this House disapproves of the Homoeopathy Central Council (Amendment) Ordinance, 2018 (No.4 of 2018) promulgated by the President on 18th May, 2018”.

“That the Bill further to amend the Homoeopathy Council Act, 1973, be taken into consideration.”

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Madam Speaker, I moved the Statutory Resolution against the Ordinance promulgated by the Government.

Madam, we have been observing that the Government has been resorting to indiscriminate use of ordinances whereby the democratic norms and procedures are being severely undermined. This is my observation. The reason is self-evident from the Statement of the Minister in which he states that as Parliament was not in Session, immediate action was required to be taken and so the President promulgated the Homoeopathy Central council (Amendment) Ordinance, 2018 on the 18th of May, 2018. This Session commenced on 18th July.

That means only two months elapsed before the commencement of the Parliament. Do you think that the Ordinance, which was meant for dismantling the CCH was so paramount, was so imperative that you did not have any patience to wait for another two months? The simple reason is that Government has been going on an Ordinance spree. The Government has been turned into an 'Ordinance-holic' Government. They are employing the instrument of Ordinance as a political Ordinance with a distinct view of saffronizing each and every institution under their custody. आपने अभी-अभी कहा कि राम सिंह जी ने रिश्त ली इसलिए उनको हटा दिया गया। यह अच्छा है, रिश्त कोई भी ले सकता है, ...* ले सकता है, ...* ले सकता है, ...* के नाम पर बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मान लीजिए, हमारे दोस्त नायक साहब ने किसी से रिश्त ली। मैं यह नहीं मानूंगा कि नायक साहब रिश्त लेते हैं। तर्क की खातिर मान लीजिए रिश्त लिया, क्या सारे आयुष मिनिस्ट्री को भंग कर

* Not recorded

देंगे? इतनी छोटी सी बात को साबित करने की कोशिश करें कि ...* डॉयरेक्टर होने के नाते सारे सीसीएच को भंग कर देंगे, इसे आपके हिसाब से सही ठहराया जाता है, यह बड़े दुख की बात है। यह स्टेटमेंट सेल्फ एक्सप्लनेटरी है कि आपने बड़ी बेरहमी से सीसीएच को भंग किया है। Simply, this is an innocuous legislation. I do not have any substantial argument to oppose this legislation because it appeared to be an innocuous legislation, but the way they are going to dismantle the apex body which is the decision making body under their Ministry, I think no plausible rationale can be trotted out by them. It is nothing but an authoritarian step that has been taken by them. By this way of promulgation of Ordinance, they should not have dismantled the institution under the nomenclature of CCH.

Madam, frequent resort to this power by the Government, particularly on dates too close to a Session of Parliament is condemnable. Ordinance should not be promulgated unless it is absolutely necessary. आप बताइए, Whether the situation was absolutely necessary? मैं कौल-शकधर को रेफर करता हूँ। Dates too close to a Session सेशन में सिर्फ दो महीने बाकी थे और इस बीच किस मजबूरी में आपको ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करना पड़ा, यह सबसे बड़ा सवाल है।

Power of Parliament to look into the desirability of the Ordinance is simply an ex post facto matter. आपने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। जारी करने से पहले हमसे कोई उपाय नहीं किया कि हम उसकी रोकथाम करें। यह एक पोस्ट फैक्टो मैटर है, इसलिए हम लोग आज इस पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन यह बात सही है कि it is not conducive to Parliamentary tradition. यह बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स और खासकर हमारे पूर्व स्पीकर्स की ऑब्जर्वेशन है, मेरी नहीं है। अगर आप किसी को नहीं मानेंगे तो हम कैसे चलेंगे? सिर्फ दो महीने का

* Not recorded

इंतजार आप सहन नहीं कर पाए। ...* नाम के किसी आदमी ने रिश्त ली। रिश्त तो मेडिकल काउंसिल में भी ली गई थी तो क्या आपने पूरी मेडिकल काउंसिल की तोड़फोड़ कर दी? उस समय हिम्मत नहीं हुई। ... (व्यवधान) नहीं, इस तरह से नहीं हुआ था। जायसवाल जी आप एक डॉक्टर हैं, आप बताइए कि क्या सिर्फ एक डायरेक्टर ने कोई गलती की तो क्या उसके लिए, जो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी है, उसे इस तरीके से भंग करना क्या सही है? ये खुद कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है। मैं करने के लिए कैसे कह सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। ... (व्यवधान) जायसवाल जी, खुद एक डॉक्टर है, इसीलिए मैंने जायसवाल जी से पूछा है।... (व्यवधान) मंत्री जी स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में खुद कहा है :

“The Central Government has taken various steps to streamline the functioning of the Council and to bring transparency in the affairs of the Council. However, the Council has been stalling all such initiatives of the Central Government. Many Members of the Council are continuing in the Council long after their tenure is completed. Further, there have been many charges of serious misconduct against the President of the Council, who continued to be a Member in the Council even after the end of his tenure as the election to elect the new incumbent could not be completed in time.”

इसका मतलब क्या होता है? ये सारी चीजें आपकी मिनिस्ट्री के अंडर आती हैं। आप खुद कह रहे हैं कि आपने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, लेकिन उसने होने नहीं दिया। आप खुद कह रहे हैं कि आपके कोशिश करने के बावजूद आपकी बात नहीं सुनी गई। इसका मतलब है कि यह आपकी नाकामयाबी है। आप अपने स्टेटमेंट में खुद कह रहे हैं कि आपने स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की, लेकिन वह हो नहीं सका। आपने सुधार करने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका। क्या इसकी रेमेडी है - काउंसिल को भंग कर देना? इसकी रेमेडी थी इसको चुस्त-दुरुस्त करना। हम यहां

* Not recorded

लेजिस्लेशन किसलिए लाते हैं? हम लेजिस्लेशन लाते हैं किसी चीज को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए, किसी संस्था को भंग करने के लिए नहीं। ये खामियां आपकी हैं। मंत्री होते हुए आपने इसको स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की थी, लेकिन आपकी कोशिश नाकामयाब रही। आपकी कोशिश नाकाम रही। इस तरह की नाकामयाबी का बयान खुद देकर आप मंत्री पद की गरिमा को शून्य कर रहे हैं। यह आपकी नाकामी है। अपनी नाकामी के लिए आप एक इंस्टीट्यूशन को भंग कर रहे हैं। ... (व्यवधान)

मैडम, मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोलिए, लेकिन इसे आज के दिन में समाप्त भी करना है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, मैंने अभी शुरू किया है। ... (व्यवधान) मैडम, यह खुद इनकी इनकम्पिटेंसी का स्टेटमेंट है। होम्योपैथी के साथ हमारा बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। होम्योपैथी के साथ बंगाल का बहुत पुराना रिश्ता है। मंत्री जी जानते हैं। आज नहीं, हिन्दुस्तान में सबसे पहले, वर्ष 1937 में बंगाल की लेजिस्लेटिव असेम्बली में होम्योपैथी को रिकग्निशन देने के लिए ब्रिटिश जमाने में बिल पारित हुआ था। गयासुद्दीन नाम के एक एमएलए ने यह बिल पारित कराया था।

बंगाल में सबसे पहले होम्योपैथी को एक फ़ैकल्टी के रूप में दर्जा दिया गया है। ... (व्यवधान) बंगाल का होम्योपैथी से बहुत पुराना रिश्ता है। आपने एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी, सीसीएच को कैसे भंग किया, क्यों किया? यह करना आपकी गलती है, यह आपको कहना पड़ेगा।

दूसरी बात यह है कि आप अभी वहां किसी को एक साल के लिए जिम्मेवारी सौंपेंगे। आप बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाएंगे, उसमें कौन-कौन मैम्बर्स होंगे, उन मैम्बर्स के लिए क्राइटेरिया क्या है? मैं भी उन मैम्बर्स का क्राइटेरिया जानता हूँ और आप भी जानते हैं। वहां आप अपने आदमी को बैठा रहे हैं। मैंने पहले सवाल किया था कि भगवाकरण हो रहा है, आप भगवाकरण के चलते वहां अपने आदमी को बैठाए, नहीं तो कौन-सा पैरामीटर है? ... (व्यवधान) आपने कोई पैरामीटर नहीं बताया है कि ऐसे पैरामीटर के चलते, मैंने ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाया।

मंत्री जी का मंत्रालय आयुष है, उसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा हैं, लेकिन आपके सेक्रेट्री, वहां पहले आईएस बैठा करते थे, अभी वहां किसी आयुर्वेदा वाले को बैठा दिया।
...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अधीर रंजन चौधरी, आपने केवल पांच मिनट के लिए बोला था।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैडम, यह बिल है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इनको थोड़ा ज्ञान देना चाहता हूँ कि आज होम्योपैथी में जेनेटिक्स आ गए हैं, जिनो होम्योपैथी। पूरी दुनिया में हिन्दुस्तान में पहली बार होम्योपैथी के साथ जेनेटिक्स कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। यह हमारी एक बहुत बड़ी तरक्की है। इसके मंत्री नाईक साहब हैं। मैं चाहता हूँ कि उनकी भी गरिमा नड्डा जी की तरह हो। ऐसा लगता है कि आप ...* मंत्री हैं। आप भी नड्डा जी की तरह ही मंत्री हैं, मैं उसी हैसियत से आपको देखना चाहता हूँ।

क्या हमारे देश में ऐसा कोई एकाउंट है कि कितने सारे लोग होम्योपैथी पर निर्भर करते हैं? मुझे यह जानकारी है कि 100 मिलियन से ज्यादा लोग होम्योपैथी के ऊपर निर्भर करते हैं। होम्योपैथी एक आर्ट है, साइंस है, चीप ड्रग है। हमारे देश में चार हजार से ज्यादा होम्योपैथी मेडिसिन्स मिलती हैं।

Hippocrates, the Father of Medicine in the ancient Greece, first discovered the law of similars and law of opposites. The law of similars means Homeopathy. The law of opposites means orthodox medicine. The medicine which follows the law of similars is called Homeopathy. It has no side effects, no addictiveness and no toxicity. That is why there is a huge potentiality of Homeopathic medicines in our country. Already, 86 countries across the world have recognised Homeopathy as an alternative medicine. So, there is a huge potentiality. That is why, I am very much interested to see the growth of

* Not recorded

homeopathic sector in our country which has been growing by a margin of 20 per cent to 25 per cent. So, there is a huge potentiality of Homeopathy.

But you do not have any sympathy; and you do not have any empathy for Homoeopathy. Rather you are displaying your apathy. You are displaying your antipathy to Homoeopathy. There lies the problem. डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को आपने कैसे भंग कर दिया? मैं मंत्री जी के सामने दो चीजें रखना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, छह बजे तक मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

The Ministry of AYUSH which shall be the in-charge of permitting persons and colleges for offering Homoeopathy courses and expand such courses has also been promoting the clause 49 of the National Medical Commission Bill 2017 which focuses on bridge course, that allows homoeopathic profession to prescribe allopathic treatment in rural areas. This has been criticised as lowering the standing of rural health, as allopathic treatment will now be delivered by practitioners who took a short cut instead of the standard MBBS. ऐसा मत कीजिए। शॉर्ट कट कोर्स बनाकर डाक्टरों की तादाद हिंदुस्तान में जबरदस्ती बढ़ाते हुए हमारी हेल्थ सर्विस को हानि मत पहुंचाइए। मैं दिल से जानता हूँ कि हमारे दोस्त डॉ. संजय जायसवाल मेरी इस बात से सहमति दिखाएंगे, क्योंकि वे एमबीबीएस डाक्टर हैं। आप ब्रिज कोर्स के जरिए किसी को भी डाक्टर बना देते हैं, क्योंकि आपको दिखाना है कि एनडीए के समय में हिंदुस्तान में कितनी अधिक संख्या में डाक्टरों बने हैं। अभी भी देश में दो लाख से ज्यादा होम्योपेथी के डाक्टर हैं। सालाना देश में 12 से 13 हजार होम्योपेथी डाक्टरों बनते हैं। इन्हें ब्रिज कोर्स पढ़ाकर इतनी जल्दबाजी में रूरल हैल्थ डिलिवरी के लिए सारे हैल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हानि मत पहुंचाइए।

आपको एजुकेशन की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपका ध्यान इधर-उधर है। आपको रामजी सिंह को सबसे बड़ा दुश्मन ठहराना पड़ा। आप प्रैक्टिस करने वालों को और ज्यादा ट्रेनिंग देने की व्यवस्था कीजिए। आप कह रहे हैं कि एक छोटा घर है, कमरा नहीं है। कमरा इसलिए नहीं है, क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप सरकार से पैसा मांगिए और खर्चा करके गांव-गांव में होम्योपेथी सेंटर क्यों नहीं बनाते हैं? कालेज बनाना आपकी जिम्मेदारी है, कोर्स करवाना आपकी जिम्मेदारी है। सीसीआई आटोनोमस बॉडी थी। उससे आपने सारी पावर ले ली है, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई सहायता नहीं करते हैं क्योंकि आपकी जेब में पैसा नहीं है। आप इसका दुरुपयोग मत कीजिए।

मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ। There is no focus on strengthening training. The Bill focuses on the authority of the Central Government in addressing the corruption. However, it does not ensure a robust mechanism for improving the quality of practitioners being trained under these institutes.

The Government will permit more number of bridge courses under the curriculum of these institutes seeking to expand courses which will do more harm in the health sector.

Instances regarding the Ministry of AYUSH taking up the role of regulator in lieu of the Council have increased which is an over reach of the Ministry into roles that should ideally be delegated to autonomous bodies.

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, मैं कुछ प्वाइंट्स कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

माननीय अध्यक्ष : आप बैठ जाएं, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, सभी लोग मेरी बात को एनज्वॉय कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है, लोग एनज्वॉय कर रहे हैं, लेकिन समय समाप्त हो गया है।

श्री अधीर रंजन चौधरी : महोदया, आज चर्चा समाप्त नहीं होगी, कृपया मुझे बोलने दीजिए।

माननीय अध्यक्ष : इसका मतलब यह नहीं है कि आप बोलते जाओगे। आप कृपया अपनी बात पूरी कीजिए।

... (*Interruptions*)

18 00 hrs

HON. SPEAKER: This is not the way. You complete it now.

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : The Standing Committee on Health observed, "The conformation of prescribed standards of Homoeopathy education has been compromised due to legal infirmities in the governing statute."

The Committee had recommended that the oversight of maintenance of standards should be done with the utmost transparency and there should be a credible and vibrant appeal mechanism in place so that minor technical and procedural defaults are not made a basis for harassment, and questionable practices and genuine grievances of homoeopathy medical institutions are addressed swiftly within set timelines.

मैं एक सलाह देना चाहता हूँ। होम्योपैथिक कॉलेजेज़ को यूनिवर्सिटी से एफिलिएट क्यों नहीं किया जाता है? Homoeopathy Colleges should be affiliated with the universities. हम भी चाहते हैं कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की और तरक्की हो।

HON. SPEAKER: Yes, you have completed.

Now the House stands adjourned to meet again on Monday, the 30th July, 2018 at 11 a.m.

18 01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, July, 30, 2018/Shravana 8, 1940 (Saka).
